खण्ड-272, अंक-4
बुधवार, 31 ज्येष्ठ, शक संवत् 1889
(21 जून, 1967 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 272 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–३५
सर्वश्री लोटनराम, रामेश्वर सहाय, जगदीशसिंह तथा माधोनारायण मुद्गल के निधन पर शोकोद्गार	३५–३७
सदन के अवशिष्ट कार्य-क्रम को कार्य सूची में सम्मिलित न करने तथा सरकार के कथित वैधानिक रूप से गठित न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	३७–४३
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् परिषद् तथा न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलों के लिये अवधि) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४३
उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४३–४४
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पांचवां संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४–४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (आवास आयुक्त की सेवा की शर्तें) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	४५
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (वेतन या मजदूरियों से कटौती करके किराये की वसूली के लिये अनुबन्ध) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों पर आवास आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५-४६
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संविधाओं और हस्तान्तरण–पत्रों का निष्पादन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	४६
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	४६
सदन के परिसर में कांग्रेस के आवंटित कमरे को यू० पी० सेक्रेटेरियट मिनिस्टीरियल) आफिसर्स एसोसियेशन की बैठक के लिये दिये जाने के संबंध में श्री चन्द्रभानु गुप्त के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	४६-४८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २१ जून, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८९

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अवेधनाथ, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
अहमदउल्ला खां, श्री
आत्मा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपालसिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्र मोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीरसिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झांसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमलाप्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम अञ्जन गुरु)
कल्याणसिंह, श्री
कामतासिंह, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशनसिंह, श्री
किशुनलाल, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशरी लाल, श्री

केशवदेव, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (एटा)
गंगाभक्तसिंह, श्री
गंगा राम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारी लाल, श्री चौधरी,
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपाल राम दास, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरीराम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रकिशोर, श्री
चन्द्रकुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगतसिंह श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीशनारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपतसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जलीलुर्रहमान, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह, श्री
जवाहरलाल, डाक्टर
जवाहरलाल जाटव, श्री
जवाहिरलाल, श्री
जसोदानन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जे० एस० चौधरी, श्री
जुगल किशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्तसिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टीकमसिंह, श्री
तिरमलसिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दल सिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराजसिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवीदयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवीसेवक, श्री
देवेन्द्रसिंह, कुंवर
देशराजसिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुधारी पाण्डेय, श्री
धर्मगजसिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
ध्रुव कुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री

नरदेवसिंह, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवल किशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पब्बर राम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतमसिंह, श्री
प्यारेलाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारुक चिश्ती, श्री
बंशीधर, श्री
बजरंग बली, ब्रह्मचारी
बदनसिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसी दास, श्री
बलवीरसिंह, श्री (मेरठ)
बलवीरसिंह, श्री (फतेहगढ़)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बसन्त सिंह, श्री
बाबू बदरे श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बिशनलाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृजमोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनीबाई, श्रीमती
बेनीसिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भगूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेश भूषण, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धुलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
मन्नीलाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखानसिंह, श्री
महरमसिंह, श्री
महिपालसिंह, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रप्रताप सिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकण्डे, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायमसिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहनलाल आचार्य श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईस दीन, श्री
रघुनाथसिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)

रघुनाथ सिंह, श्री (झाँसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खाँ, श्री
रमाकान्त, श्री
रमाबल्लभ मिश्र, श्री
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
राम अचल सिंह 'सेन्गर', श्री
राम अधार, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
राम आसरे, श्री
राम करन, श्री
राम किंकर, श्री
राम किशोर, श्री
राम कुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
राम नारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामवचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति "अंचल", श्री
राम रतन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूप नाथ, श्री
रूप नरायन, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटूरीसिंह, श्री
लाखन, श्री
लाल कृष्ण कुमार पाल, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर पाण्डेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झोंगन साहू)

विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह चौधरी, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्यामसिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिगराम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहनलाल, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

कार्यसूची न मिलने पर आपत्ति

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)----

प्रश्नों से पहले, आपसे मुझे यह निवेदन करना है कि मुझे एजेन्डे की कापी नहीं मिला करती है, मैं सके लिये दो-तीन दिन से आपसे कह रहा हूं कि एजेन्डे की कापी सदस्यों को मिलनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने इसकी व्यवस्था भी की है । जिन माननीय सदस्यों ने शिकायत की थी उनका कहना है कि अब व्यवस्था ठीक है, फिर भी कुछ दिक्कत हो सकती है । मैं आपको एक बात यह भी बताना चाहता हूं कि एजेन्डे के लिये हमें कम शिकायत मिलती है । एजेन्डे की कापी यदि रह जाये तो उसे नोटिस आफिस से माननीय सदस्यगण ले लिया करें । फिर भी मैं इसे देखूंगा ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २१ जून, १९६७

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

अराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल

**१--श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारी १३ जून, १९६७ से अनिश्चित काल के लिये अपनी मांगों को पूरी न होने के कारण तथा अपने नेताओं की गिरफ्तारी के कारण हड़ताल कर रहे हैं ?

गृह उपमंत्री (श्री रुस्तम सैटिन)---

प्रदेश में पांच लाख से अधिक राजकर्मचारी हैं और जहां तक सूचना मिल पाई है, १३ जून को केवल कुछ सौ कर्मचारी ही बिना प्रार्थनापत्र के गैरहाजिर थे। इसके बाद दिन-ब-दिन अनुपस्थित लोगों की तादाद कम होती चली गई और अब कार्य बिलकुल बदस्तूर चल रहा है। जिलों से जहां तक सूचना आई है उससे मालुम होता है कि वहां कोई भी कर्मचारी गैरहाजिर नहीं हुआ और सब जगह काम बदस्तूर चलता रहा ।

**२--श्री कृष्णानन्द राय---

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की मुख्य मांगें अब क्या-क्या हैं ?

श्री रुस्तम सैटिन---

शासन को मांगों की कोई प्रमाणित सूची प्राप्त नहीं हुई ।

श्री कृष्णानन्द राय---

अध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व की मैं कोई पूरक प्रश्न पूछूं, मैं माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की नोटिस देना चाहता हूं कि प्रश्न दो के सम्बन्ध में उन्होंने सदन को गलत सूचना दी है कि कर्मचारियों की मांगों की उन्हें कोई नोटिस ही नहीं मिली है । इतना बड़ा आन्दोलन हुआ और इतने आदमी जेलों में गये, पर मंत्री जी को उनकी मांगों के बारे में ही पता नहीं ....

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न कीजिये और विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में जो है तो उसे लिखकर दीजियेगा ।

श्री कृष्णानन्द राय--

क्या मुख्य मन्त्री बताएंगे कि इस हड़ताल को रोकने के लिए उन्होंने कितने राज्य कर्मचारियों को जेल में बन्द किया है और कानून की किस धारा के अन्तर्गत उन्हें बन्द किया गया है ?

मुख्य मन्त्री (श्री चरणसिंह)--

पी० डी० ऐक्ट के मातहत ८ कर्मचारी जेल में बन्द हैं।

आचार्य दीपङ्कर (जिला मेरठ)---

क्या यह सही है कि अब कर्मचारियों ने राजनीतिक दलों के अनुरोध पर अपनी हड़ताल वापस ले ली है ? तो क्या सरकार उनके नेताओं की रिहाई तथा उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक पुनर्विचार करने की सोच रही है ?

श्री चरणसिंह—

यह बात ठीक है कि संयुक्त परिषद् द्वारा इस तरह का एक पत्र हमें प्राप्त हुआ है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

जब उन्होंने यह आन्दोलन वापस ले लिया है तो जो लोग जेल में बन्द हैं उनको कब तक रिहा कर देंगे?

श्री चरणसिंह—

वैसे तो इस सारे प्रश्न पर विचार हो रहा है लेकिन यह ऐसा सवाल है जैसे यह कहा जाय कि आपने अपनी वाइफ को कब से पीटना छोड़ दिया।

(हंसी)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मुख्यमन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ राजनीतिक दलों के नेता उसके पूर्व उनसे मिले थ? यदि हां, तो उनसे और इन राजनीतिक नेताओं से क्या बात हुई थी?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैंने परसों अखबारों में कुछ राजनीतिक नेताओं का एक बयान देखा था। उस बयान के निकलने के पूर्व उस बयान के सिलसिले में, मुझसे उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी।

श्री कृष्णानन्द राय—

सरकार और राज्य कर्मचारियों के बीच मुख्य मतभेद वन मैन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर है तो क्या सरकार उस वन मैन कमीशन की रिपोर्ट को सदन की मेज के सम्मुख रखेगी जिससे उस पर विचार हो सके?

श्री चरणसिंह—

गवर्नमेन्ट को कोई आपत्ति नहीं हो सकती उस कमीशन की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने में, लेकिन उसका अनुवाद वगैरह कराया जा रहा है।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार सस्पेंड या बरखास्त किये गये कर्मचारियों को फिर से बहाल करने पर विचार कर रही है?

श्री चरणसिंह—

यह सारा प्रश्न विचाराधीन है लेकिन यह कहना ठीक नहीं होगा कि सभी को वापस ले लिया जायगा, या बिला शर्त वापस ले लिया जायगा या किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही बिलकुल नहीं की जायगी।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री जी को पता है कि राज्य कर्मचारियों के एक से अधिक संगठन हैं और अगर कोई संगठन है तो उनकी अलग-अलग मांगें क्या-क्या हैं?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, संयुक्त परिषद् जिसने यह हड़ताल वगैरह कराने की कोशिश की थी वह एक ज्ञानधिकृत संस्था है और अथराइज्ड नहीं है और कुछ संस्थायें हैं जो अथराइज्ड हैं उनके क्या नाम हैं और उनकी क्या संख्या है, यह इस समय मैं नहीं बता सकता।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह देखते हुए कि हड़ताल समाप्त हो गई लेकिन अभी भी मतभेद जिस बारे में है यानी मांग पैरिटी के सम्बन्ध में पूरी कर दी गई है या नहीं इसके लिये किसी निष्पक्ष आरबिट्रेशन के सामने इस प्रश्न को रखेंगे ?

श्री चरणसिंह---

जी नहीं।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि कर्मचारियों ने मुख्य मन्त्री जी के इस वक्तव्य को स्वीकार नहीं किया है कि सेन्ट्रल कर्मचारियों के बराबर उनको पैरिटी दे दी गई है ?

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट की तरफ से और कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है और सब परिस्थितियों को देखते हुये उठाया भी नहीं जा सकता। जहां तक पैरिटी वगैरा की डिमान्ड है वह डिमान्ड उनकी आई और नवम्बर, अक्तूबर में उठी। शुरू में नहीं थी। गवर्नमेन्ट का ऐसा कोई कमिटमेंट भी नहीं है कि हम पैरिटी देंगे जिस पर यह कहा जाय कि सरकार अपना वचन पूरा नहीं कर रही है। इसके अलावा हमारे अपने खयाल से पैरिटी हो गई है। फिर भी इसमें विवाद हो सकता है तो हम अपनी आमदनी को देखते हुये हिन्दुस्तान की सारी स्टेट्स के मुकाबले में अपने कर्मचारियों को ज्यादा दे रहे हैं। ११ स्टेट्स से ज्यादा टोटल टर्म्स में और दो स्टेट्स जिनकी आमदनी हमसे ज्यादा है उनसे कम्पेरेटिव टर्म्स में कम केवल डी० ए० में लेकिन सैलरी और डी० ए० मिलाकर किसी दूसरी स्टेट के मुकाबले में यहां कम नहीं मिल रहा है। डिमान्ड रहती है कि उनको ज्यादा मिले और हम भी चाहते हैं कि उन को ज्यादा मिले किन्तु इस समय में इसको फाइनल समझता हूं और किसी आरबिट्रेशन वगैरह की जरूरत नहीं है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी की जानकारी में है कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने जो हड़ताल की उस सम्बन्ध में संयुक्त विधायक दल की सरकार ने ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता था वह उनके लिये सुविधा दी किन्तु एक दल विशेष बीच में आ गया है जो यह गड़बड़ी पैदा कर रहा है तो यह जानकारी करायेंगे कि यदि वे इस तरह से गड़बड़ी पैदा करेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ?

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे इस प्रश्नोत्तर की इजाजत दें तो मैं अपने दोस्त रिजवी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस सवाल के पूछने का आग्रह मुझसे न करें।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब वह पैरिटी की बात मान नहीं रहे हैं और पैरिटी की सिर्फ डियरनेस अलाउन्स में नहीं बल्कि टोटल अमोल्यूमेंट्स में देखकर कहते हैं कि पैरिटी हो गयी और लोगों का यह खयाल है कि डियरनेस एलाउन्स की पैरिटी गवर्नमेन्ट मंजूर नहीं कर रही है और जो लीडर्स बीच में पड़े हैं वह समझौता करा रहे हैं, ऐसी अवस्था में क्या गवर्नमेंट इन तमाम झगड़ों को किसी एक न्यायाधीश को सुपुर्द करके तमाम चीजों पर फैसला लेकर इस झगड़े को खत्म करायेगी ताकि गवर्नमेन्ट का काम सुचारुरूप से चल सके ?

श्री चरणसिंह---

मैं जवाब दे चुका हूं, किसी न्यायाधीश के मुकर्रर करने की जरूरत नहीं है और अगर झगड़ा है तो माननीय मित्र जो मेरे सामने बैठे हैं उनकी नजरों में है, जो मैं कहना नहीं चाहता।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर डी० ए० पैरिटी के लिए उनका कमिटमेंट नहीं है, तो क्या मैं यह समझूं कि स्टेट गवर्नमेन्ट भविष्य में सेंट्रल गवर्नमेन्ट के बराबर पैरिटी के प्रश्न पर विचार ही नहीं करेगी ?

श्री चरणसिंह—

यह तो भविष्य का सवाल है, मैं इस पर क्या बतलाऊं ?

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस हड़ताल से पहले भी इस प्रदेश में एक हड़ताल हो चुकी थी और उस हड़ताल के सुलझाने का भार उस समय की सरकार ने माननीय चरणसिंह के ऊपर छोड़ा था और उन्होंने उस हड़ताल को समाप्त करने के सिलसिले में कुछ प्रयत्न किया था और उसी के आधार पर इस समय मंहगाई भत्ता इत्यादि बढ़ाया गया है ?

श्री चरणसिंह—

जी हां, अगस्त में जो एक बार भत्ता बढ़ाया गया था वह मेरी रिपोर्ट देने के फलस्वरूप बढ़ाया गया था।

श्री शफीक हुसैन रिजवी—

मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि ११ स्टेट तो ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से कम महंगाई भत्ता देते हैं और दो में ज्यादा मिलता है, तो मैं जानना चाहूंगा कि उन ११ स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार जहां कायम है वह कौन-कौन सी हैं।

श्री चरणसिंह—

कुछ में कांग्रेसी और कुछ में गैर-कांग्रेसी सरकार हैं और जिन दो स्टेट्स से कम मिलता है वह महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल हैं, उनकी आमदनी हमसे करीब दूनी है।

प्रश्नोत्तर के लिए अधिक समय की मांग

श्री इन्द्रलाल (जिला मैनपुरी)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। दो तीन दिन से मैं बराबर देखता आया हूं कि यहां सदन में केवल १५–२० प्रश्न ही हो पाते हैं और शेष प्रश्नों पर सप्लीमेन्टरी करने का अवसर नहीं मिलता। जो प्रश्न भी यहां किये जाते हैं वे अत्यन्त लोक महत्व के होते हैं। जिन प्रश्नों के संबंध में सप्लीमेंटरी नहीं हो पाते हैं, उनको अगर दुबारा देते हैं तो उसमें बहुत समय लग जाता है और उनके आने से पूर्व ही सत्रावसान तक हो जाता है। प्रक्रिया नियमावली के नियम १५ के अनुसार माननीय अध्यक्ष को १५ मिनट तक समय बढ़ाने का अधिकार है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप प्रश्नों का समय अपने अधिकार से कुछ बढ़ा दिया करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य पहली बार इस सदन में आये हैं। यही बात कल भी माननीय गेंदा सिंह जी ने उठायी थी कि प्रश्नों का समय कुछ बढ़ा दिया जाय। मैंने उसके उत्तर में यह कहा था कि यह सदन उसके लिये सक्षम है, वह जो भी समय निर्धारित करना चाहे कर सकता है।

[श्री अध्यक्ष]

सदन जो भी प्रक्रिया चाहे निर्धारित कर सकता है। मैंने कल यहां सदन में यह भी कहा था कि हाउस आफ कामन्स में यह भी थिंकिंग है कि प्रश्नों के लिये जितना समय दिया जाता है वह कम किया जाय और उसके लिए सप्ताह में कुछ दिन ही निर्धारित कर दिये जायं। प्रति दिन प्रश्न न रखे जायं। तो यह सदन के अधिकार की बात है, सदन को पूर्ण अधिकार है, वह जो समय चाहे रख सकता है।

जहां तक नियम १५ के अन्तर्गत समय बढ़ाने का अधिकार है, वह तो अंत में, जब कोई वाद-विवाद अवशेष रह जाय, मैं १५ मिनट का समय अपने आप बढ़ा सकता हूं। लेकिन साधारण कितना समय हो यह तो सदन ही निश्चय करेगा।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)--

इस संबंध में आप जब कोई फैसला लें तो इस पर भी विचार कर लें कि हाउस आफ कामन्स में पार्लियामेन्ट के मेम्बरों को एडमिनिस्ट्रेशन की डिफिकल्टीज या उसकी खराबियों आदि के बारे में कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने एक पार्लियामेंट के मेम्बर से पूछा भी था कि आप अपने क्षेत्र की दिक्कतों को कैसे रखते हैं, उन्होंने कहा कि उस को तो एडमिनिस्ट्रेशन खुद देखता है। वहां का एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहां जैसा नहीं है और वहां की तुलना नहीं की जा सकती।

श्री अध्यक्ष--

मैं फिर यह दोहरा दूं, मुझे इस पर विचार नहीं करना है। मैं समय भी निर्धारित नहीं करूंगा। उसके लिये तो यह सदन ही सक्षम है। सदन यदि चाहे तो नियमों में परिवर्तन कर समय बढ़ा सकता है और उसके लिये प्रक्रिया है। यह भी मैंने कहा कि जो होता है उसको आवश्यकतानुसार अनुसरण करना चाहिये। मैंने कहा कि वह भी एक विचार-धारा है।

प्रदेश की विषम खाद्य स्थिति तथा बढ़ती हुई कीमतों के सम्बन्ध में वक्तव्य

खाद्य मंत्री (श्री झारखण्डे राय)--

माननीय सदस्य, मेकराम शर्मा ने काम रोको प्रस्ताव की मांग इस आधार पर की थी कि गेहूं के भाव ४५ रुपया प्रति मन और चीनी के भाव ५ रुपया प्रति किलो है तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं। माननीय अध्यक्ष ने काम रोको प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था। परन्तु मैंने इस विषय पर सदन में वक्तव्य देने का आश्वासन दिया था। इस कारण आज मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं।

पहला प्रश्न गेहूं के मूल्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की २० मुख्य मंडियों के औसत भाव इस वर्ष निम्न प्रकार रहे हैं:

	प्रथम पक्ष में	द्वितीय पक्ष में
	(प्रति क्विन्टल में)	
फरवरी	१२७.२६	१३९.७५
मार्च	१२९.७०	१३६.८३
अप्रैल	१२४.८९	१०९.५०
मई	११९.१९	११७.७६
जून	११९.९१	..

इन भावों को देखने से यह बात स्पष्ट है कि गेहूं के भावों में स्थिरता रही है। सब से कम भाव अप्रैल के दूसरे पक्ष में रहे। उसका मुख्य कारण यह था कि नई सरकार ने प्रदेश का शासन संभाला था एवं जिनके पास गल्ले के जखीरे थे उन्होंने शासन के डर से उन जखीरों को बेचा। जिन किसानों के पास पिछले वर्ष की पैदावार का गेहूं था वह भी नई फसल आने के कारण बाजार में आया। उस समय पूर्वी क्षेत्रों में जहां अनाज की बहुधा कमी रहती है। रबी की कटाई हो गई थी इसलिये उन क्षेत्रों की मांग बाजार पर अधिक नहीं थी। धीरे-धीरे पहाड़ी और पूर्वी क्षेत्रों की मांग बढ़ती गई। गत वर्ष धान की फसल को बहुत क्षति पहुंची थी। साधारणत: ३२ लाख टन चावल हमारे प्रदेश में पैदा होता था जब कि गत वर्ष २० लाख टन से भी कुछ कम पैदा हुआ। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पंजाब के जोन से अलग कर दिया गया। पंजाब सदा से "सरप्लस" क्षेत्र रहा है। इसलिये "डेफिसिट" क्षेत्रों की कमी का भार इस वर्ष प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों को सहन करना पड़ा।

२—गेहूं की आमद ३१ मुख्य मंडियों में पिछले तीन वर्षों में पहली अप्रैल, से १५ जून तक के ढाई महीनों में निम्न प्रकार रही है :

	क्विन्टल
१९६५	३,८४.४८५
१९६६	३,६९,५७०
१९६७	३,४१,०९३

इस बात को देखते हुए कि पिछले वर्षों में कुछ पंजाब का गल्ला भी इन मंडियों में आ जाता था यह नहीं कहा जा सकता कि इस वर्ष किसानों ने खुले बाजार में उससे कम गेहूं बेचा है जितना कि वे साधारणत: बेचा करते थे बल्कि इसके विपरीत किसानों ने कदाचित खुले बाजार की मंडियों में पहले से अधिक गेहूं बेचा है। साथ ही साथ उन्होंने सरकारी खरीद में काफी मात्रा में गेहूं दिया है। गेहूं के आवागमन पर उत्तर प्रदेश में कोई प्रतिबन्ध नहीं है इसलिये सभी क्षेत्रों में गेहूं पहुंच रहा है और जगह जगह के भावों में कोई विशेष अंतर नहीं है। कभी मांग अधिक होने के कारण और आमद कम होने के कारण मंडी में भाव बढ़ जाते है। कभी मांग कम और आमद अधिक होने के कारण भाव कुछ गिर जाते हैं।

किसानों ने काफी गेहूं बेचा है। परन्तु अब भी बड़े किसानों के पास काफी गेहूं है और सरकार यह आशा करती है कि किसान लोग बराबर बाजार में गेहूं लाकर बेचते रहेंगे ताकि सब की मांग पूरी होती रहे। परन्तु किसी भी समय जब सरकार यह समझेगी कि बाजार में गेहूं नहीं आ रहा है और बड़े बड़े किसान अपने पास काफी मात्रा में गेहूं रखे हैं तो उन पर प्रतिबन्ध लगाने में संकोच नहीं करेगी।

संभवत: गेहूं के भाव कुछ सस्ते हो सकते थे यदि भारत सरकार से हमको पूरा निर्धारित कोटा मिलता रहता। परन्तु उन परिस्थितियों के कारण जिनको सभी माननीय सदस्य जानते हैं भारत सरकार से हम को पूरा कोटा नहीं मिल पाया है। खाद्य स्थिति गम्भीर है परन्तु घबराहट का कोई कारण नहीं है। हम को आशा है कि इस वर्ष खरीफ की फसल अच्छी होगी। उसके अच्छी होने से हमारे खाद्य स्थिति में सुधार होगा। खरीफ की फसल बाजार में आने तक भाव अवश्य ऊंचे रहेंगे परन्तु अनाज सब को उनकी आवश्यकतानुसार मिलता रहेगा।

चीनी

राज्य सरकार को चीनी का वितरण "शुगर कन्ट्रोल आर्डर" के अन्तर्गत भारत सरकार करती है। जैसा कि नीचे लिखे आंकड़ों से विदित होगा चार वर्षों में पिछले वर्ष सब से कम चीनी बनाई गई :

	लाख टन
१९६३–६४	२५.६
१९६४–६५	३२.३
१९६५–६६	३३.०
१९६६–६७	२३.०

फरवरी मार्च १९६७ तक उत्तर प्रदेश का २८,०८० टन प्रतिमास चीनी मिलती रही परन्तु उत्पादन में भारी कमी के कारण भारत सरकार ने अप्रैल में इस मात्रा को घटाकर २०,००० टन कर दिया और उसके बाद कई जून से हमारा कोटा केवल १६,७२० टन कर दिया गया है। अन्य राज्यों का भी कोटा इसी प्रकार कम हुआ है। कोटे में इस भारी कटौती के कारण हर एक वर्ग के चीनी के उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ा है।

गन्ने की पैदावार कम होने के कारण पिछले वर्ष खंडसारी का उत्पादन भी कर रहा है जिसके फलस्वरूप चीनी की कमी खंडसारी से भी पूरी नहीं हो पायी है। खंडसारी का निर्यात प्रदेश में पहले से ही बन्द है और सरकार ने पुलिस चेक पोस्ट स्थापित कर के निर्यात रोक पर और भी कड़ी देख रेख कर दी है। परन्तु ऐसा अनुमान है कि सट्टेबाजी के कारण खंडसारी के दाम बढ़ गये हैं। इस सम्बन्ध में यदि आवश्यक हुआ तो सरकार खंडसारी के स्टाक फ्रीज करने में संकोच नहीं करेगी।

इस प्रकार इधर तो कोटे में भारी कटौती, उधर मई, जून माह में शादी ब्याह के संबंध में गर्मी छुट्टियों, आदि की अधिक मात्रा में चीनी की मांग से चीनी का अभाव हो गया है।

(श्रीनेक राम शर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आपको अनुमति देने से पहले इतना अर्ज स्पष्ट कर दूं कि चूंकि मैंने कामरोको प्रस्ताव की ५१–५२ में स्वीकार नहीं किया गया था और माननीय मंत्री जी ने महत्व को देखते हुये वक्तव्य देना स्वीकार कर लिया था, इसलिये स्पष्टीकरण के लिये केवल दो एक सवाल करें। वहीं तक इसे सीमित रखें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

इस वर्ष बाजार में ४५, ५० रुपये मन गेहूं और ५ रुपये किलो चीनी ब्लैक में बिक रही है, यह क्या सही है? मंत्री जी को इसकी सूचना है?

श्री हरसहाय राय—

जहां तक गेहूं के थोक का भाव का सम्बन्ध है, मैंने बयान में कहा है कि मई-जून के पिछले तीन पक्षों में दाम करीब ११०, ११७ और ११७ रुपये हैं। २ रुपये प्रति क्विंटल कोई ज्यादा अन्तर नहीं है। मुमकिन है कि रिटेल में माननीय सदस्य के बताये भाव हों। चीनी के विषय में जैसा उन्होंने कहा, अन्य लोग भी ऐसा कहते रहते हैं। यह बात सही है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

पूर्वी भाग में जैसे गोरखपुर, बनारस, फैजाबाद डिवीजन हैं वहां गेहूं या दूसरे गल्ले के क्या भाव हैं जिनकी मंत्री जी को सूचना है ?

श्री झारखण्डे राय—

सरकार के पास मंडियों के थोक भाव आते हैं, २० मंडियों के जो मुख्य हैं। यही परम्परा रही है जो अब भी चल रही है। वही मैंने दिये हैं।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

ब्लैक मार्केटिंग और महंगाई जितने बड़े स्तर पर रोकी जा सकती है माननीय मंत्री जी कोशिश कर रहे होंगे लेकिन उस के बावजूद भी वह फेल हो रहे हैं, क्या यह सही है कि वह यह महसूस करते हैं कि जब तक गल्ले का राजकीय व्यापार नहीं होगा तब तक यह समस्या नहीं सुलझेगी ?

श्री झारखण्डे राय—

यह सवाल तो सर्वथा उचित है और व्यवहार का प्रश्न है। जिस तरह से हम अनुभव इकट्ठा कर रहे हैं उसमें बहुत सम्भव है कि हम सब इस जगह पहुंच जावें के सिवाय उसके और कोई उपाय नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—

मंत्री जी क्या कदम उठा रहे हैं कि रिटेल में प्राइस ज्यादा न बढ़ें और चीनी ब्लैक में न बिके ?

श्री झारखण्डे राय—

भावों को नीचा और स्थिर करने की दिशा में कुछ बातें विचाराधीन हैं जिनका अनुभव जन-जीवन का है उनसे प्रदेश के कोने कोने से ये शिकायतें मिली हैं कि बड़े-बड़े किसान भी अब बिना लाइसेंस लिये व्यापारी का काम करने लगे हैं और गल्ला होर्ड कर के भाव बढ़ने पर बेचते हैं। दूसरी बात यह है कि व्यापारी और किसान में षड़यंत्र सा दिखाई पड़ रहा है। बड़े किसानों के यहां व्यापारी गल्ला खरीद कर बड़ी मात्रा में रख देता है बजाय इसके कि अपने गोदाम में लाकर रखे। इस प्रकार कानून के चंगुल से वह बचता है और धीरे-धीरे वह गल्ला बाजार में लाकर ऊंचे दाम पर बेचता है। इन दोनों बातों की ओर हमारी निगाह है और हम विचार कर रहे हैं कि बड़े किसानों पर भी सीलिंग निश्चित कर दी जाय जिससे अधिक गल्ला वे नहीं रख सकते। इसके साथ ही साथ मुख्य विचाराधीन विषय खाद्यान्न का बाजारों में दाम निश्चय करने का है। लेकिन अभी तक उसकी कोई निश्चित रूप रेखा नहीं बन पायी है। जैसा मैंने अपने बयान में कहा है चीनी हमारे देश में इस वर्ष कम पैदा हुई है उसका असर पड़ना अवश्यम्भावी है लेकिन जो ब्लैक मार्केटिंग चल रही है उसके तीन सूत्र हमें मालूम हुए हैं—१—थोक कन्जूमर्स अपने निर्धारित कोटे में से एक भाग ब्लैक में बेचते हैं, इसका अन्दाजा है। २—आजकल चीनी के बढ़े हुए भाव होने के कारण, बहुत से किसान जो अपने कार्ड पर चीनी नहीं लिया करते वे प्रायः चीनी ले लेते हैं और बाजार में हलवाइयों को दे देते हैं (शोर) आपके इस प्रकार शोर करने से तो मैं कुछ समझूंगा नहीं मेरे हृदय में जो साफ-साफ बात है उसको मैं कह रहा हूं। मेरे बाद जो आप कहना चाहें कहें। लेकिन पहले आप कृपा करके मुझ से सुन लें, उसके बाद कहें। ३—चीनी मिलों को भी भारत सरकार कुछ कोटा छोड़ देती है, इसके अलावा कुछ चीनी वे लोग चोरी करके भी लाते हैं, उस को भी बड़े पैमाने पर ब्लैक किया जाता है। सब से बड़ा सोर्स यही हमें मालूम

[श्री झारखण्डे राय]

पड़ता है। इस सब की रोकथाम के लिये सरकार विचार कर रही है और निकट भविष्य में जो भी निश्चय होगा उसके अनुसार जो भी संभव होगा वह कदम उठाया जायगा।

श्री अध्यक्ष--

मैं एक बात फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं। संयोग से इस पर वैसा ही वादविवाद चल गया है। मैं माननीय सदस्यों की इच्छा देखकर इस के लिये ७ मिनट और दिये देता हूं और ७ मिनट के बाद यह अपने आप समाप्त हो जायगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

अभी माननीय मंत्री जी ने तीन सोर्स बताये उसके बारे में मेरी जानकारी है कि भारत सरकार जो चीनी मिल मालिकों से लेती है उसका कुछ प्रतिशत मिलों के पास रह जाता है और कुछ चीनी उत्पादन में कम दिखा कर वे बड़ी मात्रा में चीनी बेच लेते हैं जो खुले आम बिकने के लिये आम बाजार में आती है तो क्या सरकार भारत सरकार से यह निवेदन करेगी कि वह पूरी की पूरी चीनी मिलों से ले लिया करे?

श्री झारखण्डे राय--

माननीय सदस्य ने जिस बात की ओर मेरा ध्यान दिलाया है उसकी चर्चा मैंने अपने बयान में कर दी है। बड़े पैमाने में इसी प्रकार चीनी मंडियों में आती है। इसकी रोकथाम के लिये विचार किया जा रहा है और जल्द ही इस मसले को भारत सरकार तक ले जाना चाहते हैं।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)--

क्या सरकार बतायेगी कि ऐग्रीकल्चर विभाग द्वारा जो १४३ रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा जाता है वह भाव एग्रीकल्चर इन्सपेक्टर नियुक्त करता है और बाजार भाव पर ३ रुपया प्रति क्विंटल सब्सीडी दी जाती है तो इतने ऊंचे रेट पर जो खरीदारी हो रही है उस भाव से और जो माननीय मंत्री जी ने बताया, क्या उसमें कोई साम्य है?

श्री झारखण्डे राय--

इसका संबंध कृषि विभाग और बीज की खरीद से है, अगर माननीय सदस्य सूचना देंगे तो इसका उत्तर दिया जा सकता है।

श्री जी० एस० चौधरी (जिला मेरठ)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस साल खंडसारी शक्कर सूबे में कितनी बनी है और शक्कर के वितरण के बारे में आपका क्या प्रोग्राम है?

श्री झारखण्डेराय--

अगर वह सूचना दें तभी वह बताया जा सकेगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

यह देखते हुये कि प्रदेश में इस समय चीनी की कमी है अगर उसके साथ साथ यहां दूध की भी कमी होती जा रही है और बच्चों तक को पीने का दूध नहीं मिल रहा है, तो इन दोनों समस्याओं को हल करने के लिये क्या मन्त्री जी खोये से बनी हुयी मिठाइयों पर प्रतिबन्ध लगवाने की कृपा करेंगे जैसा कि पंजाब और दिल्ली में किया गया है?

श्री झारखण्डे राय--

माननीय सदस्य का सुझाव बहुत सही है और उस पर गौर किया जायगा।

श्री महेश कुमार (जिला मुरादाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय खाद्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन हलवाइयों को कोटा शक्कर का दिया जा रहा है वह भी बाजार में खुले आम ब्लैक के रेट में पर मिठाई बेचते हैं क्या यह सही है और दूसरे यह कि मिल मालिक जो बड़े शक्कर के हैं वह दानेदार खंडसारी खरीदकर चीनी की बोरियों में मिलाकर भरते हैं ? क्या मंत्री जी इसको रोकने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री झारखण्डे राय--

जिस प्रकार चीनी की कमी के कारण अन्य लोगों के कोटे में कटौती की गयी है, उसी प्रकार से हलवाइयों के कोटे में भी कमी की गयी है। उनका भी कोटा वास्तविक रह गया है।

जहां तक दूसरा प्रश्न है कि दानेदार चीनी पीसकर बूरा बनाते हैं सरकार इस पर गौर करेगी।

श्री अध्यक्ष--

अब यह विवाद समाप्त हो गया।

एक सदस्य--

एक बहुत आवश्यक सवाल बाकी है ?

श्री अध्यक्ष--

बहुत सारी बातें आवश्यक होती हैं। हमारे सदन में ४२६ सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को १-१ प्रश्न पूछने दिया जाय तो शाम तक भी पूरा न होगा।

मेरी जरा सी कठिनाई है। मैं चाहता हूं कि आप नियमों का अध्ययन करें। जिस तरह का यह वक्तव्य है, सदन की परम्परा और नियम यह है कि साधारणतया जिस माननीय सदस्य का प्रस्ताव होता है उनको स्पष्टीकरण करने का समय दिया जाता है। इस पर मैंने करीब ७ मिनट का समय दे दिया है। इसको पर्याप्त समझिये। यदि इस पर आप चर्चा करना चाहते हैं तो प्रश्नों द्वारा सूचना मांग सकते हैं।

१९६७-६८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--

अब आय-व्ययक पर सामान्य विवाद होगा।

*श्री राममूर्ति (जिला बरेली)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बजट के उपर आज तीसरे दिन सामान्य विवाद हो रहा है। इस पर माननीय सदस्यों के जो भाषण हुये, उनको मैंने बड़े गौर से सुना। हम सब इस बात को जानते हैं कि किन हालात में आज की सरकार बनी। ये जो पार्टियां यहां पर चुनकर आयी हैं और जो सरकार बनाये बैठी है, ये सरकार बनाने के काबिल नहीं थी लेकिन बदकिस्मती से हमारी कांग्रेस की संस्था में से एक टुकड़ी टूटकर उधर चली गई और उसकी मदद से यह सरकार बनी। अब जाहिर है कि सरकार जो बनी उसमें बहुतसी पार्टियां हैं, जिनके सोचने और विचार करने के तरीके अलग अलग हैं, उनके दर्शन, आडियोलाजी और मौलिक सिद्धान्त अलग अलग हैं

†२० जनवरी, १९६७ की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राममूर्ति]

प्रगतिशील पार्टी, जैसे हमारे उग्रसेन जी की पार्टी, पी० एस० पी० की पार्टी, झारखंडेराय जी की कम्यूनिस्ट पार्टी जैसी वहां हैं। वहां पर ऐसी भी पार्टियां हैं जिनके बारे में यह भी मालुम नहीं कि वे किन हालात पर बनी हैं, उनके उसूल क्या हैं। तो ऐसी मखलूद पार्टी की बनी हुयी सरकार की थिंकिंग क्लियर होगी, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है और जब कोई क्लियर थिंकिंग नहीं होगी और एक स्टीप गैप एरेंजमेंट के नजरिये से कोई सरकार बनायी गई होगी तो उसके काम करने के तरीके क्या होंगे, यह हमारे सोचने और समझने की बात होगी।

बाइबिल में लिखा है "ब्हेन दियर इज नो विजन, पिपुल पेरिश"

इस सरकार से यह उम्मीद करना कि हमारे लिये कोई अच्छा बजट बनायेगी मैं उम्मीद नहीं करता।

इस सरकार की जिन्दगी २–३ महीने की है और मैं उनकी मुश्किल को भी समझ रहा हूं कि हमारे मुल्क में एक संविधान है उसके अन्दर इनको काम करना पड़ रहा है तो उन हालात में कोई बड़ी भारी चीज, क्रांतिकारी चीज पैदा कर दें यह हो भी नहीं सकता। लेकिन जिन बातों का गवर्नर साहब के ऐड्रेस में जिक्र किया गया था वह तो जानते नहीं थे ये लोग कि इनकी सरकार बन जायेगी। पिछले २०, २५ साल से विरोध में बैठे-बैठे एक आदत पड़ गई थी गैर जिम्मेदाराना बात करने की। कोई पार्टियां भी नहीं समझती थी कि उसकी सरकार बनेगी, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ या किसी पार्टी को देख लीजिये। अब इत्तिफाक से बन गई सरकार और सारी जिम्मेदारी गले में आकर लटक गई सब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि उन मुश्किल कामों को न कर सकते, मैं समझता हूं कि कर नहीं पायेंगे क्योंकि जो प्रोग्राम जिसका जिक्र किया गया था उसके लिये बड़े रिसोर्सेज की जरूरत है। यह प्रदेश गरीब है, इस प्रदेश की गरीबी यहां तक है कि यहां की आबादी ऐसी घनी है, एक एक मील के अन्दर १,६०० आदमी रहते हैं, गोरखपुर डिवीजन में करीब १ करोड़ आदमी रहते हैं, आधे लोग भुखमरी की हालत में रहते हैं और ऐसी कितनी समस्यायें हैं उन्हें हल कर पाना कोई बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन एक बात हो सकती थी ईमानदाराना तरीके से उस बजट को जो पढ़ा गया वित्त मंत्री द्वारा यह बताया जा सकता था कि जो प्रोग्राम जिसका हमने जिक्र किया है उसके मुकम्मिल करने में कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, वह रिसोर्सेज हम कितने दिनों में कर पायेंगे या नहीं कर पायेंगे। उसमें से कितना ऐसा प्रोग्राम है जिसको शायद हम कभी भी नहीं कर पायें, तो एक सेकनियती का अन्दाज हो जाता और लोगों के दिल में भ्रम नहीं रहता। आज वह समझते हैं कि जो बात कह दी है उसको पूरा करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं हो सकती। अगर वह बतला देते तो भ्रम दूर हो जाता और सोचने के तरीके में तबदीली हो जाती।

मैंने कहा कि सरकार बनी और हमारे बड़े साथी श्री चरण सिंह ने इस सरकार को बनाया। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से सरकार को उन्होंने बनाया वह कोई अच्छी बात नहीं है। जिन हालात में पार्टी को उन्होंने छोड़ा, मैंने उनके बयान पढ़े जो पार्टी छोड़ने के पहले उन्होंने दिये थे। वे बातें कोई नयी नहीं थी। माननीय मुख्य मंत्री या उनके और साथी मास्टर जी बैठे हुये हैं; वर्मा जी के इस कांग्रेस में ३०, ४० साल गुजर गये हैं हम उनके साथ रहे हैं, इस कांग्रेस की खराबियों को जानते थे, इस पार्टी के अन्दर जो लोग हैं उनके बारे में अच्छी तरह से जानते थे, उनके तर्जेअन्दाज को जानते थे, उनकी मजबूतियों और उनकी कमजोरियों को जानते थे, वह सब जानने के बावजूद एक दम यह कदम उठाया, यह अच्छी बात नहीं है। इससे तो जो ह्यूमन वैल्यूज हैं जिनके अन्दर कुछ स्वच्छता, पवित्रता, गरिमा है, उनको ठेस लग गई। और भी ऐसे प्रदेश हैं जहां लोगों ने पार्टियां छोड़ीं। कांग्रेस की पार्लियामेंट बोर्ड जो बड़ी जमात है उसकी ऐक्जीक्यूटिव से सलाह मशिवरा किया और अपने खयालात के अन्दर अगर कोई फर्क था तो उसको जाहिर किया और देखा कि उनके खयालात पूरे नहीं हो रहे हैं तो जमात छोड़ दी। लेकिन जिस तरीके से हमारे प्रदेश के अन्दर हुआ यह आगे आने वाले लोग भी इसको अच्छा नहीं कहेंगे।

मैंने कहा कि ह्यूमन वैल्यूज को जो एप्रिशियेट करते हैं वे कभी इस बात को अच्छा नहीं बता सकते। आज रास्ता क्या है, मैं यह भी कह रहा हूं इतने दिनों का साथी होने के नाते, हमारे यहां एक रास्ता यह भी है कि अगर इंसान से गलती हो तो प्रायश्चित करे महात्मा गांधी भी जब गलती करते थे तो अपनी गलती माना करते थे। तो आपके लिये भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई गलत बात हो गई है तो उसका प्रायश्चित आप कर लें, उससे आपको शान्ति मिलेगी और जो हमारे देश के लोग हैं उनके लिये रास्ता खुल जायगा। इसके मानी यह नहीं है कि प्रायश्चित की बात कल हो सोचने लगें और बजट बिड़ी-बिड़ी हो जाय। यह काम हो गया है। आप इसे चलाइये लेकिन अगर देश के अन्दर जनतंत्र चलाना है तो आखिर में सोचना पड़ेगा कि यह जो आदत पड़ गयी है इधर से उधर जाने की यह आइत छूटे।

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यह आदत कब से शुरू हुई। सन् ५० से शुरू हुई थी?

श्री राममूर्ति—

मैं माननीय चौधरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि कोई गलत आइत पड़ी हुई हो तो हमें सोचना जरूरी नहीं है। अच्छी आदतें हम सीखें और बुरी आदतें छोड़ें। जब हम किसी टिकट पर खड़े हों तो देख लें कि उस पार्टी का क्या लक्ष्य है, क्या नब्बू नेचर है? अगर किसी पार्टी का टिकट पसन्द न हो तो फिर एक पार्टी और है जिसका नाम आजाद है। उसको आजादी है जहां चाहें बैठ जायं। उनसे कोई शिकायत नहीं हो सकती लेकिन जो सिम्बल पर चुनकर आये हैं उन पर जिम्मेदारी है।]

हमारे खाद्य मंत्री जी ने एक बात यह कही कि यह मिली जुली सरकार है। कोई खिचड़ी है जो मिल कर खा जायेंगे? सरकार को कनोवर शियस होना चाहिये। कम्युनिस्ट सरकार होती तो हम जानते कि कम्युनिस्ट सरकार किधर ले जायगी। कोई प्रगतिशील कदम उठाना हो तो कैसे उठेगा? यह तो ऐसे हो गया है जैसे वस्त्र काटना हो। केवल इस पार्टी को सरकार को हटाना था। कोई अच्छा लक्ष्य नहीं बनाया था, हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं था। केवल यह था कि हमको इस सरकार को हटाना है। परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार गिर गयी और मिली-जुली सरकार बन गयी। यहां भी बड़ी खराबी पैदा हो गई थी। यह पार्टी एरोगेन्ट बन गयी थी। झटका लग गया है तो हालात ठीक हो जायेगी और अब यह महसूस होने लगा है कि जमीन पर चलो।

मुझे खुशी है कि हमारे बहुत से भाई जो अब ट्रेजरी बैंचेज पर बैठे हैं उनको सरकार की जिम्मेदारियों से कुछ वाकफियत हुई। जब तक यहां नहीं बैठे हुये थे तब तक निहायत गैर जिम्मेदाराना तरीके से हाउस में काम हुआ करता था। जो देखने वाले आते थे वे सोचते थे कि असेम्बली किस स्तर पर पहुंच गई है। उन हालात में तब्दीली होगी। विकल जो बैठे हैं। दिक्कतों को समझने लगे हैं, इसी से उनकी आवाज धीमी पड़ गयी है। आज इस मुल्क के अन्दर कितनी गरीबी है, बेकारी है, बेईमानी है।

एक सदस्य—

आपकी देन है।

श्री राममूर्ति—

यह हमारे जमाने की है और आपके जमाने की भी हम देखेंगे। तो इतनी बड़ी कलोसल प्राब्लेम को हल करना कोई नारेबाजी से काम पूरा होने वाला नहीं है, इसके लिये हमें अपने देश के लोगों की आदत डालनी होगी मेहनत करने की और अगर हम यह नहीं करेंगे तो हमारा काम आगे नहीं चल सकता। इस काम को करने के लिये जो जिम्मेदारी आपके ऊपर आयी है उसका पूरा फायदा उठाया जायगा और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट की जो नीति है वह मजबूत होगी, लोगों के साहस बढ़ेंगे.....

एक सदस्य—

तीन-तीन हजार बीघे का लोगों ने फार्म बना लिया है ।

श्री राममूर्ति—

यह कोई छिपी बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों का इस तरह से बीच में टोकना और आक्षेप करना उचित नहीं समझता हूं ।

श्री राममूर्ति—

जितनी बातों का जिक्र किया उनमें से सिर्फ अभी दो ही कदम उठाये गये हैं । एक कदम तो भूमि भवन कर को माफ किया । मैं थोड़ा उसके बारे में बतलाना चाहता हूं । जब चीन की लड़ाई हुई तो हमारे इस प्रदेश में सरकारी अफसरों का खयाल, हुआ कि रिसोर्सेज और बढ़ाने चाहिये । खयाल था कि प्लान का बहुत ज्यादा रुपया ग्रामीण क्षेत्र में खर्च किया जाता है । उनकी कुछ हालत भी अच्छी हो रही है । यद्यपि ग्रामीण क्षेत्र इतना बड़ा है कि उसकी हालत कितनी अच्छी हो रही है उसका हम सब अन्दाज कर सकते हैं । लेकिन एक आम खयाल है कि अनाज के दाम काफी मंहगे हैं वहां के लोगों की हालत बेहतर हो रही है और उनके ऊपर कुछ थोड़ा-सा टैक्स और लगाया जाय । माननीय मुख्य मंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, मैं भी उसी क्षेत्र का हूं और मैं उनसे बहुत-सी बातों में इत्तफाक करता हूं । मैं भी इस राय का हूं कि प्लानिंग के अन्दर जो रुपया खर्च हुआ है उसका काफी रुपया शहरों में आया है और जरूर उनसे कुछ रुपया पैदा करना चाहिये । तो इसका प्रादुर्भाव उस वक्त से हुआ, भूमि भवन कर लगाया गया । खासतौर से इस तजवीज के करने में हमारे मुख्य मंत्री जी का हाथ था । लेकिन आज ऐसी महादेव जी की बरात में वे फंस गये हैं कि उस अच्छे कदम को भी पीछे हटाना पड़ा और भूमि-भवन कर को खत्म करना पड़ा । (लालबत्ती होने पर) अध्यक्ष जी, आप कितने ही सालों से इस सभा को सुशोभित कर रहे हैं और आप जानते भी हैं कि मैं कभी कभी बोल लिया करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा आप ५ मिनट और बोल लें ।

श्री राममूर्ति—

तो भूमि भवन कर हटाया, यह अच्छा नहीं है । हमारे रिसोर्सेज जो थोड़े बहुत थे भी वह भी कम हुये ।

आपने एक कदम और उठाया । बड़ी एक मासूम चीज यहां आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स थे वह आपने हटा दिये । मैं आपको जुडिशल रेफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट सुनाता हूं । सन् १९६० में १ लाख ३५ हजार केसेज आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स के द्वारा किये गये, १९६१ में १ लाख ४१ हजार केसेज किये गये, १९६६ में १ लाख ३० हजार से ज्यादा किये गये । यू० पी० जुडिशल रेफार्म्स कमेटी १९५०–५१ की रिपोर्ट है, वाल्यम १, पेज ५६ पर—

"We recommend that there should be no honorary Assistant Collectors or honorary Munsifs, but honorary Magistrates may be retained for the disposal of a large number of small criminal cases which arise particularly in big towns."

उन्होंने कहा कि आनरेरी असिस्टेन्ट कलेक्टर्स और आनरेरी मुन्सिफ तो हटा दिये जायं लेकिन आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स न हटाये जायं ताकि बड़े-बड़े शहरों में जो छोटे-छोटे क्रिमिनल केसेज होते हैं उनको वह डिस्पोज आफ कर सकें ।

रिफार्म आफ जुडिशल ऐडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में ७१८ पेज पर उन्होंने कहा है —

In U. P. the honorary magistracy has helped to expedite the disposal of criminal cases and to relieve the congestion of criminal courts. They dispose of nearly 25 per cent. of the cases in this State. It is clear from this fact that honorary Magistrates were capable of serving a very useful purpose in relieving the paid magistracy from as much as 25 per cent of its work. We recommend that the system should be introduced in the States where it has not so far been in vogue."

यह रिपोर्ट उसने दी है। यह आप जानते हैं कि बहुत से केसेज एरियर्स में रहते हैं लेकिन फिर भी आपने सारे आनरेरी मजिस्ट्रेटों को हटा दिया है। एक तरफ तो आप इकोनोमी की बात करते हैं और दूसरी तरफ इनको हटाने से कितना रुपया आपको इन केसेज के लिये खर्च करना पड़ेगा, यह सोचने की बात है। दूसरी बात यह है कि क्या यह तय हो गया है कि यह जो सारे मैजिस्ट्रेट्स हैं वह सब महाराजा हरिश्चन्द्र हैं ? क्या उनसे गलती नहीं होती। सारे इंस्टीट्यूशन को बेइमान कहना अच्छा नहीं है। वैसे इस से मुझे मतलब नहीं है। यह तो आपके सोचने की बात है। इसलिये मैंने इशारा किया कि इसमें इकोनोमी का तालमेल नहीं था।

प्राइसेज के बारे में जिक्र हुआ। यह सरकार जिस समय बनी थी तो अखबारों में छपता था कि आज इसकी इतनी कीमत गिर गई, उसकी इतनी कीमत गिर गई और माननीय मुख्य मंत्री जी ने बयान दिया कि इस साल बड़ी बम्पर क्राप है। लेकिन बम्पर क्राप होने के बावजूद भी आपने देखा कि प्राइसेज नीचे नहीं आयीं बल्कि दिन-ब-दिन बढ़ती चली जा रही हैं। आपने जो यह गल्ला इकट्ठा किया है, जब लीन मैंथ्स आयेंगे उस समय गल्ले को रिलीज करने से शायद प्राइसेज में कुछ चेक हो। लेकिन कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिये जिससे प्राइसेज बढ़े नहीं। पिछले साल गेंहूं २६-२७ रुपये मन बिकता था लेकिन इस साल शुरू में ही ४५/५० रु० मन बिक रहा है। तो आगे चलकर और भी प्राइसेज बढ़ जायेंगी। दाल भी बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं इसलिये प्राइसेज को चेक करने के लिये कोशिश होनी चाहिये।

यह कहा गया कि प्लानिंग में बड़ी गलती है और गल्ले की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने जिक्र किया था कि हमने बहुत बड़ी रकम खाली माइनर इर्रीगे न ऐग्रीकल्चर और सिंचाई योजनाओं पर रखी थी और जितने टार्गेट रखे थे उससे कहीं ज्यादा रुपया खर्च किया गया। पहले कुल १,६०० ट्यूबवैल थे लेकिन उनको बढाकर हमने ८,५०० कर दिये। जब किसानों की हालत सुधरी तो जहां पहले १५ साल में केवल १,६०० ट्यूबवैल बने थे वहां उनकी एसी हैसियत हो गई कि १५ हजार ट्यूबवैल लोग लगाने के लिये तैयार हो गये। सरकार ने ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसका श्रेय मुख्य मंत्री जी को जाता है क्योंकि उन्हीं का यह विचार था कि हमारी लघु योजनाओं में मैसोनरी वेल्स बनाये जायं। मैं पहले इसके पक्ष में नहीं था लेकिन बाद में तैयार हो गया और लोगों ने एक-एक साल में ७०–८० मैसोनरी वैल्स बनाये, १५/२० हजार ट्यूबवैल्स बनाये और बोरिंग का काम हुआ।

श्री अध्यक्ष––

दो मिनट में आप अपना भाषण समाप्त कर दीजिये।

श्री राममूर्ति––

मेहरबानी करके २/४ मिनट और दे दीजिये। आप बड़े फराख दिल हैं।

श्री अध्यक्ष––

अब बोलने का अवसर आया है। आप बोला कीजिये।

श्री राममूर्ति---

सरकारी कर्मचारियों के बारे में कहा गया। आपको सोशल सर्विस के बजट को नहीं काटना चाहिये। सोशल सर्विस के रिजल्ट्स दो-चार दिन में नहीं मिलते हैं। सोशल सर्विसेज का रुपया ह्यूमन बीइंग्ज पर लगाया जाता है, इंसानों से उम्मीद रखना कि एक दम से वहां तक पहुंच जायेंगे, मुश्किल है। इसलिये मेरी सरकार से अर्ज है कि सोशल सर्विसेज का बजट बजाय घटाने के बढ़ाना चाहिये क्योंकि पिछड़ी हुयी जनता को बढ़ाने में रुपया लगता है।

एक लफ्ज सरकारी कर्मचारियों के बारे में कहूंगा। मैं माननीय झारखंडे राय और आपके और लोग हैं, उनसे माननीय मुख्य मंत्री जी से कुछ नहीं कहूंगा, कि आपने उनका बड़ा शोषण किया है। आपने उनको सही रास्ते से हटा दिया। इंडिसिप्लिन सिखा दिया जिसके जरिये कोई सरकार चल नहीं सकती। अगर सरकारी कर्मचारियों में यूनियनिज्म आ गयी तो किसी सरकार को वह चलने नहीं देंगे। हम आते-जाते रहते हैं यह मुस्तकिल हैं। हर फाइल को उठाकर देख लीजिये ८० फीसदी काम इनका होता है और ऊपर की देख-रेख हमारी होती है। आपने उनको बिगाड़ा है, हमने स्पीचेज सुनी हैं, इलेक्शन के बाद की भी स्पीचेज देखिये। वह काफी झटका खा गये। गरीबी का जमाना है। सुने खुशी है कि उनका आन्दोलन जो चला वह कामयाब नहीं हुआ। अब इतनी आप से जरूर अपील है कि जब वह सही रास्ते पर जा रहे हैं तो उनको दुत्कारिये मत। गिरफ्तारियां हो गयी, जेल में हैं उनको माफ करते हुये अपनी जगह देना चाहिये और उनको बता देना चाहिये कि आगे इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिये। वह न उनके हक में है, न प्रदेश और गणतंत्र के हक में है। उससे हमारा सबका रास्ता बिगड़ जायगा। ऐसे सरकार कभी चल नहीं सकती। उनको गलती को माफ करना चाहिये वरना अगर आपने कुछ लोगों को निकाल दिया और सड़कों पर जा पड़े तो उनके बच्चों की बद्दुआयें आपको मिलेंगी। आप अच्छे काम में लगे हुये हैं, उसी तरफ चलिये। यह मेरी आप से दरख्वास्त है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रतापसिंह)---

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यह समझता हूं कि जनतांत्रिक प्रणाली में जब किसी भी सरकार का बजट पेश किया जाता है तो विरोधी दल के नेता से उम्मीद की जाती है कि सामान्य विवाद में वह सरकार की नीतियों की आलोचना करें और उसके साथ कुछ अपने सुझाव दें। लेकिन मुझे दुख है कि माननीय नेता विरोधी दल से लेकर जो भी उनके वरिष्ठ सदस्य हैं सबने अपना दो-तिहाई समय इसमें बिताया कि माननीय चरणसिंह ने कांग्रेस को छोड़ने में क्या किया, एक तिहाई समय इसमें बिताया कि विभिन्न पार्टियों की क्या पालिसी है और यह किस तरह से यहां पर हैं। मैं आपके द्वारा माननीय नेता विरोधीदल को बताना चाहता हूं कि जब सरकार हमारे हाथ में आयी थी उस समय हमारी बैलेंसशीट क्या थी। मैं अपने लायक दोस्तों से निवेदन करूंगा कि खंड २ के पेज १६८-१६९ को पढ़ने की कृपा करें। इसमें पब्लिक से लोन लिया है ८७ करोड़ १४ लाख ४८ हजार और केन्द्र से आपने कर्ज लिया है वह ५ अरब १९ करोड़ ७४ लाख ६४ हजार है और आपने दूसरी संस्थाओं से लोन लिया है वह है १२ करोड़ ७५ लाख २५ हजार। इस तरह से ६ अरब १९ करोड़ ६४ लाख ८७ हजार कर्जा जिस स्टेट का है और फिर यह मांग आना कि हमारे एम्प्लाइज और दूसरे लोगों को कुछ मिलना चाहिये और जिस जमाने में हम बधाई भी देते थे अधिकारियों को किसी अच्छे काम के लिये लेकिन मुझे खेद है इस बात का कि जिस पद को माननीय चन्द्रभान गुप्त जैसे अनुभवी लोगों ने संभाला हो अगर उस पद पर कोई नौजवान हो जिसने पिछले दस दिनों के अन्दर १५ हजार की दवाइयां स्टोर से निकालीं, उसके बाद बनारसी दास जो कहते हैं कि यह पुलिस ऐक्ट है तो फिर मैं क्या कहूं? पर उपदेश कुशल बहुतेरे। माननीय राममूर्ति जो मेरे मित्र हैं और वे मुझे उपदेश देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे इसका जवाब दें कि श्री अशोक मेहता को जब आपने अपनी तरफ खींचा, इस प्रदेश के एक मजबूत सदस्य श्री गेंदासिंह जी

को अपनी पार्टी की तरफ खींचा तब आपका उपदेश कहां चला गया था ? मैं कहना चाहता हू कि माननीय चरणसिंह जी ने क्या काम किया—"यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत" जब माननीय चरणसिंह को मालूम हो गया कि ८ करोड़ जनता का हित कांग्रेस के जरिये नहीं हो सकता, उस आदमी की हिम्मत देखिये जिसे ४५ वर्ष का प्रशासनिक अनुभव है, वे जब यहां बोल रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे और उनके हृदय में एक वेदना थी कि गांधी जी के कांग्रेस से जो इतने वर्षों का संबंध था वह संबंध छूट रहा है। माननीय चरणसिंह जी ने प्रदेश की जनता की इच्छा के अनुसार काम किया क्योंकि जनता उनसे यही चाहती थी कि वे कांग्रेस से अलग हो कर उनकी सेवा करें। क्योंकि जनता समझती थी कि माननीय चरणसिंह जैसा व्यक्ति कांग्रेस के अन्दर रहते हुये उनकी सेवा नहीं कर सकता। हम तो माननीय चन्द्रभानु गुप्त जैसे तजुर्बेकार व्यक्ति से उम्मीद करते थे कि वे हमारे सामने कोई आस्टरिटी का बजट पेश करें लेकिन अब क्या कहा जाय। यह सही है कि जहां मिक्स्ड इकोनामी होती है वहां घाटे का बजट अच्छा होता है। आपने कहा कि यह सरप्लस बजट है। मान्यवर, बजट के पेज ६ से मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है––"राजस्व लेखे में ५५ लाख रुपये की जो बचत होने की आशा है उसके हिसाब में सम्मिलित करने के बाद २० करोड़ १७ लाख रुपये का घाटा होने का अनुमान है।" तो हमारे ऊपर यह चार्ज लगाया गया है कि हमारे पास बहुत रुपया है जिससे यह बजट सरप्लस का है वरना घाटे का बजट होना चाहिये।

दूसरी बात यह कही गयी कि किसानों के लिये इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। आपकी आज्ञा से मैं बजट भाषण के पेज ९ से पढ़ देता हूं––"रासायनिक उर्वरकों की खपत भी १९६६–६७ में ४.५२ लाख मीट्रिक टन से बढ़कर १९६७–६८ में १३.२० लाख मीट्रिक टन हो जाने की संभावना है। हरी खाद के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र भी १९६६–६७ में १५.४२ लाख एकड़ से बढ़कर १९६७–६८ में २५ लाख एकड़ हो जायगा। १९६६–६७ में भूमि संरक्षण के अन्तर्गत २.२४ लाख एकड़ क्षेत्र लाया गया जब कि १९६७–६८ में इसके अन्तर्गत २.८८ लाख एकड़ क्षेत्र और लाये जाने की संभावना है। इस साल ६५ नई फार्म इकाइयों के स्थापित हो जाने की भी आशा है।"

मान्यवर, यह भी कहा गया कि सिंचाई के लिये कुछ इंतजाम नहीं किया गया है। आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस प्रोग्रेसिव बजट और समाजवादी बजट के पेज ११ को देखने का कष्ट करें। इसमें लिखा है––"इन नलकूपों द्वारा चालू वर्ष के दौरान कुल १.३९ लाख एकड़ के अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की जा सकने की आशा है। निजी छोटी सिंचाई के कार्यक्रम का १९६७–६८ के लिये जो लक्ष्य निश्चित किया गया है, उसमें ६०,००० कुओं का निर्माण करना तथा ८०,००० बोरिंग करना और २५,००० रहट, १८,००० पंपिंग सेट, १६,५०० निजी नलकूप लगाना और १५,००० नलकूपों तथा पंपिंग सैटों में बिजली लगाना सम्मिलित है।"

श्रीमन्, इसके अलावा एक बात और कही गयी कि भुखमरी के समाधान के लिये कुछ नहीं किया गया है। मैंने अखबारों में पढ़ा कि श्री चन्द्रभानु गुप्त जैसे वरिष्ठ सदस्य का बयान निकला कि पहाड़ पर ५ आदमी भूख से मरे हैं। इस संबंध में मैंने कमिश्नर, अधिकारियों एवं उस क्षेत्र के संयुक्त विधायक दल के सदस्य के द्वारा छानबीन की। उसके बाद मैंने सोचा कि हो सकता है सूचना ठीक से न आवे, इसलिये मैं खुद उस दनिया गांव में गया जहां के लिये कहा जाता है कि ५ आदमी भूख से मर गये। मुझे इस बात का दुख है कि उस गांव में तीन आदमी भूख से मरे लेकिन वे मरे मार्च, १९६७ में जबकि माननीय चन्द्रभानु गुप्त का राज्य था। यह बात मुझे वहां के प्रमुख और प्रधानों के बयान से मालुम हुई और उन्होंने स्वयं कहा कि अप्रैल से जब से कि यह नयी सरकार आयी है एक आदमी भी भूख से नहीं मरा है और मैं इस प्रदेश की ८ करोड़ जनता को विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रदेश की किसी भी जनता को भूख से मरने नहीं देंगे।

इसके बाद अब मैं आता हूं जिसका शोर बहुत हुआ। वह है मेडिकल कालेज। मेडिकल कालेज को हमने लेने का निश्चय किया है। यह निश्चय हमने तीन कारणों को दृष्टि में रखकर

[श्री प्रतापसिंह]

किया है। नम्बर एक—पिछली कार्यवाहियां इस विधान सभा की जब हम देखें, यहां पर बार-बार कहा गया है कि वहां पर बहुत इर्रेगुलैरिटीज हैं, बजट का इस्तेमाल ठीक से नहीं होता है, और एप्वाइन्टमेंट्स ठीक से नहीं होते हैं उनमें अनियमितता बरती जाती है। इस सम्बन्ध में मैं आपकी आज्ञा से श्रीमन्, कालेज की आडिट रिपोर्ट को पेश करना चाहता हूं जो कि उस समय तैयार की गयी थी जबकि श्री गुप्ता के नेतृत्व में सरकार यहां पर बनी हुई थी। रिपोर्ट में लिखा है—

"It may be stated at the very outset that the way in shich much important records as Grant Registers and Income and Expenditure, Ledgers which served the purpose of classified abstracts, were maintained left much to be desired. The Regis e:s were not only full of cuttings, alterations and unattested additions and substractions ; but some of them also contained entries in pencil till the date of Audit. Besides, these did not bear any evidence of any review and were devoid of signatures by proper authority such as Assistant Registrar (Accounts). The officials concerned made changes in the figures 6 without bringing them to the notice of the proper authority. This was obviously a serious position."

मैं इसको आपके सामने आपको हिन्दी में भी बताना चाहता हूं। जब मान्यवर इसका स्पेशल आडिट कराया गया तो उसकी रिपोर्ट में यह बताया गया कि जिस मेडिकल कालेज को हमारी ग्रान्ट जाती है वहां पर उसका सदुपयोग होता है या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन जिनमें हिसाब-किताब रखा जाता है वे सारे रजिस्टर ठीक से नहीं बनाये गये हैं उनमें उनको इच्छानुसार मनमाने ढंग से काम किया गया है। इतना ही नहीं रजिस्टरों में जगह-जगह पर कटिंग है, बदला गया है, और मिटाया गया है और अनेक जगह पर पेंसिल से ही लिखा गया है। ऐसे कटिंग्स वगैरह पर किसी जिम्मेदार अधिकारी के दस्तखत नहीं हैं, और इन सबका परिणाम क्या हुआ? श्रीमन् ३१-३-६१ तक ३४ लाख ३९ हजार २२७ रुपये का घाटा हुआ है। और इस घाटे की पूर्ति कांग्रेस सरकार द्वारा सन् ६६-६७ में १६ लाख रुपये की डेफिसिट ग्रान्ट देकर की गयी है और यह यूनिवर्सिटी आज भी उन्हीं लोगों के द्वारा और उन्हीं लोगों के नेतृत्व में चल रही है। इस कालेज को लेने का कारण यही है कि इस सम्मानित सदन ने इस विषय में अपने अमूल्य सुझाव दिये हैं कि इसे सरकार अपने हाथ में ले ले। इस पर एक गुट विशेष का आधिपत्य हो गया था, ऐसी आवाज बार-बार इस सदन में सुनाई दी कि इसको सरकार द्वारा मिलने वाली ग्रान्ट का सदुपयोग नहीं हो रहा है, फलस्वरूप एक स्पेशल आडिट पार्टी बिठाई गयी, जिसकी रिपोर्ट आज हमने इस सदन में रखी। दूसरे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स की पोस्टिंग और पदोन्नति के जो तौर-तरीके हैं, वे भी बड़े ही पक्षपातपूर्ण रहे हैं, उनमें योग्यता का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। वहां का वातावरण इतना खराब रहा है कि कुछ लोगों को मजबूर किया गया कि वे यूनिवर्सिटी छोड़ कर चले जाएं, मैं इसके कारण में इस समय नहीं जाना चाहता हूं। वहां पर एक पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च सेन्टर भी बनना चाहिये, यह बात भी कही गयी जहां पर ३० करोड़ की स्कीम लागू हो सकती है। किन्तु प्रश्न यह है कि जहां पर इतनी ग्रान्ट का सदुपयोग नहीं किया जा सकता, उसका प्रबन्ध ठीक से नहीं किया जा सका वहां पर इतना बड़ा प्रबन्ध और इतने ग्रान्ट का प्रयोग ठीक से भली प्रकार होने की कैसे आशा की जा सकती है। यह तो मैंने बहुत संक्षेप में कुछ बातें कहीं हैं किन्तु जब इसकी ग्रान्ट आएगी तब मैं डिटेल में कहूंगा।

यह भी कहा गया कि आटोनामस बाडी के अधिकारों का यह हनन हो रहा है। उनको स्मरण होगा कि मैं भी आटोनामी का बड़ा हामी रहा हूं और उसी की आवाज उठाने के फलस्वरूप मेरा एक बार विश्वविद्यालय से रेस्टीकेशन भी हुआ था जब उनके नेतृत्व में सरकार बनी हुई थी। जब आटोनामी नहीं रहती है, सरकार ले लेती है, तो उसका सिलेबस कौन बनाता है? सरकार नहीं बनाती है, उसका सिलेबस इंडियन मेडिकल कौंसिल बनाती है, इसका निरीक्षण भी होता है और वह भी इंडियन कौंसिल ही करती है। इंडियन मेडिकल कौंसिल की तरफ से निर्देश होता

है तो इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुये जब सारे मेडिकल कालेजेज चलेंगे तो फिर इसमें भी उसी तरह कर दिया जाय। जो टीचिंग प्रोफेशन है उसमें विश्वविद्यालय का अन्तिम अधिकार होगा, उसमें किसी प्रकार का आक्षेप नहीं किया जायगा लेकिन विद्यार्थियों को अध्यापकों को जो असुरक्षा थी उसके बदले सुरक्षा उन्हें दी जायगी, पोलिटिक्स वैंडेलाइजेशन नहीं होगा, राजनीतिक आधार पर प्रोफेसरों का प्रोमोशन और अप्वाइन्टमेंट नहीं होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि गत बीस सालों में वहां कितने ही प्रतिभाश ली प्रोफेसर्स रहना ठीक नहीं समझते। उन्हें घुटन हो रही है और इसलिये हो रही है कि हम उन्हें जो सम्मान देना चाहिये था वह नहीं देते हैं। इसी को देखते हुये हमने यह फैसला किया है कि इस कालेज को इस आदरणीय सदन की आज्ञा से ले लिया जाय और मुझे विश्वास है कि इससे मेडिकल कालेज का, जनता का और इस सारे प्रदेश का लाभ होगा। मुझे आशा है कि इस सदन के माननीय सदस्य इसमें हमारी मदद करेंगे। और जब इसके लिये बिल आयेगा तो इसको शीघ्रातिशीघ्र पास करेंगे।

पांचवां कारण है कि हम सारे मेडिकल कालेजेज को एक सेंट्रल पूल में लाना चाहते हैं। केवल लखनऊ मेडिकल कालेज एक ऐसा कालेज है जो अलग था। इसके डाक्टर्स आज अमेरिका और विलायत जाना चाहते हैं। आज हमें दुःख है कि चाहे केन्द्रीय सरकार हो चाहे प्रान्तीय सरकार उनकी अदूरदर्शी नीति के कारण आज ५ हजार डाक्टर्स, प्रतिभाशाली लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं और हमारे प्रदेश में डाक्टरों की कमी है। मैंने ४ आदमियों से परसनली बात की और उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें नान-प्रैक्टिसिंग में न रखें। हमने एलान किया कि डाक्टरों के मामले में कोई सिफारिश नहीं सुनी जायगी। उन्हें एक साल तक पहाड़ी इलाकों में भेजा जायगा, २ साल तक उन्हें पी० ए० सी० और एस० पी० एफ० में भेजा जायगा, उन्हें देहातों में भी भेजा जायगा और १० साल या १० साल से अधिक के डाक्टरों को रीजनल हेडक्वार्टर्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर रखा जायगा और ५ साल से अधिक जिनको एक स्थान पर हो गया है उनका रोटेशन से ट्रांसफर किया जायगा। क्या ऐसा करना गलत है। यही हो रहा है। मान्यवर, आपको यह सुनकर खुशी होगी कि पिछले २० सालों में जिनकी बात नहीं सुनी गयी थी जो पिथौरागढ़ में पड़े थे उनको आज जस्टिस मिली है। यही मैं कहना चाहता हूं।

यह कहा गया कि यह बजट निगेटिव है। मैं जानना चाहता हूं कि पाजीटिव बजट क्या है। जो सबसे बड़ी बात हम करना चाहते हैं और जो पाजीटिव है वह यह है कि हम प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन देना चाहते हैं। मुझे मान्यवर, बड़ा दुख हुआ कि जब माननीय कमलापति त्रिपाठी जी एलेक्शन जीत कर आये तो उन्होंने चूंकि हमने बधाई दी इसलिये बधाई दी, लेकिन हमें जो निर्देश दिया वह मोटे लफ्जों में अखबारों में छपा कि यह गल्ला वसूली की स्कीम एंटी किसान है। मैं माननीय त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आपका फैसला गलत था तो हम नहीं जानते लेकिन २० मार्च सन् ६७ को आपने फैसला लिया था कि सवा ६ एकड़ तक काश्तकारों को छूट देने की बात की जाय। हमने यह समझा था और पढ़ा था कि पिछली जो गवर्नमेंट होती है उसने जो फैसला किया है उसको आने वाली सरकारें आनर करती हैं, उसमें माडीफिकेशन करती हैं और कर सकती हैं, हमने उसमें सुधार किया और लागू किया। माननीय चौधरी चरणसिंह ने क्रान्ति की और जो जनता कराह रही थी उसके लिये सुधार करके उस आपकी ही योजना को लागू कर दिया उसको सवा ६ एकड़ के स्थान पर सवा ८ एकड़ कर दिया और पूर्वी जिलों के लिये तो साढ़े १२ एकड़ कर दिया। मैं आज माननीय त्रिपाठी जी से बताना चाहता हूं कि आप जो यह कह रहे थे कि हम किधर जा रहे हैं तो मैं बताता हूं कि आप किधर जा रहे हैं। आज प्रदेश के लोगों को यह सोचना है कि प्रदेश के ८ करोड़ लोगों को कब तक दूसरे के अधीन रखना है। क्या हम इसी ८ किलो पर गुजर करते रहेंगे या कुछ और भी इससे अधिक देना है। प्रदेश के लोगों को यह फैसला देना होगा कि क्या हम सदा विदेशों के अधीन ही रहेंगे या अपने प्रदेश के अधीन रहेंगे। यदि हम यह फैसला नहीं कर सकते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो सकें तो हम कुछ भी देश के लिये नहीं कर सकते हैं।

[श्री प्रताप सिंह]

कहा गया कि इस सरकार की कोई नीति नहीं है। इस सरकार की यह विशुद्ध नीति है कि प्रदेश को एक क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाय, इस प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन दिया जाय। इस सरकार की यह नीति है कि जो प्रदेश के नागरिक हैं और जो आने वाली सन्तान है उनको आत्म-निर्भर बनाया जाय जो हमको पूज्य बापू ने बताया था और जिसके लिये बापू ने हमको पाठ पढ़ाया था और सिखाया था। मैं समझता हूं इससे अधिक सब से अच्छी नीति क्या हो सकती है और इससे प्रोग्रेसिव बजट क्या हो सकता है और खाद्य नीति क्या हो सकती है। हम प्रदेश के किसानों से यह कह रहे हैं तुम अमेरिका की सरकार के भरोसे पर न रहो। कांग्रेस सरकार ने यह सिखाया कि यहां की जनता को अमेरिका का किसान खिलायेगा और तुम पैदा मत करो और घर में बैठ कर आराम करो। अमेरिका खाने के लिये अनाज भेज देगा लेकिन चौधरी चरणसिंह की नेतृत्व में बनी हुई कैबिनेट यह कहती है कि अमेरिका से मांगने की हिम्मत मत करो कि अमेरिका हमको खिलायेगा। हिन्दुस्तान का नागरिक इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकता है कि वह इस तरह से सदा के लिये अपमानित होकर जीवन बिताता रहे। इस प्रदेश का वफादार सिपाही और राष्ट्र का नौजवान इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकता है। यहां के लोग यह बरदाश्त नहीं कर सकते हैं कि अमेरिका के अखबारों में यह निकले कि हिन्दुस्तान देश नंगा और भूखा देश है। पर उपदेश में बहुत लोग कुशल होते हैं लेकिन अपने यहां करके दिखायें तो मालूम हो।

इस सरकार के लिये यह प्रचार किया गया कि यह सरकार गिरने वाली है और हम इसको गिरायेंगे यह बात उधर के लोगों ने कही। इसके लिये चन्दा भी इकट्ठा किया जा रहा था। मैं किसी पर इसका लांछन नहीं लगाना चाहता हूं कि कानपुर में किस तरह से किसने इस तरह से प्रचार करके चन्दा वसूल किया लेकिन २० साल तक हमने उधर की सरकार को यहां पर बरदाश्त किया है तो हमको कुछ समय तो दीजिये। इस तरह के प्रचार से यह प्रदेश आगे नहीं जाने वाला है। आपको इस बात को सोचना है और इस पर चिन्तन करना है। इस प्रकार से अव्यवस्था का वातावरण प्रदश में पैदा किया जा रहा है। इस तरह की बातें उधर के लोग कर रहे हैं या इधर के लोग कर रहे हैं। अगर दूसरे पक्ष के लोग कर रहे हैं तो आज सदन उठने के पहले गुप्ता जी का यह एलान होना चाहिये कि उनकी तरफ से ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस सरकार को चलने दिया जाय और किसी तरह से गिरने गिराने का सवाल पैदा न किया जाय। आप यहां पर २० वर्ष तक रहे तो हम भी उसी तरह से रहना चाहते हैं और प्रदेश की जनता के लिये कुछ करना चाहते हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव के सम्बन्ध में यहां पर बहुत-सी बातें कही गईं। यह भी कहा गया कि यह सतरंगी सरकार है और इसकी कोई पालिसी नहीं है। हमने १९ सूत्री कार्यक्रम बनाया है जिसकी चर्चा गुप्ता जी ने भी यहां पर किया कि उस कार्यक्रम के आधार पर यह सरकार बनी थी और पुरानी सरकार गिरी थी और उसका कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। अगर प्रजातन्त्र की प्रणाली के अनुसार सरकार चलती है तो उसकी सरकारी पालिसी ५ साल के लिये होती है। ५ साल के अन्दर हम उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। हमारा भी यह विचार है और निश्चय है कि जल्दी से जल्दी उस कार्यक्रम को पूरा करें। जो समय बीता है २ महीने का हमने उस समय में कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। अगर हम ऐसा न करते तो १६ तारीख को हम यहां न होते। अभी चौधरी चरणसिंह जब मेरठ गये थे तो ४० हजार आदमियों से उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को क्या दे सकता हूं। उन्होंने कहा कि आप हमको पानी दीजिये और बीज दीजिये। यह जनता की आज मांग है। बुलन्द शहर के अन्दर एक जगह बहुत से लोगों के मकान गिराये गये। निर्माण मंत्री जब वहां पर जांच करने के लिये गये तो वहां पर पुलिस का जलूस निकाल दिया गया। यह तो सब कुछ करा के तैयार हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी कैबिनेट रहे या न रहे, यह सरकार रहे न रहे, लेकिन ८ करोड़ जनता के हितों का हनन हम नहीं होने देंगे। हमें कैबिनेट में बैठने का शौक नहीं है,

लेकिन ८ करोड़ जनता ने हमें आदेश दिया है कि यहां बैठ, ये लोग इस लायक नहीं हैं कि हमारे हितों की रक्षा कर सकें। तो उनके आदेश पर यहां बैठे हैं किसी की मरसी पर नहीं बैठे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि गुप्ता जी ने चुनाव के दौरान में, मैं यह नहीं कहता कि यह बात उनको नालिज में है या नहीं है, वह स्वयं स्पष्ट करेंगे, लेकिन उनके चुनाव के दौरान में गोविन्द सिंह मेहरा के मकान को आग लगा दी गयी और जल कर राख हो गया। गरम पानी के सप्लिस्ट कार्यकर्ता के पैरों में गोली मार दी गयी, वह अस्पताल में पड़ा हुआ है। अगर वह उनकी नीति में नहीं भी है तो भी उनके कार्यकर्ताओं ने किया, इस तरह से जनतंत्र नहीं चल सकता।

मैं अधिक नहीं कहना चाहता। जब तक उधर थे तब भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते थे। मैं तो सोच रहा था कि आपकी पार्टी की ओर से कहा जायगा कि किसी किसी विभाग में अच्छा काम हुआ है, लेकिन यह किसी एक ने भी नहीं कहा। आपने यही कहा कि जनसंघ, पी० एस० पी०, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं उनकी मिली जुली सरकार है। न तो इस बजट को पढ़ने की तकलीफ की और न अपनी पिछली बैलेंस शीट देखी। लेकिन फिर भी कोई भी अच्छा प्रस्ताव किसी तरफ से भी आयेगा, आपकी तरफ से आवेगा तो उसकी मेरिट पर हम जज करेंगे न कि किसी पक्षपात पर। इस आश्वासन के बाद मैं चन्द्रभानु गुप्त और उनके साथियों से कहना चाहता हूं कि वे इस नये मोड़ को आनर करें और हेमवतीनन्दन बहुगुणा और और नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश को स्वच्छ बनाने में हमारी मदद करें, आपकी इधर जरूरत है, उधर नहीं है, हम आपको आमंत्रित करते हैं।

श्री जी० एस० चौधरी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो हाउस में कहा गया था कि चीनी मिल वाले ब्लैक में चीनी बेचते हैं यह हाउस की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता।

(श्री गोविन्द सहाय का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य--

एक सदस्य को २० मिनट का जो समय दिया गया है उसे कम कर दिया जाय जिससे अधिक सदस्य बोल सकें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य बोलने को खड़े हो चुके हैं, इस सम्बन्ध में कोई आग्रह नहीं हो सकता।

***श्री गोविन्द सहाय** (जिला बिजनौर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बजट एक उस दर्पण के समान है जिसके जरिये किसी सरकार के ध्येय प्रोग्राम और आकांक्षाओं का पता चलता है। यह सरकार जो आयी है, कुछ विशेष परिस्थितियों में आयी है और इसके आने से इस प्रदेश की जनता में नयी आशा भी जगी है, इसलिये इसके बजट को मैं उसी पृष्ठभूमि में देखना चाहता हूं और मेरा खयाल है कि जिस मात्रा में इस सरकार से आशाएं लगी थीं उस मात्रा में बजट में उसकी झलक नहीं दिखायी देती, उससे मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई। आजकल के जमाने में चाहे उधर बैठने वाले सरकार में हों या उधर बैठने वाले हों कुछ प्रारम्भिक हालात हैं जिनके होने के बाद ही एक सरकार कुछ नतीजा दिखा सकती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सहाय]

पहली चीज जो किसी भी सरकार के लिए जरूरी है वह यह है कि वह किधर को जनता को ले जाना चाहती है, यानी जैसा समाज बनाना चाहती है उसको एक झलक लोगों के सामने होना जरूरी है। मुझे इस बात को देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बजट में कैसा समाज यह सरकार बनाना चाहती है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। यह आपके समाज को तरक्की के लिये जरूरी है, चाहे इधर के लोग करें या उधर के। एक आब्जेक्टिव जरूरी है कि ऐसा समाज हम बनाना चाहते हैं। दूसरे उस समाज को हासिल करने के लिये यह हमारा प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम को पूरा करने के लिये यह हमारी टीम है। और उस टीम में जो काम करेंगे, उसका बाहर की मशीन और अन्दर की दवाओं में मेल हो। अगर ये चारों चीजें जुड़ जाती हैं तो यह सरकार तरक्की की तरफ ले जायेगी। जहां तक इस सरकार का ताल्लुक है, उसमें इनमें दो विद्यमान थे और दो आखिरी चीजों में कमी होने के कारण संगठन और सरकार में मिनिस्ट्री और डिसीडेन्ट इस तरह के चक्कर की वजह से जितनी तरक्की होनी चाहिये उतनी नहीं हुई। मैं जानना चाहता था कि क्या सरकार ने मौलिक चीजों को करने की कोशिश की है जिस पर कि तरक्की निर्भर है। इस बजट में एक कोने से दूसरे कोने तक किस किस्म का नक्शा सरकार के सामने है, मेरी समझ में नहीं आया है। मैं तो आशा करता था कि इस टीम में चूंकि प्रतापसिंह जी और झारखंडे राय जी हैं तो अवश्य इस बजट में सोशलिज्म की झलक होगी। और सोशलिज्म इसीलिये खत्म होता है कि आप सरकार में आ गये हैं, तो कोई परस्पेक्टिव आप सामने नहीं रखते हैं। आप चाहें जितनी भी इनर्जी पैदा कर दें वह उसको सही दिशा नहीं होगी। मैं समझता हूं कि यह इस प्रकार एक लक्ष्यविहीन सरकार का लक्ष्य है।

दूसरे प्रोग्राम का जहां तक ताल्लुक है यह एक ऐसी सरकार का बजट है, ऐसी पार्टी का बजट है जिसने एक प्रोग्राम पास कराया है, सदन से पास कराया है, मैनिफेस्ट दूसरी चीज होती है, सदन की सेंक्शन दूसरी चीज होती है। सदन में आपने एक प्रोग्राम पर मोहर लगाई है जिससे आप निकलना चाहते हैं। यह ऐसी पार्टी की सरकार है जिसे उसने स्वीकार किया है। उसे अब आप पूरा नहीं करना चाहते हैं। इस तरह से आप में और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। आपकी पार्टी तो रेडिकलिज्म के लिये आई थी, प्रेगमैटिज्म के लिये नहीं। "वीकनेस आव योर प्लेसिंग इज नेवर योर डिफेन्स"। आपको हमसे हर बात में अच्छा होना चाहिये। इसी तरह से जिनका ख्याल है कि हम मिल रहे होंगे, हमारी ओर से तोड़ने की साजिश हो रही है, ये सब गलत है। हमारी कोई साजिश आपको गिराने की नहीं है। आपकी टीम जो है, एक टीम में अच्छे आदमी हो सकते थे। आप सब बहुत अच्छे आदमी हैं। मगर जैसे चार अच्छे डाक्टर्स होते हुए भी उनके डायग्नसिस में फर्क हो सकता है उसी तरह से आपकी टीम में भी विभिन्न आवाजें गूंजती हैं। कोई इर्रीगेशन में प्राईवेट सैक्टर की बात कहता है तो दूसरा शराब पर मुनाफे की बात, चौथा इक्स्पोर्ट की बात। तो इस तरह से पता चलता है कि यह एक टीम नहीं है। मैं तो नम्रता से कहूंगा कि यह तो मुझे अच्छा खासा एक सरकस दिखाई देता है जिसमें एक होशियार सर्कस मास्टर ने सब को बिठा रखा है। मैं एक बात के लिये बधाई दे सकता हूं कि उन्होंने विभिन्न लोगों को जो कहीं एकत्र बैठ नहीं सकते थे एक जगह पर होशियार सर्कस मास्टर की तरह से बिठा दिया है। यह कोई टीम नहीं है। मैं इस तरह से याद दिलाना चाहता हूं कि सब पार्टियों के रेजोल्यूशन हैं। जो मिनिस्ट्री में होंगे और जो बाहर होंगे उनमें मेलजोल की जरूरत नहीं है।

पार्टियों को अधिकार है कि वह सरकार की नीतियों की आलोचना करें। यही नीति कांग्रेस की भी थी कि आर्गेनाईजेशन गवर्नमेंट से मिल कर काम नहीं करता था जो ठीक नहीं था। यहां आपकी पार्टियों को अधिकार है कि वे मंत्रियों की आलोचना करें और मंत्री अपने स्थान पर बने रहें। यह रास्ता आप ही निभा सकते हैं। समझदार व्यक्ति नहीं निभा सकता और मेरा ख्याल है कि यह पोलीटिकल मोरेलिटी के खिलाफ है। यह मैं मानता हूं कि आपकी नीयत हमसे अच्छी है, आप में उमंग ज्यादा है मगर इतनी ही चीज काफी नहीं होती लेकिन इसके साथ

ही साथ एक मौलिक चीज और जरूरी है वह यह है कि प्राब्लम की डाइग्नेसिस के बाद उसके इलाज का प्रोग्राम बनाया जाना चाहिये। लेकिन उसको करने में आपके सामने कांग्रेस से ज्यादा दुश्वारियां हैं। कांग्रेस के चार में से दो इन्ग्रेडियेन्ट्स गड़बड़ थे और आपके चारों के चारों गड़बड़ हैं। अगर फिर भी आप कुछ कर पायें तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिये हम लोग आपके रास्ते में हायल नहीं होंगे।

बजट की चर्चा की गयी, यह बात सही है लेकिन बजट स्पीच जिन शब्दों से शुरू की गयी वे मुझे अच्छे नहीं लगे। कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर अपनी बजट स्पीच को दूसरी गवर्नमेंट की बुराई से शुरू नहीं करता। अगर आपका काम हमारी बुराई से ही चलता हो, उससे आपकी तरक्की होती हो तो आप सुबह शाम दोनों वक्त उसे करें हमें उसमें कोई एतराज न होगा। लेकिन यह ग्रेस की बात नहीं है। दूसरी बात उसमें यह कही गयी है कि हमारी प्लानिंग का जो तरीका था वह खराब था। मैं नेकनीयती से जानना चाहता हूं कि आपकी प्लानिंग का तरीका क्या है। अगर हमारी प्लानिंग दोषपूर्ण थी तो आपने उसकी किस चीज में तब्दीली की है लेकिन मैं देखता हूं कि हमारी प्लानिंग का जो स्ट्रक्चर था उसी से आपने काम चलाया है फिर हम में और आप में फर्क क्या हुआ? फर्क यही दिखायी पड़ता है कि हमारे स्ट्रक्चर में नीचे पैर और ऊपर को एक मुंह था किन्तु आपके स्टक्चर को देखने से मालूम होता है कि उसके पैर तो एक है लेकिन मुंह ७–८ हैं।

जब हम कन्टेन्ट्स आफ बजट को देखते हैं तो हमें उसकी वायस देखने को मिलती है। उसको देखने से पता चलता है कि हमारा केपीटल एक्सपेंडीचर का दायरा सिकुड़ा है, सोशल वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर, वोमेन वेलफेयर आदि का दायरा सिकुड़ा है। ट्रान्सपोर्ट में प्राइवेट इन्टरप्राइस की चर्चा की गयी है। मिनिस्टरों के द्वारा निजी क्षेत्र की चर्चा की गयी है, प्राइवेट कोलेबोरेशन से फर्टिलाइजर फैक्ट्री खोलने की चर्चा की गयी है। इस सबसे मालूम होता है कि आप सोशलिज्म और पब्लिक सेक्टर की ओर से कैपेटलिज्म और प्राइवेट सेक्टर की ओर बढ़े हैं। और इधर एम्प्लायमेंट की ओर से रिट्रेचमेंट की ओर बढ़े हैं। बजाय इसके कि और लोगों को रोजगार दिलाते और कुछ अधिक लोगों का रोजगार खत्म किया है। सोशलिज्म और वेलफेयर स्टेट की ओर से पुलिस स्टेट की ओर बढ़े हैं। जब पब्लिक सेक्टर में कमी हो तो मैं उसको कभी भी प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट नहीं मान सकता।

अब मैं इस बात पर आता हूं कि इस सरकार ने आकर किस स्पिरिट का प्रोजेक्शन किया। डाक्टर सम्पूर्णानन्द के बाद माननीय चन्द्रभानु गुप्ता यहां आये। उन्होंने छोटी गाड़ियों और छोटे मकानों की बात करके एक अपना प्रोजेक्शन देने की कोशिश की। एक कलेक्टर भी जब भी जाता नये जिले का चार्ज लेता है तो वह भी वहां पहुंचकर अपना एक व्यक्तिगत प्रोजेक्शन करता है। और इसी तरह से आपने भी किया। मैं जानना चाहता हूं कि आपका यह प्रोजेक्शन किस स्प्रिट का था। आपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एक पुलिस स्टेट का सा प्रोजेक्शन किया। पुलिस स्टेट वह होती है जो सत्ता के द्वारा मसलों को हल करना चाहती है और डेमोक्रेटिक राय को नजरअन्दाज करती है। कालागढ़ की इन्क्वायरी की मांग सब तरफ से की गई लेकिन उसको नहीं माना गया, उसको मानने में आपका कोई नुकसान नहीं था अगर आपका दामन साफ था तो आपको इन्क्वायरी से बचना नहीं चाहिये था। अगर कोई स्टेट अपने यहां के दलों और उसके जुजों की राय को नहीं मानती और इधर की भी राय को नहीं मानती तो वह एक डेमोक्रेटिक अप्रोच नहीं है।

इसके अलावा एक और दूसरी मिसाल भी मैं दे दूं कि अभी जो यहां प्रोवयोरमेंट की स्कीम लागू की गई तो पहले जब मुख्य मंत्री माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी थे उन्होंने उसके बारे में पहले अपोजीशन के लीडर्स से मशविरा किया, सबको बुलाया। यह एक डेमोक्रेटिक अप्रोच था। इतना बड़ा और व्यापक कदम था उसको उठाने से पहले यह जरूरी था कि कम से कम कर्टसी के नाते ही सही कि अपोजीशन के लीडर को बुलाया जाता लेकिन नहीं बुलाया गया। इससे पता चलता है कि आपकी अप्रोच डेमोक्रेटिक नहीं है। इसलिये मैं इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं

[श्री गोविन्द सहाय]

कहता। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट महज इधर-उधर से वोट तोड़ने से नहीं बनती और न हम इस तरह से डेमोक्रेटिक कहलाने का दावा कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो वह है जो रोजाना की जिन्दगी में प्रशासन को इस तरह से ढालती है कि उसमें लोगों की आकांक्षाओं, तमन्नाओं और आवाजों की झलक दिखाई दे, अगर जन आकांक्षाओं को नजरअन्दाज किया जायगा तो हम जनतन्त्र से दूर हटते जाते हैं। तीसरी मिसाल एक मैं और दे सकता हूं आज तक आ ने दुनिया में कहीं नहीं सुना होगा कि नामिनेशन एलेक्शन से पहले पहुंच जायं, कोआपरेटिव में ऐसा ही हुआ। यह हमने इस ग र्नमेंट में ी देखा कि नामिनेशन पहले हो गये। इससे क्या असर चुनाव पर पड़ता है। इससे मैं यह कहने पर मजबूर हूं और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है।

मुझे अफसोस है और कहना पड़ रहा है, अगर माननीय झारखंडे राय जी की बात मेरी समझ में ठीक आई तो उन्होंने कल कहा था कि इतिहास बदल रहा है और इतिहास के मोड़ को मानना चाहिये। उन्होंने हमें चेतावनी भी दी और कहा कि इतिहास बदल रहा है और कांग्रेस को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिये। इतिहास का जिक्र किया तो मैंने भी ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है अ र मैं चाहता हूं कि माननीय झारखंडे राय की बात को उसके वजन के साथ मंजूर करूं। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज तक अगर किसी ने इतिहास को गलत समझा है तो यह हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी है और उसने कम्युनिज्म के साथ ज्या ती की है। सन् ३९ में जब नमक सत्याग्रह हुआ उस वक्त, सन् ३१ में जब गांधी-लार्ड इरविन पैक्ट हुआ उस समय, सन् ३९ में जब लड़ाई हुई उस वक्त कहा कि सत्याग्रह करो और सन् ४२ में भी पीपुल्स वार की बात कही और कहा कि उसमें शामिल हो जाओ। मैं कम्युनिज्म को बड़ी आदर की निगाह से देखता हूं और मेरा ख्याल है कि कम्युनिज्म ने दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऊपर उठाया है लेकिन जो पालिसी यहां की कम्युनिस्ट पार्टी की रही है उससे देश का नुकसान ही हुआ है। आप वह गलती न करें कि जो हिटलर के आने से पहले जर्मनी को कम्युनिस्ट पार्टी ने की। उन्हीं की वजह से वहां फासिज्म ताकत बढ़ी और तरक्की करती चली गई। मैं कहता हूं कि फासिज्म और कम्युनिज्म के मेल में आप घाटे में रहेंगे। कांग्रेस बुनियादी तरीकों से आपके ज्यादा नजदीक है। हम प्लानिंग में विश्वास करते हैं, हम मौन-एलाइनमेन्ट में विश्वास करते हैं और समाजवाद में यकीन करते हैं। आपकी तरफ से माननीय सैटीन साहब की तरफ से लैक्चर दिए गये कि कांग्रेस का २० साला प्रशासन, भ्रष्ट प्रशासन हमको मिला है। आपने परसों तक हमारे साथ तालमेल रखा है। आप २० साल की बात न उठाइये, आपको महंगी पड़ेगी। कौन जानता है कि आपको अपनी नीति कल बदलनी पड़े। इसलिए बड़ी आवाज बुलन्द न कीजिए, हालात को समझने की कोशिश कीजिए। आपका यह कहना कि आप यहां पर जनता के फैसले से बैठे हैं, गलत है। यह भी कहना सही नहीं है कि जनता के फैसले से हम हारे हैं। उन्होंने हमारे खिलाफ कभी फैसला नहीं लिया है। यह तो महज आपका मैनिपुलेशन है जिसकी वजह से आप कामयाब हुए हैं। जनता ने जब फैसला लिया उस वक्त आप नहीं मिले पाये। आप मिल पाये तो केवल अपने मैनिपुलेशन के कारण ही मिल पाये। तो यह जो गवर्नमेंट बनी है यह कोई गवर्नमेंट नहीं है बल्कि यह बनी है विभिन्न लोगों के मैनिपुलेशन से, और खास डर की वजह से। तो हमें न पढ़ाइये कि इतिहास ने नया मोड़ लिया है। न इतिहास ने और न हम लोगों ने मोड़ लिया है बल्कि आप सब लोगों ने अपने उसूलों से मोड़ लिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह पोलिटिक्स आपस में न कीजिए।

(तालियां)

श्री ऊदल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सहाय जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय पंडित जवाहरलाल जी जो अपने को बड़े समाजवादी समझते थे उनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग से केरल में समझौता किया ग ा था। मैं जानना चाहता हूं इतिहास की दुहाई जो गोविन्द सहाय जी दे रहे हैं उसके बारे में इनकी क्या राय है।

श्री गोविन्द सहाय—

इस पर कभी अलग से सेमिनार हो सकता है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

मैं प्रार्थना करूंगा कि कृपया आप सुनें।

श्री गोविन्द सहाय—

मैं चाहता हूं कि पोलिटिक्स के नाम पर जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जिनकी बेसिक बातों में मतभेद है, उन्हें ज्यादा वफादारी की दिवालें नहीं खींचनी चाहिए।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मुझे २-३ मिनट और बोलने दीजिए ?

श्री अध्यक्ष—

अभी आप और २-३ मिनट बोल सकते हैं।

श्री गोविन्द सहाय—

मैं अधिक इस विषय पर नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि समाज में एक रिश्ता होता है। मां का रिश्ता होता है, भाई का रिश्ता होता है। रिश्ते के बिना समाजवाद बिल्कुल अस्तव्यस्त हो जायगा। ऐसे ही पोलिटिकल पार्टीज का रिश्ता होता है। अगर कांग्रेस ने कभी कोई गलती की हो तो जो हमारे देशभक्त हैं उनको शिकायत नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को हमसे अच्छा स्टैन्डर्ड पेश करना चाहिए। जन कांग्रेस के जनरल सेक्रटरी, श्री रामनारायण त्रिपाठी की एक स्पीच है जिन्होंने एक दिन हमारे मुख्य मन्त्री को जो काम्प्लीमेन्ट्स दिए हैं, मैं आज भी वह देने के लिए तैयार नहीं हूं। उन्होंने उनको काल मार्क्स, लेनिन और गांधी की श्रेणी में रखा, और दूसरे ही दिन उन्होंने उनको राक्षस की श्रेणी में कर दिया। आप जनता को इतना भोला मत समझिए, वह सब समझती है। हम लोग तो २० साल में बहुत कुछ तजुर्बा सीख चुके हैं। कोई बहुत बड़ी तमन्ना बाकी रह गयी हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज जो एक्सपेरीमेंट यहां की पोलीटिक्स में हुआ है, यह जो एस० वी० डी० बना है, यह सिर्फ एक विजिटिंग दल बन कर रह गया है, इस दूकानदार को पकड़ा, उसको पकड़ा। अगर इनको इन्स्पेक्टरों का मजमुआ कहा जाय तो ठीक ही होगा। इनको यह कान्शेसनेस ही नहीं है कि यह मिनिस्टर्स हैं। मिनिस्टर के काम करने का एक तरीका होता है। मैं तो चौधरी चरणसिंह साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सेवा की है और वह यह कि सारे विरोधी दलों को एक साथ लेकर बैठ गए हैं। और इसका अंजाम आपको बाद में देखने को मिलेगा। जो आस्था लोगों की आप में थी वह आप देखेंगे कि समाप्त हो चुकी है। अगर अब आप में भी आस्था नहीं जम पायी तो फिर देश डिक्टेटरशिप की तरफ जायगा और इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूशन आपका होगा।

माननीय झारखंडे राय जी ने आज एक स्टेट ट्रेडिंग का सुझाव दिया। मगर जहां वेस्टेड इन्टरेस्ट और रिवोल्यूशन दोनों एक साथ काम करेंगे वहां वेस्टेड इन्टरेस्ट जीतेगा या रिवोल्यूशन जीतेगा? आपको जरा इस पर सोचना होगा। माननीय प्रतापसिंह जी ने जो बात कही मुझे बड़ी खुशी है कि आज २० साल बाद जो लोग इधर बैठते थे उधर बैठने लगे और जो उधर बैठते थे इधर बैठने लगे। यह तो इस सिस्टम का कसूर है। मैं तो कहना चाहूंगा कि आपने भी कुछ कमी नहीं छोड़ी है। यह इस हुकूमत का ग्लेमर ही है कि हमारे विकल जी महाराज भी इधर कन्डीशन्ड में बैठने लगे। आज इस सरकार की हालत उसी भूखे व्यक्ति की तरह है जो भूख से पीड़ित होकर किसी हलवाई की दूकान के सामने खड़ा है, कभी जरा सी

[श्री गोविन्द सहाय]

कोई मिठाई खा ली, कभी कोई खा ली, और समझ में उसकी नहीं आ रहा है कि वह कौन सी मिठाई खाए। कांग्रेस हुकूमत हिकमत से काम करती थी, अंधाधुंध काम नहीं करती थी। अगर आप इस सरकार के पिछले तीन महीनों के टी० ए० बिल्स को देखेंगे तो पायेंगे कि तमाम पैसा घूमने फिरने में ही खर्च हुआ है। आप इतिहास की बात करते हैं। इतिहास केवल एक बात लिखेगा और वह यह कि गिरावट के चिन्ह कांग्रेस में २० साल हुकूमत करने के बाद आये वे सारे अवगुण आप में (सरकार) ढाई महीने में ही आ गए। आप सोचिए कि जब आप ताकत में आए थे उस वक्त कितनी गुडविल आपके साथ थी, और आज वह कितनी कम हो गयी है। लोकल बाडीज के चुनाव अभी आयेंगे, इलेक्शन होगा, आपको मालूम हो जायगा कि जनता का रुझान कितनी तेजी से आपके खिलाफ जा रहा है, उसे अगर रोक सकें तो रोकिए। हमारी फिक्र मत करो, अपनी फिक्र कम से कम इस बात की करो कि जो एक काम सौंपा गया है तो कुछ नतीजे दिखाओ।

करप्शन की बात की जाती है। यह एक सोशल मैलेडी है जिसको आप डरा धमका कर नहीं मिटा सकते हैं। मैं एक मिसाल आपको देता हूं। ६० हजार लोगों से आप ने गल्ला वसूल किया है। इस गल्ले की स्कीम पर आप रेफरेंडम ले लीजिये कि हर किसान को किन हालात के मातहत अपनी जान बचाने के लिए कितना देना पड़ा है। आप समझते हैं कि इस तरह से सरप्राइज चेकिंग कर के करप्शन दूर कर देंगे। यह एक एपेडेमिक है उसे आप आज तक दूर नहीं कर सके, और आप जो खुद एक करप्ट सर्कमस्टांसेज की उपज हैं जो बिल्कुल अपार्चुनिज्म की उपज हैं वह करप्शन दूर करेंगे? इसलिए इन बातों को छोड़ कर अब आप को एक मौका मिला है मिलकर के इस सरकार को चलायें और जो बातें आप ने कही हैं उस तरफ प्रदेश को ले जाने की कोशिश कीजिए। आप के हर प्रोग्रेसिव काम में हमारी सब की मदद आप के साथ होगी। आप को गिराने के लिए हमें कोई हिकमत नहीं करनी है, आप खुद अपने की कंट्रेडिक्शन्स से दुनिया की कोई ताकत आपको गिरे बगैर रोक नहीं सकती, यह इतिहास है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है जो दो दिनों से मैं प्रस्तुत बजट पर विवाद सुन रहा हूं और खास करके अपनी पुरानी कुर्सियों से जो भाषण मुझे सुनने को मिल रहे हैं दो दिनों से, नेता विरोधी दल सम्भवतः चले गए, पहले तो मेरी बात सुनते थे, मैं माननीय गोविन्द सहाय को बधाई देना चाहता हूं। एक ही बात का मुझे आज दर्द है जिसके लिए मैं आपका व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं क्योंकि आप मेरी ही कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कल परसों माननीय बहुगुणा जी बैठे हुए थे, तो वह मेरा दूसरा रूप ले रहे थे। मगर मुझे आप से यही शिकायत है कि जो सीख आज हमें आप दे रहे हैं, शिकायत नहीं है, वह सीख कभी गुप्ता सरकार, सुचेता सरकार को नहीं दिए। इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। मैंने पढ़ा था एक बार पुराने श्लोक हैं कि विधान की सभा में तो जाना ही नहीं चाहिए। अगर जाना जरूरी हो तो सच बोलना चाहिए। जो सभासद् विधान की सभा में जाकर सच नहीं बोलता है वह महा पापी है। तब भी जब मैंने कहा था तो नेता विरोधी दल मुख्य मन्त्री की जगह पर विद्यमान थे उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। आज वह सच्चाई की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के बारे में कुछ नहीं हुआ। बहुत सही बात कही। मेरी सरकार को पत्रकारों की मांग जरूर सुननी चाहिए। लेकिन जब कोई पत्रकार उग्रसेन की सही बात छापते थे तो गुप्ता जी का मोटा डंडा माननीय बनारसी दास जी ले कर फटा-फट पीटते थे। आज वह चले गए। उनकी बात तो पहले भी छपती थी, आज भी छपेगी, चाहे उनकी बात करें या न करें। आप सही सीख दो। मैं कहता हूं कि जो बात माननीय गोविन्द सहाय जी नेता विरोधी दल पर लागू है वह आप को भी लागू है। अपनी सरकार की नीतियों का समर्थन स्वयं करना यह हमारा फर्ज नहीं है। जनता स्वयं जान जाएगी, हम आदरणीय विधान सभा के सदस्य हैं। हमको जनता ने चुन कर भेजा

है। माननीय गोविन्द सहाय जी कुछ मुद्दों पर चुन कर आए हैं लेकिन वे उनके घोषणा-पत्र में नहीं थे, उग्रसेन के घोषणा-पत्र में थे।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर, अधिष्ठाता, डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, पीठासीन हुईं।)

आप यह कह कहते हैं कि मेरा वह घोषणा-पत्र कहां गया? उसके लिए हमने ३३ सूत्री कार्यक्रम बनाया और वह बाइबिल हो गयी। १९ सूत्री पर हमारी सरकार बनी और आपकी सरकार गिर गयी। यह सही है कि समाजवादी बुनियाद पर अभी इस सरकार ने कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किया। उनकी सरकार ने मिर्जापुर में १४ मुफ्त भोजनालय खोले और हमारी सरकार ने २८५। इसको हम समाजवादी कदम नहीं मानते। उनके मन्त्री ने बार-बार गला फाड़ कर यह कहा कि भूख से कोई मर ही नहीं सकता लेकिन हमारे खाद्य मन्त्री मिर्जापुर गए और कहा कि ३५ आदमी भूख से मर गए। हम इसको समाजवादी कदम नहीं कहते। केवल सही बात कहने की हमारी आदत है और उसे कहना चाहिए। हम अपनी जगह से दूर जायं तब गोविन्द सहाय जी शिकायत हो सकती है। बहुत सी शिकायतें उनकी जायज भी हो सकती हैं।

एक बात की बड़ी चर्चा हुई कि लोग उधर से इधर और इधर से उधर चले जाते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। नवलकिशोर जी उसके लिए बड़े दुखी हैं कि १८ आदमी उधर से इधर चले आए। गोविन्द सहाय जी आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे, उनके साथ कामराज जी बैठते थे, उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष इन्दिरा गांधी थीं। उसी समय अशोक मेहता और गेंदा सिंह कांग्रेस में चले गए। हम लोगों ने विधान सभा में सवाल उठाया। कोड आफ कंडक्ट पर सभी दलों के दस्तखत हैं कि एक आदमी इधर से उधर जाएगा तो हम नहीं लेंगे तो उस समय यह कोड आफ कंडक्ट कहां गया था? खैर, देर आयद दुरुस्त आयद। मैं गोविन्द सहाय जी को बतलाना चाहता हूं कि यह सवाल यहीं नहीं है। इंग्लैंड, कैनाडा और दूसरी जगहों में भी यह हुआ है और संयुक्त सरकारें वहां बनी हैं और आप इस संभावना को रूल आउट नहीं कर सकते।

माननीय चरणसिंह जी से प्रदेश की एक मांग थी। यह मांग नहीं थी कि चौधरी साहब मुख्य मन्त्री बनते। प्रतापसिंह अथवा झारखंडे राय मुख्य मन्त्री हो जाते लेकिन प्रदेश की उनसे एक मांग थी कि कांग्रेस हटाओ और देश बचाओ। अगर यह तालमेल कहीं पहले हो जाता तो जो आप १५० की तादाद में उधर बैठे नजर आते हैं वह केवल २५ अथवा ५० ही रह जाते। चौधरी साहब ने वही बात की क्योंकि वह अन्दर से बड़े घुट रहे थे। घुट न तो गोविन्द सहाय जी को भी बहुत हो रही है। कम्युनिस्ट पार्टी को रोज गाली देंगे और विद ले कर रूस फौरन चले जायेंगे। हमारे और उनके दो स्कूल चलते थे। फर्जी समाजवादी स्कूल गोविन्द सहाय जी चलाते थे और असली समाजवाद का स्कूल मेरा चलता था। मेरे यहां भी बहुत से मन्त्री पढ़ने आते थे। गुप्ता जी के पैरोकार नवलकिशोर और बनारसीदास अलबत्ता नहीं आते थे लेकिन हम दोनों की वार्ता लाबी में अवश्य हो जाया करती थी। कभी नहीं मिलते थे तो खयाल आता था कि कहीं खिसक तो नहीं गए गोविन्द सहाय जी जेड० ए० अहमद का पल्ला पकड़ कर। मगर आज मुझे उनसे भी शिकायत नहीं है क्योंकि मेरे तो कुछ निश्चित सिद्धांत हैं। बर्क ने एक जगह लिखा है कि जो लोग चुन कर आते हैं उनको अधिकार है कि विभिन्न समस्याओं पर विभिन्न रायें रखें। माननीय चौधरी चरणसिंह और उनके साथी पहले भी मन्त्रिमण्डल में थे। उनको और उनके साथियों को पूरा अख्तियार था कि जो भी कदम चाहते उठाते। जिस घुटन को माननीय गोविन्द सहाय नहीं तोड़ सके उसको चौधरी चरणसिंह ने तोड़ा इसलिए मैं उनकी तारीफ करता हूं। मैं अपने मुख्यमन्त्री के बहुत से विचारों का विरोधी हूं मगर यहां पर उन्होंने क्रान्तिकारी कदम उठाया। आखिर ३३ सूत्री कार्यक्रम में कौन चीज नहीं है। इसमें लगान हटाने की बात है, राज कर्मचारियों को समान वेतन, समान सुविधाएं देने की बात है, सभी बातें तो हैं। तो इस पर ज्यादा बहस न हो कि इधर चल आए या उधर चले गए।

[श्री उग्रसेन]

मैं तो कहता हूं कि आप सब उठ कर इधर चले आयें। हां, यह जरूर है कि कुछ हमारे साथी हैं जिनको हम लेने के लिए तैयार नहीं होंगे।

हमारे गोविन्द सहाय जी ने कहा और यह बात सही भी है कि हम लोग मिठाई की दुकान पर खड़े हैं, तमीज ही नहीं है कि कौन-सी मिठाई खाएं। बात उन्होंने सही कही कि २० वर्षों में सारी मिठाई तो ये लोग उड़ा ले गए। और यही नहीं, आपकी सरकार ने तो हमें इस हद तक पहुंचा दिया कि १९ साल के आपके राज्य में हमारे बच्चे मिठाई की दूकान पर खड़े मगर आपने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उनकी तरफ देखा है तो अब झारखंडेराय जी ने देखा, प्रतापसिंह जी ने देखा। १९ साल तक हमारे बच्चे मिठाई के लिए तरसते रहे और जब आपने मिठाई खा कर पत्ते फेंक दिए तो वे उसका दाना निकाल कर खाते रहे। हम आपको बताते हैं, हम आपको गुमराह नहीं कर सकते। आप हमारी बातों से नाराज न होइए। मैंने नवलकिशोर जी को सुना, बहुगुणा जी को सुना। आपका १९ वर्ष तक शासन रहा मगर किसी ने नहीं बताया कि मैंने क्या किया। योजनायें, यह आपके पाप का फल हैं माननीय राममूर्ति जी। इन्होंने विधान सभा में उत्तर दिया था। मैं बता दूं कि जब केन्द्रीय सरकार से उड़ीसा की सरकार ने योजना से २५ करोड़ रुपया ज्यादा ले लिया, पश्चिम बंगाल की सरकार ने १२ करोड़ रुपया ज्यादा ले लिया, टमिलनाड ने ५८ करोड़ रुपया ज्यादा ले लिया उस समय माननीय राममूर्ति की सरकार ने ३२ करोड़ रुपया कम लिया था। जरा आप लोग सुनिए। माननीय राममूर्ति जी ने कहा था कि यहां पहली योजना में २४ रुपए प्रति व्यक्ति खर्च हुआ वहां दूसरी जगह ४० रुपए प्रति व्यक्ति खर्च हुए। तीसरी योजना में जहां हमारे यहां ६८ रुपए एक आदमी पर खर्च हुए वहां दूसरी जगह ९३ रुपए प्रति व्यक्ति खर्च हुए। आपको चौधरी चरणसिंह ने मना नहीं किया था कि आप ज्यादा रुपया न लीजिए या हमारे माधवप्रसाद त्रिपाठी ने जो उस समय जनसंघ के नेता थे उन्होंने मना नहीं किया था। आपने समाजवाद की कहीं गुंजायश नहीं रखी। मैं पूछना चाहता हूं कि अवाड़ी का प्रस्ताव क्या हुआ ? स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल का एक प्रस्ताव था कि वेलफेयर स्टेट बनायेंगे। तो जितने आपके कांग्रेस के प्रस्ताव रहे उनके तदनुरूप आपने क्या किया। आपने प्रदेश को और गरीब बना दिया। दूसरी योजना में २९३ रुपए प्रति व्यक्ति की आय को घटा कर आपने २३६ रुपए कर दिए। आपने कौन योजनायें चलायीं। आप जिस समय सिंचाई मन्त्री थे तो आपने माता टीला बांध की योजना चलाई। रामगंगा बांध योजना ६८ करोड़ रुपए से बढ़कर ११० करोड़ की हो गई। छितौनी बांध की योजना में भी करोड़ों रुपए बढ़ गए। यह माननीय राममूर्ति जी की बात है। मेरा कमीशन कालागढ़ की जांच करने वाला है। इस बात को भी देखना है कि रामगंगा बांध योजना ६८ करोड़ की थी वह ११० करोड़ की कैसे हो गई ? राममूर्ति जी मैं तो देवरिया से आता हूं। हमारे यहां अनाज खाने को कहां मिलता था। बैल जो अनाज खाते थे उसके गोबर में से दाना बीन कर उसकी रोटी बनाकर लोग खाते थे। गेंदासिंह जी के इलाके में एक गेठिया की जहरीली जड़ होती है उसकी भी रोटी लोगों को नहीं मिल सकी। जब बहुत हल्ला किया तो गेंदासिंह जी ने कहा कि चूहा खाओ। एक पत्र मैंने उनको दिया था। यह सारी बातें आपके राज्य में हुईं। हमारा तो केवल अभी तीन महीने का ही राज्य हुआ है। उसको बुरा न कहिए। लेकिन उसका स्वागत कीजिए। वर्मा जी मेरे यहां गए तो कांग्रेसी लोग कूद गए। मैंने कहा कि कांग्रेसी राज्य में अगर हम लोग कूद जाते तो आप गोली मार देते। लेकिन हमारा मन्त्री मुस्करा रहा था।

आप छटनी की बात करते हैं कि छटनी नहीं होनी चाहिए। जब उनकी सरकार थी तब भी ये लोग पढ़ते नहीं थे और आज जब ये विपक्ष में हैं तब भी नहीं पढ़ते हैं। राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में मुख्य मन्त्री जी का एक पत्र छपा था कि सरकार अच्छी तरह से अनुभव करती है कि जहां छटनी होगी वहां अवश्य कठिनाइयां सामने आयेंगी। इसलिए सरकार विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है जिससे उनको कोई दूसरा कार्य दिया जा सके। राममूर्ति जी का विभाग है। जरा सुन लीजिए। छटनी और अचार के बारे में है। बड़े-बड़े

लोगों की बीबियां वहां जाती थीं और मिनिस्टरों की बीबी जाती थीं या नहीं इसका पता नहीं। शाम को हजरतगंज में सामान खरीदती थीं और चटनी अचार बनाकर राममूर्ति जी को खिलाती थीं। हमने इसको तोड़ दिया है तो क्या बुरा किया है? इसका बजट १४ लाख का था। हमें एक सज्जन ने रस पिलाया और पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं तो इसे गार्डन से मंगा लेता हूं। कहने का मतलब यह है कि सारे समाज में यह बात फैली हुई है। गोविन्द सहाय जी मांग करते हैं कि इसमें कोई समाजवादी दृष्टिकोण नहीं है। मैं मान सकता हूं कि इसमें खामियां हो सकती हैं। लेकिन हमारा दृष्टिकोण किस ने फेरा। मैं घोषणा-पत्र पढ़ा करता था जिसमें लिखा होता था कि हिन्दुस्तान में जब स्वराज्य होगा तो किसान मजदूर प्रजा का राज्य होगा। लेकिन इन २० सालों में कैसा राज्य बनाया है? क्या इस किसान मजदूर राज्य के मालिक माननीय गुप्ता जी हैं। हमारे लिए आप कहते हैं कि मन्त्री लोग बड़ा दौरा करते हैं। लेकिन इसको नहीं देखते हैं कि लखनऊ में एक मोतीलाल सोसाइटी है जिसमें टाटा मरसडीज कम्पनी है और उसमें डेढ़ करोड़ रुपया है। सारा रुपया कहां गया? इसको कोई देखने वाला नहीं है। हमारी सरकार की भी एक कमजोरी है कि क्रान्तिकारी कदम उठाने में यह हिचकती है। जैसे क्रिकेट में होता है पहले बाउन्डरी मारते हैं फिर ४/६ रन बनते हैं। इसी तरह से होना चाहिए। गलतियां होंगी लेकिन कोई कुछ नहीं कहेगा। सरकार को इधर काम करना चाहिए।

मैं दूसरी ओर आपका दिमाग ले जाना चाहता हूं। भ्रष्टाचार की बड़ी चर्चा हुई। भ्रष्टाचार यहां गोमती की कीचड़ को खत्म करने से खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार जमनोत्री और गंगोत्री में चला गया है। भ्रष्टाचार दिल्ली से, सेंटर से चल रहा है। बीस साल से वहां से बहता चला आ रहा है। एक सिंचाई मन्त्री के खिलाफ आरोप है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि हजार एकड़ का फार्म बना लिया, नौ लाख का तालाब बना लिया, डेढ़ सौ हरिजनों का फार्म अपने नाम कर लिया। हमारे मुख्य मन्त्री ने एक काम किया है। उसमें मेरी भी जांच समझते हों तो मेरी भी जांच हो। करवा लो। लेकिन भ्रष्टाचार किसी हालत में नहीं रहना चाहिये। हमने यह सरकार इसलिए नहीं बनाई है कि जिस रास्ते पर आप चलते रहें उसी पर चलते रहें। हमने सरकार इसलिये नहीं बनायी है कि कुर्सी को पकड़ कर बैठे रहें बल्कि इसलिए कि क्रान्तिकारी परिवर्तन लाएं। उसके लिए हम रास्ता बनाएं। हमारा दिमाग बिलकुल साफ है। जब तक हमारी सरकार उन क्रान्तिकारी परिवर्तनों को करने की और लगातार निर्भीक तरीके से आगे बढ़ती जायगी उसको कोई नहीं गिरा सकता। आप क्या गिराएंगे, आप क्रान्तिकारी परिवर्तन के आदी हैं नहीं। लिखा है आपकी किताब में जरूर। माननीय गोविन्द सहाय के लेखों और किताबों को पढ़ता रहा हूं।

राजकीय कर्मचारियों की बहुत सी बातें कही जाती हैं। गुप्ता जी ने बड़ी वकालत की। नवलकिशोर जी और गोविन्द सहाय जी ने भी कह दिया। ठीक है उनकी मांगें जायज हैं। मुख्य मन्त्री ने कह दिया कि जो रिट्रेंच किये जायेंगे उनको हम जगह देंगे। माननीया सुचेता कृपालानी जी ने मुझे एक दिन बुलाया था। उन्होंने कहा कि गुप्ता इन राज्य कर्मचारियों को मुझे हटाने के लिए भड़का रहे हैं। मैंने कहा कि आप डरिए नहीं, डटी रहिए। मैं नहीं कहता कि उनकी मांग नाजायज है। मजदूरों की मांग नाजायज नहीं होती है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी कहूंगा कि छोड़िए शुक्ल वगैरह को। करने दीजिए उनको यूनियन। हम भी यूनियन चलाते हैं। हमारे नेताओं ने जो अपील की थी उसमें उपेन के भी दस्तखत हैं। हमने उनकी हड़ताल वापस करने के लिये जब लिख कर दिया तो उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किये। मैं नहीं कहता कि वह बेईमान हैं। उनको अनुभव नहीं है। नये मुसलमान ज्यादा प्याज खाने लग गये थे। उन्हीं में रोडवेज और कालागढ़ के भी मजदूर आते हैं। कालागढ़ की घटना हुई। कुछ यूनियन के लोगों की नासमझी से ऐसा मामला हो गया। कालागढ़ के मजदूरों के साथ हमारी पूरी-पूरी हमदर्दी है। हमारे मंत्री लोग जाने वाले हैं। वह न्याय करेंगे।

[श्री उग्रसेन]

मालगुजारी और लगान के बारे में बिलकुल स्पष्ट चाहता हूं कि हमारे संविद ने एक कार्यक्रम रखा है भू-राजस्व की समाप्ति। आपने क्या रखा? केवल एक प्रस्ताव पास किया मुजफ्फरनगर में कि सवा छः एकड़ तक लगान हटाना चाहिए, राजस्थान सरकार ने पास कर दिया लेकिन इन्होंने नहीं किया। हमने जब चार आने वाले सरचार्ज को हटाने की बात की तो सदन से उठा कर हमें फेंक दिया गया, भूमिभवन कर को हटाने की बात की तो हमें यहां से उठा कर फेंक दिया गया, जब कि हमारी सरकार ने आते ही भूमि भवन कर को समाप्त कर दिया।

श्री चन्द्रदेव (जिला देवरिया)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब बजट में मालगुजारी की माफी के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो क्या माननीय उग्रसेन जी उसके बारे में यहां बोल सकते हैं?

श्री उग्रसेन---

मान्यवर, अभी मैं उसी के बारे में कहने जा रहा था तब तक उनके पेट में बात पची नहीं और वे खड़े हो गये। मालगुजारी का प्रश्न एक गम्भीर प्रश्न है और उसके बारे में हम लोग मंत्रिमंडल से और माननीय मुख्य मंत्री जी से समय समय पर कहते रहते हैं कि कम से कम सवा ६ एकड़ तक का लगान जरूर माफ करें। आप कहते हैं कि बजट में इसका कोई इन्तजाम नहीं है, मैं कहता हूं कि जहां चाह है वहां राह है। सरकार जब कोई विधेयक लाना चाहे ला सकती है और किसी भी समय किसी चीज का एलान कर सकती है। क्या जब एलान करना होगा तो सरकार को इसके लिये जगह कोई नहीं मिलेगी? मैं कहता हूं कि मालगुजारी के प्रश्न पर हम लोग आपस में बातचीत करते हैं।

अन्त में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। सिंचाई के सम्बन्ध में तो मैंने कह ही दिया। अब मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में एक ही लाइन में कह दूं, माननीय गोविन्द सहाय जी सुनते जाइये। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी भी इसे सुन लें कि सन् १९३८ में कांग्रेस की पंत सरकार ने फैसला किया कि इस मेडिकल कालेज को सरकार अपने हाथ में ले ले। इसके बाद ४२ का आन्दोलन हुआ और सन् १९४६ में गुप्ता जी आ गये और उन्होंने मेडिकल कालेज में अपने मामा के मामा, फूफा के फूफा और नाना के नाना को भरना शुरू कर दिया और इस तरह भाई भतीजावाद को खूब बढ़ावा मिला।

एक बात कही गयी कि उग्रसेन को ही सब से बड़ा दर्द है। मैंने तो कोई कुर्बानी की नहीं, आप का झंडा उठाते रहे, अपना गुरु कमलापति के भाषण के लिये रोज पोस्टर चिपकाते रहे। सन् १९४२ का आन्दोलन हुआ और अंग्रेज गये और जब प्रदेश की जनता ने प्रदेश का सारा भार आपके ऊपर सौंप दिया तब क्या हो गया। वही गोलीकांड, बांदा, गोलीकांड, वही भूखमरी, वही पापाचार, वही अनाचार। अब मैं एक शेर पढ़ कर अपनी बात समाप्त करता हूं---
"अगर तूफां डुबो देता तो इतना गम नहीं होता, किनारे आके डूबा हूं, किनारे बेवफा निकले"
यहां केवल भाषण करने से और लफ्फाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है श्री गोविन्द सहाय जी। इन शब्दों के साथ में माननीय वित्त मंत्री जी के बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्द सहाय---

माननीया अधिष्ठाता महोदया, माननीय उग्रसेन जी का मैं आभारी हूं कि मेरे भाषण का इतना असर उनके ऊपर पड़ा।

*श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

माननीया अधिष्ठाता महोदया, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं इस मौजूदा बजट का समर्थन नहीं कर सकता हूं। उसका कारण यह है कि मौजूदा बजट का यदि ध्यान से अध्ययन किया जाय और समझा जाय तो मेरी राय में यह प्रतिक्रियावादी बजट है। यह बजट प्रदेश को पीछे ले जाने वाला बजट है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि यह बजट जो है वह एक समाजवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किन्तु इस बजट में दरवाजे की बात कौन कहे, खिड़कियां भी नहीं खोली गयी हैं मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि इस दरवाजे और खिड़कियों के बन्द कमरे में समाजवाद का गला घुंट रहा है और जान ऐसा भी पड़ता है कि वित्त मंत्री महोदय ने केवल मात्र इस बजट को पढ़ लिया है और इस बजट के साथ उन की कोई भावनाएं नहीं हैं। आप देखेंगे कि बड़ा जोर दिया गया है दो दिन की बहस में कि इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। मेरे समाजवादी मित्र जो उधर बैठे हुये हैं वह इस बात की गवाही देंगे कि एक समाजवादी समाज बनाने के लिये यह आवश्यक होता है कि नये कर लगाये जाएं। उसमें केवल प्रश्न एक यह रहता है कि इस नये कर की व्यवस्था किस के ऊपर की जाए। नये कर उन लोगों पर लगाए जाएं जिनकी आमदनी या पूंजी उनकी आवश्यकता से ज्यादा है, ऐसे लोगों पर नये कर लगाकर उस कर की आमदनी से उस वर्ग को, समाज के उस हिस्से को राहत पहुंचाई जाए जो आज तकलीफों से घिरा हुआ है, बेदर्दी से जकड़ा हुआ है और आर्तनाद कर रहा है। तो इस बात का दावा जो उधर के हमारे मित्र करते हैं कि यह बजट इसलिये सुन्दर है कि इसमें कोई नया कर नहीं है, थोथा दावा है। तो समाजवादी समाज की व्यवस्था के लिये विद्वानों का यह मत है और उस मत में मेरी भी आस्था है कि देश और प्रदेश का कल्याण तभी सम्भव है जब यहां पर एक स्वस्थ समाज की रचना हो तो इस सरकार द्वारा इस प्रदेश के इस बजट में बड़ों को छोड़ा गया है, बड़ों पर कर न लगा कर उनकी असीमित आमदनी और अथाह पूंजी की तरफ से आंखें मूंद ली गयी हैं और गरीबों का हित करने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि उधर के भाई जो पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक हैं उनके दबाव से यह बातें इस सरकार से हो रही हैं और इसका नतीजा क्या होगा कि अब आप नये कर उन लोगों से नहीं वसूल करेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि आपको खर्चे में कमी करनी पड़ेगी।

मुझे तकलीफ हुई कि कल एक प्रगतिशील विचारधारा के हमारे मित्र जो उधर से खड़े हुये थे उन्होंने कहा कि यदि छंटनी न की जाए तो फिर खर्चा कैसे चलाया जाए। यह स्पष्ट है कि जब आप आमदनी नहीं करेंगे तो आप छंटनी करेंगे। छंटनी किसकी करेंगे, जिनको काम मिला हुआ है, नौकरी करते हैं। नौकरी कौन करता है, जिनको काम करने की जरूरत होती है, जिसको अपनी रोटी के लिये बाल बच्चों की रोटी के लिये नौकरी करना आवश्यक होता है,। एक समाजवादी व्यवस्था में देश और प्रदेश के नागरिकों का अधिकार होता है कि वे रोटी और रोजी मांगें और सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह उसे रोजी दे और रोटी उपलब्ध करे और यह सरकार को देना पड़ता है। किन्तु इसके विपरीत पूंजीवादी व्यवस्था में यह होता है कि जब चाहे सरकार रोजी-रोटी दे और जब चाहे छीन ले। और इस परिभाषा के अन्तर्गत आप इस बजट को कसें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह सरकार चूंकि पूंजीवादी व्यवस्था की पोषक है इसलिये जब चाहे मनमाने ढंग से वह किसी की रोटी रोजी छीन लेना चाहते है और इस पर इसे गर्व भी है।

अभी हमारे उपनेता जी ने कहा कि हमें मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि लोग जो छांटे जाएंगे उनको नौकरी में लगा लिया जाएगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर आप उनको रोजी देने वाले हैं तो आज उनको आप क्यों निकाल रहे हैं। इस प्रकार की जो दया और ऐहसान की भावना आप उनके सामने दिखलाना चाहते हैं उससे समाजवादी समाज की रचना नहीं हो सकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

इस बजट में माननीय उग्रसेन जी ने बड़ी कृपा करके शहादत की कि अलाभकर जोतों की मालगुजारी माफ होगी। वर्षों से उनका गला फट गया इस बात का नारा लगाते हुए कि अलाभकर जोतों से लगान माफ हो आज जब कि उनको भगवान ने अवसर दिया कि अपनी मंजूरी तब देते जब लगान माफ करने के लिए सरकार राजी होती तब सरकार बनाने देते। लेकिन जब वह वक्त आया तब आप हिम्मत हार गये और आपने अपनी हिम्मत का कोई प्रदर्शन नहीं किया बल्कि दूसरे वह दोस्त जो गला फाड़ फाड़ भूमि भवन कर के बारे में कहते रहे उन्होंने अपना अंदर का पैर जमा दिया। हमने खुद भी ६७ में अपने घोषणा मैनिफैस्टो में इस बात का एलान किया था कि अलाभकर जोतों को मालगुजारी माफ हो। अगर हमारे समाजवादी दोस्तों ने हिम्मत दिखाई होती तो हम समझते कि चलिये हम सफल हो गये। आज इस प्रकार की भावना फैल रही है कि हम जो कुछ भी कहेंगे आप उसका उलटा करने लगेंगे जैसा कल ही पंडित चतुर्भुज जी शर्मा कह रहे थे कि हमने कहा कि लगान माफ करो तो आप कहने लगे कि माफी नहीं करेंगे।

इसके अतिरिक्त माननीय झारखण्डेराय जी से मैं बड़ी आशा रखता था कि वे साम्यवादी होने के नाते कुछ क्रान्तिकारी कदम उठावेंगे। पानी पी पी कर वे पहले अमेरिका को गाली दिया करते थे लेकिन मंत्रिमंडल में आने के बाद अब वे बजट के उस अंश को नहीं पढ़ते जिसमें यह लिखा है कि अमेरिका के सहयोग से लगभग ३६ करोड़ की पूंजी की लागत से हम निजी क्षेत्र में रासायनिक खाद का एक संयंत्र स्थापित करने की सोच रहे हैं। जैसा माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि इस भारत के साम्यवादी कब क्या कर सकते हैं इसका पता किस को नहीं होता। सरकार में आने के बाद अमेरिका के विरोधी अमेरिका की मदद से निजी क्षेत्र में ३६ करोड़ की पूंजी से उर्वरक का संयंत्र लगाने के पक्ष में हो गये। मैं यह भी सोचता हूं कि दो ढाई महीनों में झारखंडे राय की अन्तरात्मा ने इतनी उन्नति की है तो इसके लिये उनके पास मास्को से बधाई का पत्र दो चार दिनों में जरूर आता होगा। माननीय झारखंडे राय ने उस सरकार से हाथ मिलाया है जिस सरकार में ग्रामीण जनशक्ति योजना काम कर रही है जो अमेरिका के पैसों और आदमियों से चलाई जा रही है। इसमें दो राय नहीं हैं कि पूंजी लगा कर अमेरिका के लोग अपने विचारों को और इस देश को ले जाने की कोशिश करते हैं। माननीय झारखण्डे राय जी जिस सरकार के सदस्य हैं उसी में अमेरिका की पूंजी से निजी क्षेत्र में वह भी एक संयंत्र लगाया जावेगा। वे उसी सरकार के केबिनेट के सम्मानित सदस्य हैं आज भी जहां आर० एम० सी० की योजना चल रही है। तो गोविन्द सहाय जी की बात सही जान पड़ती है कि इस प्रदेश के साम्यवादी जो हैं वह कब किधर करवट लेगा इसका ठिकाना नहीं है। इसके अतिरिक्त इसको क्रान्तिकारी बजट कहा गया। मैं समझता हूं कि उग्रसेन जी इस बात को याद करेंगे कि आप वही सब बातें कह रहे हैं जो २० वर्ष हम लोगों की ओर से उधर से कहा जाता था और उसी तरह से काम कर रहे हैं। अगर वह खराब रास्ता था तो आप उस को ही पकड़े हुये हैं। कालागढ़ में एक भी लाठी चार्ज नहीं हुआ यह वही जवाब है जो हम २० वर्ष तक उधर से देते रहे हैं। जितने फोर्स की जरूरत थी उतना ही इस्तेमाल किया गया। इसी तरह के जवाब दिये जाते थे। ११६ आदमियों के सिर फोड़ दिये गये, ८४ आदमियों के फ्रैक्चर हो गये तब भी कहा गया कि जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया गया। यही शब्द अंग्रेज भी इस्तेमाल करता था लेकिन यह साम्यवाद और समाजवाद से सम्बन्धित सरकार भी उन शब्दों का ही प्रयोग कर रही है। हम आप से यह निवेदन करेंगे कि जो रास्ता आप गलत समझते थे उसी रास्ते पर मत चलिये।

आज गल्ला वसूली की योजना को ले लीजिये। कल बड़े जोर के साथ मन्त्री मंगलदेव जी विशारद गल्ला वसूली पर बोले थे। मंगलदेव जी विशारद जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे तो उनकी भाषा और थी और उनका काम भी दूसरा था लेकिन आज मंगलदेव

जी विशारद की भाषा बदल गई। पता नहीं कि इसमें कुर्सी का दोष है कि उस पर बैठते ही भाषा भी उनकी बदल जाती है। आपने फरमाया कि हमने ८। एकड़ वालों से गल्ला लेना माफ कर दिया है। सब अफसरों की रिपोर्ट है कि मामला सही रूप में चल रहा है। अफसरों की रिपोर्ट क्या बतलाती थी इसका तल्ख तजुर्बा हम लोगों को भी है। कल वह मन्त्री जब बोलकर गैलरी में जा रहे थे तो मैं भी उस समय पानी पीने के लिये जा रहा था। उसी समय एक अफसर आये और उन्होंने उनको मुबारकबाद दिया कि आप बहुत अच्छा बोले। मुझे याद आया कि इस तरह की बात हमने भी अपने मन्त्रियों के लिये एक बार सुनी थी। इन्होंने भी वही रास्ता पकड़ा है। वह बड़े प्रसन्न हुये कि हमारे अफसर ने हमारी पीठ ठोक दी। मंत्री जी ने बतलाया कि गल्ला वसूली ठीक रूप से हो रही है। मैं उग्रसेन जी से पूछना चाहता हूं कि ८। एकड़ की बात कौन कहे एक बिस्वा का भी छूट नहीं है। एक ि स्वे के काश्तकार से भी गल्ला वसूली की जाती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह से गल्ला वसूली हो रही है वह अन्याय के साथ हो रही है। सरकारी आदमी बड़ा होशियार होता है। उन्होंने २० वर्ष हम को भी चरका दिया है। वह समझते हैं कि चरणसिंह जी बड़े सख्त आदमी हैं जो कोटा उनके लिये रखा गया है वह वसूल करना जरूरी है। उसको सहारा मिल गया उस क्लाज का जिसमें कहा गया है कि जो खुद देना चाहे वह भी बेच सकता है। वह हिस्सा उस पर लागू कर दिया गया। बाकी सब छोड़ दिया गया। आज क्या हो रहा है? उग्रसेन जी मैं इस बात के लिये चेलेंज करता हूं आप चाहे जिस जिले में चलिये और देखिये। चकबन्दी के आदमी, तहसील के आदमी, लेखपाल, एस० डी० ओ० हरएक के दरवाजे पर जाकर ५, १०, ३, ४ किलो अनाज लेता है और ५, ४ किलो वसूल कर के एक आदमी के नाम वह रसीद काटता है। रसीद काटने के बाद उसी को कहा जाता है कि हम बता देते और वह ४ किलो ३ किलो और ५ किलो जो देने वाला आदमी है वह दो चार दिन दौड़ता है, फिर चुप-चाप अपने घर बैठ जाता है और जिस आदमी के नाम रसीद काटते हैं वह आदमी जितना गल्ला ले रहा है, उसका दाम कुछ खुद रख लेता है और बाकी रसीद काटने वालों के हवाले होता है।

आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उसकी नींव पर यह सरकार बनी हुई है, उसको वह क्या हटायगी? समाज में एक व्यक्ति का भ्रष्टाचारी होना खराब बात है, लेकिन जहां समूह का समूह भ्रष्टाचार में फंस जाय तो बड़ी गड़बड़ होती है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, सामाजिक, आर्थिक भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की बहुत सी परिभाषाएं हैं। एक यह है कि जिस वक्त आपने गल्ला वसूली की बात कही तो चारों तरफ एलान हो गया, हजारों लोग तहसील दौड़े। एलान हुआ कि तुम अपना इन्तखाब ले आओ कि तुम्हारे पास सवा आठ एकड़ से कम है। आ मी दौड़े इन्तखाब लेने, उसके दाम ज्यादा हो गये। आप विश्वास करें कि एक एक इन्तखाब खसरा खतौनी के लिए २०–२५ रुपया देने पड़े आपके ही राज्य में। हमारे में जो कुछ हुआ सो हुआ। इसके बाद जिस तरह से लोगों ने कमी करवायी है अपने कोटे को वे जानते हैं।

इस बजट को मैं प्रतिक्रियावादी बजट इसलिए भी कहता हूं कि इसमें साहित्यकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह सही है कि पहले भी उनका शोषण होता था, लेकिन आज समाजवाद की समर्थक सरकार जब आयी है तो लेखकों, साहित्यकारों के लिए कोई योजना रखनी चाहिए थी ताकि उनका शोषण न हो सके। मैं कहता हूं अपने प्रगतिशील साथियों से जो उधर बैठे हुए हैं कि वह दीवार पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ें। मैंने अपने एक जनसंघी मित्र का एक लेख एक जगह पढ़ा था, पत्र था। उसमें उन्होंने लिखा था कि सन् १९५२ में हम प्रचार के लिए आये थे, सन् १९५७ में प्रतिनिधित्व के लिये गये थे सन् १९६२ में विरोधी दल होने के लिए गये और सन् १९६७ में कांग्रेस को हटाने के लिए गये। सन् १९७२ में अगले चुनाव में हम प्रदेश और देश में शासन करेंगे। इसका आप पता कर लीजियेगा, यह उनका कहना है। इसलिए हम जिस समाजवाद की कल्पना कर रहे थे कहीं वह धूमिल न हो जाय आपके द्वारा।

मुझे इस बजट के समर्थन करने में बड़ा दुःख हो रहा है। उधर से बजट में और भाषणों में भी २० वर्ष की कांग्रेस के कुकृत्यों की बात कही गयी है। बनारस के एक नौजवान समाजवादी

[श्री रामनरेश शुक्ल]

चन्द्रशेखर जी तो जैसे कसम खाए हुए हैं कांग्रेस को गाली देने की। जिन परिस्थितियों में वह चुन कर आये हैं वह भी वे जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन मैं अपने माननीय मुख्य मन्त्री जी से जिनका मैं सदैव आदर करता रहा हूं और आज भी करता हूं उनसे कहना चाहता हूं, वैसे मुझे हक नहीं है कहने का कि २० वर्ष तक आप नेता थे, अग्रणीय नेताओं में थे और हम सिपाही थे आपके। आप सरकार में थे, हम तो सरकार के बाहर थे, आपकी चिट्ठी ले जाया करते थे। आज आप के सहयोगी कहते हैं कि २० वर्ष के कांग्रेस के कुकृत्यों का पहला अध्याय को अन्त हुआ तो मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या आप को धक्का नहीं लगता इससे? आपका आत्म-सम्मान, स्वाभिमान क्या जागता नहीं है? एक डाकू होता है उसके गृह पर कोई हमला करता है तो उसका भी आत्मसम्मान जाग जाता है। एक परिवार पर हमला होता है तो उसके सदस्य का भी आत्मसम्मान जाग जाता है तो क्या आपको चोट नहीं लगती है? मैं उपदेश देने के लिए या भर्त्सना करने के लिए नहीं कहता। अगर चोट लगती है तो क्या आशा करूं कि आप अंगड़ाई लेंगे और अंगड़ाई लेने के बाद ऐसी बात कहने वाले जो लोग हैं वह अपनी उसी जगह पर पहुंच जायंगे जहां वे थे?

श्री रामनरेश पांडेय (जिला देवरिया)---

अधिष्ठात्री महोदया, इसके पहले कि कुछ कहूं, मैं आपके प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं। हमने बड़े गौर से प्रतिपक्ष के और अपनी सरकार के लोगों के बजट भाषणों को सुना। बजट को भी हमने पढ़ा है, देखा है और समझने की कोशिश भी की है। जब से नयी सरकार बनी, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि उसने ऐसे कदम उठाये जो जनता को हर तरह से राहत देने वाले थे और खास तौर से जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां खुशी की लहर दौड़ी। लेकिन वस्तुस्थिति जब सामने आने लगी तो इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि सरकार के बदलने के बाद जिस बात को लेकर लोगों में खुशी आयी थी उसमें जब एक एक करके तकलीफें नजर आने लगीं तो मन में कुछ गिरावटें भी हुईं। यद्यपि कांग्रेस वालों ने यह कहा कि यह बजट प्रतिक्रियावादी है, खोखला है, इसके अन्दर कोई खास दिशा नहीं है, लेकिन मैं तो इसे मानता नहीं। इसको पढ़ने के बाद लगा कि प्लान है, निश्चित उद्देश्य है और निश्चित दिशा की तरह इसका संकेत भी है। इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि यह प्रगतिशील बजट है, गरीबों को राहत देने वाला है लेकिन इसमें ऐसे अवसर भी मौजूद हैं जिनको देख कर घोर निराशा हुई। मैं पूर्वी जिलों के देवरिया जनपद से आता हूं, वहां पानी की कमी के कारण, ट्यूबवेलों की कमी के कारण, प्राइवेट सेक्टर के अन्दर बहुत कम कुएं होने के कारण, गंडक नदी से जो नहर निकल रही है उससे जितना पानी मिलने की आशा थी उसमें कमी होने के कारण सिंचाई की बड़ी खराब स्थिति है। हमने इस बात को भी इस बजट के अन्दर देखने की कोशिश की कि वहां के लिए इसमें विशेष व्यवस्था होगी, वह जूट के कारखाने के लिए, अन्य उद्योगों के लिए कोई व्यवस्था होगी, लेकिन हमें बड़ी निराशा हुई। वहां के लिए मेडिकल फैसिलिटीज की तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया। इस ओर सरकार को पर्याप्त ध्यान देना चाहिये। सरकार का जितना ध्यान इस ओर जाना चाहिये था वह नहीं गया है।

लगान माफी की बात कही गयी। जहां तक लगान माफी का प्रश्न है मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय हो नहीं हो सकतीं कि लगान माफ होना चाहिये। अगर सरकार अपनी कुछ आर्थिक दिक्कतों के कारण ६-७ एकड़ तक लगान माफ नहीं कर सकती थी तो उसे कम से कम एक दो एकड़ तक का ही लगान माफ करके उसकी घोषणा बजट में करना चाहिये थी और नहीं तो यह लिखना चाहिये था कि हम इस पर भी विचार कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता---

आप का भाषण समझ में बिलकुल नहीं आ रहा है, आप कृपया माइक से कुछ दूर हट कर बोलें।

श्री रामनरेश पांडेय---

मैं यह कह रहा था कि लगान माफी की ओर भी इस बजट में कुछ संकेत होना चाहिये था । अब कुछ और बातें हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं

अनेक सदस्य---

माननीय सदस्य का भाषण समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री रामनरेश पांडेय---

मैं शिक्षा के विषय में भी कहना चाहता हूं । शिक्षा हमारे समाज और देश की रीढ़ होती है । इस बजट में शिक्षा और शिक्षकों के विषय में कुछ नहीं कहा गया है । मुझे दुख है कि इस ओर बजट में निराशा दिखाई पड़ती है ।

श्री अधिष्ठाता---

आपका भाषण समझ में नहीं आ रहा है । आप कृपया दूसरे माइक का प्रयोग करके देखें ।

श्री रामनरेश पांडेय---

मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि माध्यमिक शिक्षकों की हालत को सुधारने के लिये कदम उठाने चाहिये थे । प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक तो उपेक्षित हैं ही । बजट में इनके विषय में कुछ न देखकर हमने अपने को निराशा की स्थिति में पाया है । मैं यहां एक बात की तारीफ किये बगैर नहीं रह सकता कि हमारे क्षेत्र से ही छपरा जिला शुरू होता है । हमारे यहां पर बार्डर सील हो गया है और कोई गल्ला बाहर नहीं जाने पा रहा है । यही कांग्रेस वाले जब शासन में थे, तो यही बार्डर का इलाका अष्टाचार का इलाका बना हुआ था और दिन दहाड़े ब्लैक में गल्ला बाहर जाता था ।

इसके अतिरिक्त भी प्रशासन के सामने समस्यायें हैं जिनसे हम अपनी आखें नहीं मूंद सकते । सोशल वेलफेयर के कार्यक्रमों पर जितना खर्च होना चाहिये था वह नहीं हुआ है । इसमें हमें पैसा बढ़ाना चाहिये था । हमारी जितनी भी सोशल वैलफेयर की स्कीम्स चल रही हैं अगर उनको कुशलता से आगे नहीं बढ़ाया जायगा तो वे एकदम मर जायेंगी और हमें फिर नये सिरे से शुरू करना होगा । कई स्कीमें ऐसी होती हैं जो केवल मुनाफे के लिये ही नहीं बनाई जातीं । इसीलिये हमें इस सम्बन्ध में अधिक व्यवस्था करनी चाहिये थी । हमारी सरकार ने आबपाशी के इन्तजाम को बढ़ाने का प्रयास किया है वह सराहनीय है । इनके अनुसार ११० प्रतिवर्ष ट्यूबवैल्स लगा दिये जायेंगे, इससे हमको राहत पहुंचेंगी । चाहिये तो यह था कि इससे भी अधिक ट्यूब वेल्स का प्रबन्ध करने की व्यवस्था होती । गंडक नदी के सम्बन्ध में कांग्रेस के समय में जो बजट बनाया गया था उससे हमको उम्मीद थी कि वह नदी को हार्नेश करेगा और गोरखपुर को भी पानी मुहैया होगा। मैं बताना चाहता हूं कि पहिले जिस तरह से कार्यवाही इस पर चल रही थी उससे बांध के टूट जाने का खतरा था और जो नहर निकाली जा रही है अगर इस समय उस पर ठोस काम नहीं किया होता तो नहर नदी का काम करती ।

कुछ बातें और हैं जिसके द्वारा हम कृषि के उत्थान और प्रगति की दिशा में कदम उठाना चाहते हैं । जैसे सस्ती खाद का इन्तजाम है । हमारे दल के लोगों ने कहा था कि हरी खादों में ज्यादा पैसा खर्च होता है, वह खर्चीली है । लेकिन हमारा विश्वास है कि अगर हमने खाद के सस्ता करने की बात की होती तो काश्तकारों की उपज ज्यादा बढ़ती है । हम भी एक काश्तकार हैं । हमको इसका अनुभव है । हमारा ३२ एकड़ गन्ना सूख रहा है । स्टेट के

[श्री रामनरेश पाण्डेय]

ट्यूब वैल्स से पानी नहीं मिल पाया है । हम ही इसके शिकार नहीं हैं, लाखों आदमी ट्यूब-वैल्स की बदइन्तजामी से उसके शिकार हो रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उनको इसके इन्तजाम के लिये घूमना चाहिये । शासन की कुशलता तो हमारे सामने है लेकिन जो तथ्य हैं उसको भी हम भुला नहीं सकते हैं । गन्ने का उत्पादन बढ़ना चाहिये । इससे चीनी पर प्रभाव पड़ेगा । आज जो गन्ने के पानी का रेट बढ़ा है उसी पर काश्तकारों को देवरिया जिले में पानी दिया जा रहा है । अगर सरकार को चीनी की मात्रा बढ़ानी है और गन्ने की पर एकड़ ईल्ड बढ़ानी है तो वैसी नीति भी होनी चाहिये ।

सरकार की ओर से माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ६०० एकड़ से घटाकर कमान्ड एरिया ३०० एकड़ कर दिया गया है । क्या सरकार ने यह सोचा है कि बचे हुये ३०० एकड़ के लिये क्या होगा ? या उसके लिये सरकारी ट्यूबवैल्स की घोषणा करेंगे ? लोग निजी ट्यूबवैल्स नहीं लगा सकते हैं, तो हम कैसे मान लें कि बचे हुये ३०० एकड़ में ठीक से आबपाशी हो सकेगी ? माना कि पैकेज प्रोग्राम में हमने एकड़ कम किया लेकिन बचे हुये हिस्से का भी खयाल करना जरूरी समझा गया ?

हम इस बजट को प्रगतिशील और समाजवादी मानते हैं और गरीबों के लिये हमदर्दी रखने वाला मानते हैं । इस बजट में ऐसे लोगों को दबाने की कोशिश जरूर की गई है, दबाने की नहीं कम राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है जिन्होंने कांग्रेस के जमाने में खूब लूटा है ।

सरकारी नौकरों की बहुत चर्चा कांग्रेस की ओर से की गई । उन्हीं के राज्य में उनके बारे में जो कुछ हुआ वह आपके सामने है । चौधरी चरण सिंह ने जो राहत देने की बात की है उससे हम लोगोंको पर्याप्त सन्तुष्टि है । पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सरकार के साथ है और हमारा पूरा यकीन है कि यह सरकार इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करेगी । कोई भी समाजवादी सरकार छटनी को नापसन्द करती है । इन नौकरों को हटाने के बजाय अगर हम उन्हें दूसरी जगह रख देंगे तो तमाम समस्या का समाधान हो जायगा । इससे कर्मचारी संतुष्ट हो सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है ।

हमने अपने जिले में देखा कि लोगों में घूस लेने और देने की प्रवृत्ति का खात्मा हुआ । उनके मन में डर पैदा हुआ । जनता हमारी तरफ देख रही है कि हम उसे कहां तक राहत देने में सफल रहते हैं । जनता हमको पूरा कोआपरेशन दे रही है, जैसे गल्ले की वसूली में उसने स्वेच्छा से गल्ला दिया । हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि २ कीलो, ४ कीलो, गल्ला जनता ने स्वेच्छा से पहुंचाया । जहां फसल मारी गई, वहां इतना भी क्या कम है ? सवाल यह है कि खुशी से दिया ।

(इस समय २ बजकर २० मिनट पर, श्री उपाध्यक्ष, श्री श्रीपत मिश्र, पीठासीन हुये ।)

इतना कहने के बाद हम हायर सेकेन्डरी टीचर्स की तरफ और उनकी समस्याओं की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे । हमको तो ऐसा लगा कि हमारी सरकार ने अध्यापकों को एक मजदूर जैसा माना । उसने उनके प्रश्न को राष्ट्रीय सवाल नहीं माना है । मैं घोषित करता हूं कि मैं भी एक टीचर हूं । मैं समझता हूं कि अध्यापकों की उपेक्षा करके कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है ।

मैं बजट का पूर्णतया समर्थन करता हूं और इस सरकार का समर्थन करता हूं ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला पिथौरागढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस आम बहस के दौरन में दोनों पक्षों की स्पीचेज सुनीं और अब तक एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का और टीका टिप्पणी का रवैया रहा है । मैं समझता हूं कि जो

भी पार्टी हो या इंसान हो, तरक्की अपने गुणों से करता है । जनता ने हमें यहां इसलिये भेजा है कि हम उसकी बेहतरी की बात सोचें, देश का उत्थान हो और जनता के रोटी कपड़े को हम सोचें । मुझे दुख है कि इस विचारधारा से अभी तक कोई भी स्पीच नहीं हुई । मैं आशा करता हूं कि दोनों तरफ के सदस्य अपनी आपसी रंजिश छोड़कर देश के निर्माण की ओर अपनी शक्ति लगावेंगे ।

वैसे अगर देखा जाय तो उधर के लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने २० साल में इस प्रदेश को सिवाय बरबाद करने के और कुछ नहीं किया। यह बात गलत है । अंग्रेज जब यहां थे तो १२ करोड़ का बजट था । मगर आज कांग्रेस की ही देन है कि इस साल का बजट ३२४ करोड़ ८२ लाख का बना है । तो यह कहना कि प्रगति नहीं हुई, नितान्त भूल है ।

मैं पर्वतीय इलाके के बारे में ज्यादातर कहना चाहूंगा। पर्वतीय, प्रदेश के बारे में अभी तक इस सदन में कोई चर्चा नहीं हुई । उत्तराखन्ड के लिये इस साल केवल ३।। करोड़ रुपया स्वीकार किया गया है । जबकि पिछली पंचवर्षीय योजना में २८ करोड़ रुपये का बजट था । इसका मतलब यह है कि ५ साल में १७।। करोड़ ही हमको मिलेगा । यह बहुत ज्यादा कटौती हुई । मुझे विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ था कि १९ ।। करोड़ रुपया इस पंचवर्षीय योजना में रखा गया है, लेकिन उसका कोई आभास मुझे इस बजट में नहीं मिला । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालें कि उत्तराखन्ड का बजट इतना ज्यादा यकायक क्यों काट दिया गया ? वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है । वहां खाने पहनने की समस्या है । वह निर्धन इलाका है । २८ करोड़ से काम वहां हुये उनसे समस्या हल नहीं हुई । मुझे तो पूर्ण आशा थी कि इस योजना में २८ करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि वहां के लिये रखी जायगी । वह तिब्बत के बार्डर का इलाका है और चीन से मिला हुआ है । शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है और कोई रोजगार, इंडस्ट्री या खेती वहां नहीं होती। साल भर में तीन महीने का भी अनाज वहां पैदा नहीं होता है । ऐसी परिस्थिति में सरकार को उधर ध्यान अवश्य देना चाहिये । जब वहां २८ रुपये खर्च होते हैं तो २४ रुपये केन्द्रीय सरकार देती है । इस प्रकार से सिर्फ ४ रुपये इस प्रदेश की सरकार को देने पड़ते हैं । फिर भी अगर प्रदेशीय सरकार वहां की उन्नति के लिये पूरा प्रयत्न न करे तो मैं यह समझता हूं कि यह वहां की जनता की एक बहुत दुखद कहानी है ।

दूसरे मैं आपके जरिये से माननीय नेता सदन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक विकास बोर्ड पहाड़ों के उत्थान के लिये ३.४३ करोड़ से स्थापित किया है । लेकिन इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि इससे केवल सलाहकार बोर्ड रहने से समस्या का कोई हल नहीं होगा । सरकार इसको एक महत्वपूर्ण संस्था बनाये जिससे वह काम कर सके । उसको फाइनेन्शियल पावर्स दी जानी चाहिये और उसके चेयरमैन के पद पर किसी मिनिस्टर के रैंक का व्यक्ति रखा जाय । अगर इसको केवल सलाहकार बोर्ड ही रखा गया तो उत्तराखण्ड बोर्ड की तरह सिर्फ कुछ लोगों द्वारा भत्ता खर्च किया जाता रहेगा लेकिन काम कोई न होगा । वह रिपोर्ट देगा और सरकार उस र कोई विचार नहीं करेगी । इसलिये मैं आशा करता हूं कि इसको सरकार अधिक अधि ार दे जिससे पर्वतीय जिलों का विकास हो सके ।

तीसरे आजकल पर्वतीय प्रदेश में अन्न का महान कष्ट है । नार्मल ईयर्स में भी वहां पर साल में ३ महीनों के लिये ही होता है । लेकिन दो साल से बराबर सूखा पड़ने के कारण वहां पर बड़ी हाहाकार मची हुई है । अभी आपके सामने माननीय प्रताप सिंह जी ने कहा कि वहां पर ३ मौतें भी हो गयी हैं और वे इन ३–४ महीनों में ही हुई हैं । इससे आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि वहां पर अन्न का कितना कष्ट है । जब मैं अपनी कान्स्टीटुएन्सी में गया तो मैंने लोगों को बड़े कष्ट में पाया । मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर विशेष रूप से ध्यान देगी ।

एक बात और भी महत्वपूर्ण है वह यह है कि चम्पावत तहसील पिथौरागढ़ जिले का पैर है जो रेलवे हैड टनकपुर से जुड़ा हुआ है लेकिन वह पिथौरागढ़ जिले में नहीं है इसलिये यह जिला उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कोई इंसान बिना पैर के हो । बिना चम्पावत के पिथौरागढ़ पूरा

]श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट]

जिला नहीं समझा जा सकता। मैं आशा करता हूं कि सरकार चम्पावत तहसील को पिथौरागढ़ में मिला देगी। ताकि वहां का विकास भी पिथौरागढ़ के साथ साथ हो सके। अभी तक वह अल्मोड़ा जिले में है और बिलकुल पिछड़ा हुआ इलाका है। अंग्रेजी हुकूमत में भी वहां का विकास नहीं हो पाया। उस समय भी रानीखेत अल्मोड़ा जैसे स्थानों का विकास हुआ लेकिन इसका नहीं हुआ और अब चीन के हमले के बाद जब नये जिले बनाये गये तो भी चम्पावत के इलाके को अलैहदा ही छोड़ दिया गया वहां की कोई तरक्की नहीं हो रही है। मैं सरकार से चाहूंगा कि चम्पावत तहसील को किसी न किसी तरह से पिथोरागढ़ जिले से मिला दें इसका बोर्डर चीन से ही नहीं नैपाल से भी मिलता है। यह एक छोटा सा भाग है पिथौरागढ़ का और वहां न कोई उद्योग है, न अच्छी खेती ही है और वहां के लोग बहुत गरीब हैं और अत्यन्त कष्ट से वह पीड़ित रहते हैं। वहां की जनता बराबर अपनी दरिद्रता की कहानी रोती रही है और वह भाग आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। इस लिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाय और इस इलाके को पिथौरागढ़ जिले में मिलाने की कृपा की जाय।

अभी तक जितनी पंचवर्षीय योजनायें बनी उन में पिथौरागढ़ जिले के लिये सर्वत्र बिजली की योजनायें मंजूर हुई और उन के लिये काफी धनराशि मंजूर हुई लेकिन आजतक पिथौरागढ़ जिले में पानी से बिजली बनाने और उसको उद्योग में लगाने की कोई भी योजना कार्यान्वित नहीं हुई। इस तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये क्योंकि बिजली पर ही वहां की कृषि, सिंचाई और उद्योग धन्धे आधारित हैं। वहां का मंजूर रुपया ही लैप्स नहीं हुआ बल्कि वहां की प्रगति भी रुकी है। मैं चाहता हूं कि इस तरफ सरकार विशेष ध्यान दे ताकि बिजली और उद्योगों की सारी योजनायें वहां कार्यान्वित हो सकें।

वनों के बारे में भी मैं कहूंगा कि स्वायल कंनजरवेशन डिवीजन खोलने के लिये पिछले ५ साल से डेवलपमेन्ट बोर्ड से, वहां की स्टेंडिंग कमेटी से और कुमायूं फारेस्ट से भी प्रस्ताव हुये कि पिथौरागढ़ में इरोजन बहुत हो रहा है और वहां एक स्वायल कन्जरवेशन डिवीजन खुलना चाहिये। यहां से भी करीब करीब यह चीज पास हो चुकी थी लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। मैं चाहता हूं कि इसी साल सरकार वहां स्वायल कन्जरवेशन डिवीजन जरूर खोलने का प्रयत्न करे।

सहकारिता आन्दोलन में भी पिथौरागढ़ जिले में कोई कार्य प्रगति का नहीं हुआ है और कोई उद्योग भी सहकारिता के क्षेत्र में स्थापित नहीं हुआ है। मैंने सुना है कि मैदानी इलाकों में उद्योग विभाग सब जगह तोड़ा जा रहा है और जिला उद्योग अधिकारी की पोस्ट को समाप्त किया जा रहा है वैसे ही पर्वतीय क्षेत्र में भी जहां कोई इस तरह का विभाग नहीं है और वहां के ग्रामीण नहीं जानते कि उद्योग कैसे चलाये जाते हैं, उनका क्या महत्व है और नहीं जानते कि कहां से कौन सी मशीनरी लाकर कैसे चलाई जाय, उन के दिल में उद्योग के प्रति रुचि पैदा करने के लिये जरूरी है कि चाहे सब जगह से यह इंडस्ट्रीज आफिसर हटाये जायं लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के लिये अपवाद कर के उन को वहां अवश्य रखा जाय। कोई उद्योग अधिकारी अगर निकम्मा हो तो उसे जरूर बदला जाय लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में जहां उद्योग की अभी शुरुआत ही थी उस को 'निप इन दि बड' न किया जाय, वहां तो होशियार आदमियों को भेजकर वहां के लोगों को इंडस्ट्री-माइन्डेड बनाया जाय। जैसे भी हो वहां सहकारिता के क्षेत्र में या वैसे कोई उद्योग कायम किया जाय और वहां जो उद्योग के सेन्टर हैं उन्हें वैसे ही रहने दिया जाय जैसे मैदानी इलाके में चल रहे हैं। उत्तराखन्ड क्षेत्र में उनको तोड़ना उचित न होगा।

पिथौरागढ़ जिले में एक रेडियो स्टेशन खोलने की भी बात थी, पता नहीं केन्द्र द्वारा इस संबंध में यहां की सरकार से भी राय ली जाती है या नहीं, लेकिन उसके बनने की वहां नितान्त आवश्यकता है। वह एक बहुत रमणीक स्थान है वह भी मसूरी, नैनीताल शिमला की तरह टूरिस्ट सेन्टर बन सकता है। यदि सरकार थोड़ी रुचि ले तो वहां के लोग भी इस तरफ आकर्षित हो सकते हैं और बहुत अच्छे टूरिस्ट केन्द्र वहां बन सकते हैं जैसे कि कश्मीर

में बने हुये हैं । वहां का जो फारेस्ट हाउस है वहां भी बिजली वगैरा लग जाय और थोड़ी सी और फैसिलिटीज हो जायं तो वहां भी काफी तरक्की हो सकती है । और दूध और दही की व्यवस्था अगर वहां पर हो जाय तो पिथौरागढ़ एक बहुत सुन्दर टूरिस्ट सेन्टर हो सकता है। माननीय सम्पूर्णानन्द जी के समय में जब ये नये जिले बनाये गये थे तो ३२ लाख रुपये की धनराशि से एक डिग्री कालेज चलाने की व्यवस्था की गयी थी लेकिन ७–८ साल हो गये अब तक भी वहां पर उस दिशा में कोई भवन निर्माण नहीं हुआ है । अभी तक वहां पर शेड्समें काम चलाया जा रहा है । अभी कुछ दिन हुये हमारे शिक्षा मंत्री जी वहां पर गये थे और उनके कर कमलों से वहां पर भवन की शिलान्यास हुआ है । मुझे आशा है कि इस ओर पूरी दिलचस्पी रखेंगे और वे इस बात का प्रयत्न करेंगे कि जो भवन वहां पर बनने वाले हैं, वे शीघ्रातिशीघ्र बन सकें क्योंकि वहां पर भवनों के न होने के कारण एकोमोडेशन की बहुत तकलीफ है जिससे वहां पर लेबारेटरीज और विज्ञान के इन्स्ट्रमेन्ट्स नहीं ले जाये जा सकते हैं ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय बजट पर सामान्य विवाद चल रहा हो, उस समय मंत्रि-मंडल का कोई न कोई सदस्य यहां पर उपस्थित रहें तो बड़ी कृपा हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो वे आकर बैठ गये हैं ।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—

श्रीमन्, मेरी कोन्स्टीट्एन्सी में एक डैम बनने जा रहा है जिसके लिये केन्द्र के इर्रीगेशन व पावर के मंत्री, श्री राय, आये थे । उनका कहना था कि वहां पर एक बड़ा पंचेश्वर डैम बनेगा । यह सुनकर वहां के लोगों ने बड़ी आशा लगायी थी लेकिन इस काम में वांछित प्रगति नहीं हो रही है ।

श्री रामायण राय—

श्रीमन्, कोई मंत्री इस समय सदन में नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी बैठे तो हैं ।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट—

मैं इस सरकार से भी पंचेश्वर डैम की योजना को जल्दी से जल्दी करवाने की प्रार्थना करूंगा ।

एक महत्वपूर्ण बात की ओर मैं इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि इस इलाके के लोग बहुत गरीब हैं लेकिन उस पर भी शराब की भट्टियों को बढ़ाते जा रहे हैं और जगह-जगह पर शराब की भट्टियां चल रही हैं । उत्तराखंड में जो काम करके लोगों ने पैसा बनाया है वह अब शराब में जाया कर देते हैं जिसके कारण वहां के लोगों की आर्थिक दशा दिन प्रति दिन खराब हो रही है । सरकार को भी कोई लाभ नहीं हो रहा है । एक तरफ तो हमारी सरकार २८ करोड़ की योजना बनाये और दूसरी तरफ ५–१० लाख के लाभ के लिये वहां पर शराब की भट्टियां खुल जाये, यह बहुत गलत बात है । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इनको तोड़ा जाय और जितना कम हो सके वह किया जाय ताकि जनता का आर्थिक स्तर नीचे न गिरने पाये और वहां के लोग सुख का जीवन बिता सकें ।

मैंने सरकार का विशेष ध्यान बहुत सी चीजों की ओर आकर्षित किया है परन्तु और चीजों में हम उतनी उन्नति नहीं कर पायेंगे जितनी उन्नति हम हार्टिकल्चर में कर पायेंगे। जैसे चौपटियों में एक नर्सरी कायम है वैसे ही इन ३ जिलों में भी नर्सरी चलायी जायं ताकि वहां पर

[श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट]

फलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके । वैसे ही डेरी फार्म, पोल्ट्री का काम है । इस सम्बन्ध में मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरी का उत्थान सरकार तभी उन इलाकों में कर सकती है जबकि मुक्तेश्वर की तरह सरकारी डेरी बना कर वहां ब्रीड करे और जानवरों की वृद्धि इन तीनों जिलों में एक-एक सेन्टर खोल कर वहां से की जाय । वहां का आर्थिक स्तर अभी तक जैसे का तैसा है ।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री चले गये उनसे मेरा निवेदन है कि वहां के डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स की इमारत करीब करीब तैयार है। इसको शीघ्रातिशीघ्र चलाने की कोशिश की जाय। पी० डब्ल्यू० डी० में जो सड़कों के निर्माण का काम है गंगोलीहाट के अन्दर उसे ज्यादा चलाने की जरूरत है क्योंकि लोग बहुत गरीब हैं, धन न होने से अनाज भी नहीं खरीद सकते । उन लोगों को जिनकी जमीन ली गई है १० साल से अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कम्पेन्सेशन नहीं दिया है । इन केसेज को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाय । तराई में जमीन देने के लिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि बंगाल के रिफ्यूजी और सिखों को जमीन देने के बजाय पर्वतीय प्रदेश के लोगों का सबसे पहला स्थान होना चाहिये । जिनकी जमीनें कैन्टोनमेन्ट के लिये ली गई है या फौजी भाई हैं उन लोगों को तराई में भूमि देने की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

सेरीकल्चर के लिय भी मुझे कहना है। अभी तक बहुत कम काम इस दिशा में हो रहा है। अगर सेरीकल्चर में इस ओर विशेष ध्यान दिया गया तो हमारे इस इलाके में काफी उन्नति हो सकती है । आखिरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि अभी तक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन्स हमारे इन तीनों जिलों में, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में नहीं हैं । वहां न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, न म्युनिसिपलबोर्ड और न क्षेत्र समितियां हैं, इसकी ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये और जैसे मैदान में चुनाव हो कर ये बौडीज बनायी गई हैं ऐसे ही वहां भी बननी चाहिये । गरीबी इतनी ज्यादा है कि लोगों को खाने तक को नहीं है ऐसी दशा में जो नेशनलाइज्ड जो आपकी रोडवेज की ट्रान्सपोर्ट है उस के भाड़े में, आदमियों के और माल के भाड़े में, कंसेशन होना चाहिये । अभी तक यह देखा गया है कि थर्ड क्लास सड़क होने की वजह से उस का जो भाड़ा है बहुत ऐग्जोर-बीटेंट है जिस की वजह से बहुत महंगी चीजें हो गई हैं । जब यहां ५ रु० किलो चीनी मिलती है तो उस इलाके में काफी फर्क हो जाता है । चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा वहां बढ़ गई हैं । इसके लिये और आप कोई काम न कर सकें तो इतना तो कर दें कि रोडवेज के भाड़े में कमी करने के लिये विशेष कृपा करें ।

*श्री मुलायमसिंह (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । २० वर्ष से इस कांग्रेस शासन ने अपने गलत नियोजन द्वारा और दोषपूर्ण नीतियों के द्वारा हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था और हमारे जीवन के समस्त पहलुओं को नष्ट किया । ऐसी परिस्थितियों में जो बजट पेश किया गया है वह बचत का है और मूल्यों को संतुलित करने के लिए प्रयास है। जब कांग्रेस शासन था तब प्रतिवर्ष बजट पेश होता था और सदा घाटे का बजट दिखाया जाता था तब यह कहा जाता था विकसित समाजवाद के लिए टैक्स लगाना जरूरी है । वह समाजवाद का नारा देते थे और कांग्रेस ने अपने शासन में कभी भी समाजवाद को कार्यान्वित नहीं कर पाया और उस ने सुनहले समाजवाद के बहाने प्रदेश की जनता के आर्थिक जीवन को नष्ट कर दिया। इन परिस्थितियों में जो हमारी सरकार ने बजट पेश किया है वह बधाई का बजट है और उसका स्वागत करना चाहिए था । विरोधियों ने जहां इसका विरोध किया वहां प्रदेश की जनता ने इसका स्वागत किया और वह इस ओर से निसंकोच हो गयी कि आगे टैक्सेज लगने वाले नहीं हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कांग्रेस सरकार जो खाद्य के मामले में पीछे हटती जा रही है इस सरकार ने इस ओर अग्रसर होने के लिए हार्दिक प्रयास किया है और इसका सबूत यह है कि बजट का बहुत बड़ा हिस्सा विकास के लिए रखा गया है। लेकिन किसानों को जो इस सरकार से आशा थी उसे वह पूरा नहीं कर सकी क्योंकि इसे लगान माफ करना चाहिए था। उसे वह नहीं कर सकी और वह अपने वायदे को पूरा नहीं कर सकी। दूसरे एक नारा यह था कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए लेकिन इस सरकार ने इस ओर भी उपेक्षा बरती है क्योंकि जो मांगें अध्यापकों की चल रही थीं उनकी ओर इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। पब्लिक स्कूलों में एक ओर तो एक बच्चे पर ३०० रुपए माहवार खर्च होते हैं दूसरी ओर गरीब किसान व मजदूर के बच्चों को बैठने के लिए झोपड़ी भी नहीं है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि पब्लिक स्कूल जो हैं वह जल्दी से जल्दी समाप्त किए जायं। मुझे आशा है कि सरकार शीघ्रातिशीघ्र लगान माफ करेगी और असमानता को दूर करेगी।

हमारी सरकार यह कहती है कि वह पूंजीवाद प्रथा को खत्म करेगी लेकिन वह कांग्रेस की जो परम्परायें तथा दोषपूर्ण नीतियां थीं उनसे अपने को मुक्त नहीं कर सकी है। हमारे प्रदेश में पूंजीपतियों, जमाखोरों, चोरबाजारों तथा रिश्वतखोरों ने जो गरीबों की कमाई को बुरे तरीके से एकत्रित किया था उसको वापस लेने के लिए इस सरकार ने इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की है।

अब मैं कांग्रेस की कारगुजारियों पर आ रहा हूं जो बड़े जोरों से मेजें थपथपा रहे हैं। ए० डी० ओ० (महिलाओं) को, ग्राम सेविकाओं तथा ग्राम लक्ष्मियों को इस सरकार ने खत्म किया। कांग्रेस की ओर से उनके प्रति बड़ी सहानुभूति दिखाई जा रही है। लेकिन क्या कभी कांग्रेस सरकार ने इस ओर ध्यान दिया कि उन्होंने गांव में जा कर क्या काम किया। उन्होंने गांवों में जाकर महिलाओं तथा लड़कियों को चुड़ैलें बना दिया और वह शिक्षा दी कि गांव को भ्रष्टाचार का साधन बना दिया। उन्होंने वहां अच्छी से अच्छी साड़ी पहनना सिखाया, क्रीम और पाउडर लगाना सिखाया, परिवारों में मतभेद कराने का प्रयास किया। हमारी सरकार की नीति है कि कोई भी विभाग हो अथवा व्यक्ति जो जनता के कल्याण की बात नहीं कर सकता उसे रखा नहीं जायगा। आप दलील देते हैं कि बेकारी बढ़ेगी लेकिन ये जो हमारे प्रदेश को बरबाद करने जा रही थीं अगर निकाल दिए जाने पर बेकार हो जायंगी तो उससे क्या हर्ज हो जायगा? इस तरह से हमारी सरकार की नीति की जो बड़े जोरों से आलोचना की जा रही है यह उचित नहीं है। इसमें साफ तौर से कह दिया गया है कि उनकी भी व्यवस्था की जायगी। जो हमारे प्रदेश की जनता के हित में नहीं हो सकते हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं है।

आगे मैं अपनी सरकार के सामने सुझाव रखता हूं कि कांग्रेस की दोषपूर्ण नीतियों के कारण जो जंगलात का एरिया बनाया गया है वह बहुत जगहों पर गलत तरीके से बनाया गया है। मिसाल के लिए गांव की गलियों तक को जंगलात में रख दिया गया था, जहां पर मवेशी बांधे जाते हैं वह स्थान भी जंगलात में रख दिए गए। उनको समाप्त करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं मानता हूं कि जंगलात की आवश्यकता है, पानी बरसेगा, लकड़ी की व्यवस्था होगी, लेकिन क्या गलियों में जंगल लगेगा। तो मैं अपनी सरकार के सामने सुझाव रखता हूं कि इस ओर भी ध्यान दे।

अन्त में मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सुबह भी कहा था, मेरा आपके पास नाम भी गया लेकिन आपने मुझे बुलाने का कष्ट नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य आश्वस्त रहें, मैं उनको अवश्य समय दूंगा।

*श्री रामनाथ (जिला मिर्जापुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मिर्जापुर जिले का रहने वाला हूं जहां बहुत अकाल पड़ा हुआ है। हमारी सरकार के बहुत से मिनिस्टर्स उस जिले में आए, हमारे मुख्य मन्त्री जी भी आए और उनके सामने अकाल को दिखाया गया। आज कहा जाता है कि पहले की सरकार बड़ी गलत थी और आज की सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं एक समस्या आपके सामने रख रहा हूं कि कांग्रेस सरकार के जमाने में टेस्ट वर्क पर काम करने वाले मजदूरों को एक हफ्ते के अन्दर मजदूरी बांटी जाती थी मगर आज १५-१५ दिन और १-१ महीना के बाद मजदूरी बांटी जाती है। जो गरीब अपने छोटे-छोटे बच्चों को ले कर मिट्टी खोद रहे हैं वे मजदूरी न पाने के कारण महान कष्ट उठा रहे हैं। अधिकारियों की फौज वहां भेज दी गयी है। एक-एक तहसील में दो-दो हाकिम परगना भेज दिए गए हैं मोटरें इधर से उधर दौड़ रही हैं। उनका काम कितना सुन्दर हो रहा है यह अगर किसी को देखना हो तो वह मिर्जापुर में आ कर देखे मैं दिखाऊंगा। मुख्य मन्त्री के आदेश के बावजूद आज एक-एक महीने तक उनको मजदूरी नहीं मिलती है। क्या ऐसा ही प्रबन्ध संयुक्त विधायक दल की सरकार का होगा। अगर इसी तरह का इन्तजाम होना है तो इससे तो पहली सरकार अच्छी थी। मन्त्रिगण मिर्जापुर जाते हैं। वहां से सौ मील दूर रिहन्द डैम है। सीधे वहां मोटर जाती है। अगल बगल क्या हो रहा है, लोग भूखों मर रहे हैं या क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। इस हुकूमत के आने के बाद दौरे में कितना खर्च हुआ है, टेस्ट वर्क के नाम पर मजदूरों को रोटी दी जा रही है या अधिकारियों का पेट भरा जा रहा है यह मिर्जापुर चल कर देखिए। इन्तजाम दौरे या बैंस से नहीं होगा, उसके लिए कार्यवाही कीजिए और जांच कराइए। बड़े-बड़े अफसरों से प्राइवेट काम बनवाया जा रहा है। जो गरीब हैं वहां टैस्ट वर्क नहीं लगेगा। श्रीमन्, आज से नहीं वर्षों में बराबर कहता चला आ रहा हूं कि हमारे यहां पीने के पानी के लिए ४-५ मील जाना पड़ता है। एल० एस० जी० विभाग द्वारा स्कीम बनाई गई थी कि पाइप लाइन बिछा दी जाय। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। पानी के अभाव में बहुत से मवेशी मर गए हैं। घास और भूसा भी नहीं मिल रहा है। सैकड़ों मवेशी घास, भूसा और पानी के अभाव में मर गए हैं। जब मवेशी ही नहीं रहेंगे तो आज जैसा आकाल पड़ा हुआ है उससे कहीं भयंकर अकाल पड़ेगा।

वर्षा होने के लिए किसान आशा लगाए रहते हैं कि धान की खेती करेंगे। अक्सर १५ जून से वर्षा शुरू हो जाती है। इस साल १५ जून तो क्या २१ जून हो गई है लेकिन आज तक किसानों को बीज नहीं दिया गया है। किसान लोग घबराए हुए हैं कि अगर पानी बरस गया तो बोने के लिए बीज कहां से लायेंगे। मुख्य मन्त्री जी के सामने इस बात को रखा गया कि टेस्ट वर्क्स पर १५-१५, २५-२५ दिन बाद मजदूरी दी जा रही है। आज तक बहुत से टेस्ट वर्क्स पर मजदूरी नहीं बंटी है। मजदूरों को इस महंगाई के जमाने में समय से मजदूरी मिलनी चाहिए और किसानों को बीज देने की व्यवस्था की जाय तथा पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्रीमन्, यहां पर स्वास्थ्य मन्त्री जी बैठे हैं, हमारे इस इलाके में ५०-५० मील दूर तक गांवों में कोई भी अस्पताल कैसा भी नहीं है।

श्री राजबहादुर--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य जरा बैठ जायं। माननीय सदस्य जरा ध्यान रखें कि सदन में सतर्क रहना अत्यन्त उचित और आवश्यक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक दफा हमारे यहां हैजा फैल गया। लेकिन २५-३० मील तक वहां कोई अस्पताल नहीं था और खबर आते-आते बहुत से आदमी मर गए। टेस्ट वर्क्स पर अगर ज्यादा मजदूर हो जाते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है। इस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यहां खाली बजट पेश कर देने और पास कर देने से काम नहीं चलेगा बल्कि आप लोग देखिए कि काम हो रहा है या नहीं। जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपके अधिकारी काम करने वाले नहीं हैं। हमारे यहां २५-२५ मील की दूरी पर कोई टेस्ट वर्क नहीं है। बीज के लिए जिलाधीश कहते हैं कि ५ एकड़ जिसके पास जमीन है उसको बीज दिया जायगा। इससे ऊपर वाले को बीज नहीं दिया जायगा। यह उचित नहीं है। २५ एकड़ वाले किसान को ५ एकड़ का बीज तो देना ही चाहिए। तकावी और बीज की व्यवस्था की जाय। पानी बरसने पर मजदूर कम मिलेंगे। उस समय भुखमरी होगी। इसके लिए अभी से सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। एक बुढ़िया कई दिन की भूखी थी वह खाने के शिविर तक नहीं पहुंची। बीच में ही गिर कर मर गयी। अधिकारी कहते हैं कि वह बीमार होकर मरी और गांव सभापतियों से भी कहते हैं कि वह कह दें कि भूख से नहीं मरी।

पाइप लाइन जो लगायी जा रही है, पहले यह तय हुआ था कि पाइप लाइन पहाड़ों में दी जाय। उस पर लाखों रुपया लग चुका है। उसे कहा जाता है कि अस्थायी है। लोगों का कहना है कि ८५ पैसे फीट उस लाइन पर खर्चा पड़ा है, उस लाइन को फिर उखड़वाने में कितना पैसा नष्ट होगा। उस पाइप लाइन को स्थायी किया जाय।

पिछले जमाने में गांवों में वहां तालाब थे। नक्शों में मौजूद हैं। १९१६ में अकाल पड़ा। तालाब पटने से पहाड़ का स्तर ऊंचा हो गया है। तालाब पटने से वहां के कुएं भी सूख गए हैं। उन तालाबों को जो हर गांव के नक्शे में हैं, उनको खुदवा कर दुरुस्त कर दिया जिससे पानी का वहां कभी अकाल न पड़े। यह दोषारोपण करने से कि वह सरकार गलत थी या यह सरकार गलत है कोई लाभ नहीं है। इन्तजाम कैसे हो यह देखने की बात है। दो महीने में इसका सबसे बड़ा सबूत है कि वहां पर मजदूरी १२ महीने के बाद बांटी जाती है। उन अधिकारियों की जांच करायी जाय कि ऐसा क्यों किया गया। पिछली सरकार के जमाने में जो मजदूरी सात दिन में बंटती थी अब २०, २५ दिन पर बटती है। ऐसा क्यों किया गया? उस इलाके में रबी की कुछ बोवाई होती है। वहां पत्थर (ओले) पड़ गए। गुप्ता जी और प्रधान मन्त्री वहां आए थे। उन्होंने पत्थर को देखा। सारे गांव के गांव साफ हो गए। खपरैल तक बाकी नहीं बची। उस पत्थर वाले इलाके में किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गयी। घर भी नहीं छाए जायंगे। उसके लिए जो भी व्यवस्था हो सरकार की तरफ से की जाय। अभी एक नया आदेश हुआ है। मवेशियों की, जंगल में चराई लगती है। गाय और बैल की चराई मिर्जापुर और बनारस के राज में नहीं ली जाती थी। जो लोग जंगल में रहते हैं उनको इस पर बड़ा क्षोभ है कि गाय और बैल की चराई जो जमींदारों के जमाने में नहीं ली जाती थी अब वह भी ली जायगी। अगर यह चराई लगायी गयी तो लोगों को महान् कष्ट होगा। वहां पर अंधों और असहायों को मुफ्त गल्ला दिया जाता है। उनको समय पर गल्ला नहीं मिलता। अंधे और अपाहिज इधर उधर घूमते रहते हैं। कभी कहते हैं कि तहसील में जाओ, कभी कहते हैं कि ब्लाक में जाओ। जल्द से जल्द असहायों को गल्ला दिया जाय क्योंकि उनके पास कोई गल्ला नहीं है। गल्ला मिलते रहने का आदेश होने पर भी उन्हें समय से गल्ला नहीं मिलता तो परेशान होकर उनके भूखों मरने की नौबत आ जायगी। इसलिए आप से मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे असहायों को गल्ला देने की उचित व्यवस्था की जाय।....

श्री उपाध्यक्ष—

पाठक जी, क्या आप अभी और अधिक समय लेंगे?

[श्री रामनाथ पाठक]

जो कुछ कहना था मैंने सरकार से कह दिया कि वहां गल्ला देने का जल्द से जल्द प्रबन्ध किया जाय। वह सूखाग्रस्त इलाका है और वहां संकट की हालत है, यह तो सब लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। मेरा यही कहना है कि लोगों को मरने से बचाया जाय। और अब मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री रामदत्त (जिला नैनीताल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिनों से मुझे सदन के समक्ष उपस्थित बजट पर इस पक्ष के और उस पक्ष के सभी लोगों के विचार सुनने को मिले। उस पक्ष के लोगों ने अपनी आलोचना का मुख्य विषय सरकार का जो आज संगठन है उसको बनाया या कुछ ने शिकायत या शिकायत पेश की। लेकिन किसी ने कोई भी रचनात्मक आलोचना बजट की नहीं की जिससे हमें कोई बहुमूल्य सुझाव मिलता जिससे सरकार को भी नयी दिशा मिल सके। बहुतों ने चर्चा इस बात की भी की कि यह ७–८ या ९ दलों की मिली जुली सरकार है। किसी ने इसे भानुमति का पिटारा कहा, माननीय गोविन्द सहाय ने इसे सर्कस की संज्ञा दी और उसी के इर्दगिर्द उनका सारगर्भित भाषण समाप्त हो गया। मैं उधर बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों की गलतफहमी को दूर कर देना चाहता हूं कि उनको यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि किस दशा में, किस हालत में इधर के लोगों को नयी सरकार बनाने का अवसर मिला और उन्होंने कार्यभार सम्भाला। उन्हें हैरत होती है यह देख कर कि ये ८–९ पार्टियां किस तरह से इकट्ठा बैठी हुई हैं। उन्हें याद करना चाहिए कि उन्होंने पिछले २० साल के दौरान प्रदेश की हालत इस कदर खराब कर दी है और इतना संकट उत्पन्न कर दिया है कि जिस प्रकार पाकिस्तान के हमले के समय तमाम राजनीतिक दल उसका सामना करने के लिए एकत्रित हो गए थे, उसी प्रकार कांग्रेस के कुराज का सामना करने के लिए समस्त दल अपने भेदभाव को दूर करके आपस में इकट्ठा हुए हैं। आज देश और प्रदेश के अन्दर कांग्रेस ने अनेक संकट ला दिए। कांग्रेस ने पिछले बीस सालों में जो रवैय्या अख्तियार किया उससे इस देश में एक लानत की शक्ल हो गयी और फिर तमाम देश की पार्टियों का यह कर्तव्य हो गया कि इस लानत को अपने देश और प्रदेश से हटावें। आज तमाम दल जो इकट्ठा हुए हैं उनके सामने कोई उच्च सिद्धांत या आइडियोलाजी का प्रश्न नहीं आया क्योंकि इस कांग्रेस राज्य में मामूली से मामूली वह काम भी नहीं हुआ जो किसी पूंजीवादी सरकार में प्रशासनिक सुधार के नाम पर किया जाता। जो एक कल्याणकारी राज्य में कार्य होता है वह भी जनता के लिए नहीं किया गया। इसलिए यह परिस्थिति उत्पन्न हुई और प्रदेश के तमाम दलों ने मिल कर सोचा कि वह ऊंचे सिद्धांत और आइडियोलाजी की बात को छोड़ कर पहले जो इस प्रदेश का नर्क बना हुआ है उसे दूर किया जाय, इसको हटाया जाय। उसका उपचार करने के लिए सब दल ाले मिल कर यहां इकट्ठा हुए हैं।

समाजवाद की बात कही गयी। मैं यही अर्ज कर रहा था कि समाजवाद एक बहुत ही उच्च विचारधारा है। जो देश समृद्धशाली है उनके सामने यह सवाल आता है कि वहां की सम्पत्ति का बटवारा समान रूप से हो और सब को समान अवसर मिले जब कि बुनियादी बातें जो एक कल्याणकारी राज्य में होती हैं उनको हमने पूरा कर लिया हो। जैसा कि मैंने अर्ज किया वे पूरी नहीं हुई हैं और प्रदेश की हालत बदतर हो गयी है। समाजवाद के नारे की आड़ में कांग्रेस पार्टी पिछले २० साल से जो कार्य कर रही है उसके काले कारनामों ने उसको आकर्षण को एकदम से समाप्त कर दिया। इसलिए हमने यह सोचा कि हम बजाय नारा लगाने के काम करना शुरू करें और यही हमने करके दिखाया है और दिखाएंगे। आपकी तरह नारेबाजी करके हम भी उल्टा काम करते रहते तो आप हमारा साथ देते क्योंकि आपकी आदत खराब ह गई है। हमने मिलकर तय किया कि आज नारेबाजी का जमाना नहीं है काम करने का जमाना है। इस हेतु इस बजट में भी नारे बाजी नहीं है। सरकार ने आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को हटा दिया, इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि वे भ्रष्टाचार और पक्षपात के अड्डे

थे। हमने भूमि भवन कर हटा दिया है, इससे भी आपको तकलीफ है। यह कर किससे वसूल किया जाता था? जिसके पास न भूमि है न भवन। इस लानत को हटाने की बड़ी जरूरत थी और इनको हटाने से जनता को बड़ी राहत मिली है।

शिकायत की गयी कि समाज कल्याण के कार्यों पर कम खर्चा किया गया। मैं आपकी बात मानता हूं कि विकासोन्मुख समाज में इस पद पर ज्यादा खर्च करना चाहिए। लेकिन समाज कल्याण के नाम पर कांग्रेस सरकार जो कारनामे करती रही और जो फिजूलखर्ची करती रहे उन्हें अब बरदाश्त नहीं किया जा सकता है। महिला मंगल योजना कैसे कबूतर खाने की योजना जो कांग्रेस सरकार की काली करतूतों की योजना थी उसको हम नहीं चलने दे सकते हैं।

सरकारी कर्मचारियों की हमदर्दी में बड़ी-बड़ी आहें भरी गयीं, आवाज उठाई गई। जैसे इन्हें ही उनके साथ सारी सहानुभूति हो और हमें कुछ न हो। हमारी भी उनके साथ हमदर्दी है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने यह नहीं सोचा कि अभी यह सरकार दो-ढाई महीने पहले बनी है, प्रशासन सम्भाले उसे अभी थोड़ा समय हुआ है, और १० करोड़ रुपए बजट में उन्हें दे दिया गया है और इसके बाद भी हमारा इरादा है कि हम कांग्रेस सरकार की तरह जनता पर कोई कर न थोपें। उन्हें धीरज रखना चाहिए था कि हमें बैठने दें, सोचने दें कि हम आमदनी के साधन इकट्ठे करेंगे। लेकिन उन्होंने यह रुख अपनाने के बजाए डाइरेक्ट ऐक्शन लिया। यह राज्य कर्मचारियों की हड़ताल माननीय गुप्ता जी जो बहुत बड़े राजनैतिक खिलाड़ी हैं उनकी करामात है। सुचेता जी के जमाने में भी जब गुप्ता जी उनसे नाराज हुए उन्होंने हड़ताल करा दी, फिर जब गुप्ता जी गद्दी पर बैठे हड़ताल खत्म हो गयी और फिर जब दूसरी सरकार आई हड़ताल शुरू हो गयी। इन सब बातों की क्या वजह है, आप देखें? मैं आज भी कहता हूं कि उनकी मांग से हमारी सहानुभूति है, लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि एक ऐसी सरकार जिसने २ महीने पहले कार्यभार सम्भाला है, जिसने बर्बाद शुदा शासन को सम्भाला है और जिसने आमदनी के साधन समाप्त कर लिए हैं, उन्हें इस तरह की भेंट देना, इस प्रकार की नोटिस देना कोई भी प्रशासन बरदाश्त नहीं कर सकता है।

गल्ला वसूली करने की चर्चा की गयी, किसानों की हमदर्दी की गयी कि उनसे गल्ला वसूल किया जा रहा है। इधर कहते हैं कि इधर ७–८ पार्टियों की सरकार है, इसलिए इनके विचार भिन्न-भिन्न हैं। किन्तु मैं आपसे पूछता हूं कि आप में विभिन्न रायें क्यों हैं जबकि आपकी एक पार्टी की सरकार है। आपके जगजीवन राम जी गल्ला वसूली के बारे में कुछ कहते हैं और गुप्ता जी बात कुछ कहते हैं। आपमें त्रिपाठी गुट, गुप्ता गुट आदि-आदि न जाने कितने गुट हैं। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि जनकल्याण के लिए विभिन्न विचार धारा के लोग एक मंच पर आए हैं, और एक मत से उसके अनुसार काम कर रहे हैं। आपकी तरह हम समाजवाद का नारा लगाकर देश को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार से जो गल्ले का कोटा हमको मिलता था वह नहीं मिला। मैं नहीं कहता कि किसी दुर्भावना की वजह से या मजबूरी की वजह से किया गया लेकिन इतना कहता हूं कि केन्द्रीय सरकार से प्रान्तीय सरकारों को निर्देशित किया कि वे अपने यहां गल्ला वसूली करें। वस्तुतः गल्ला वसूली होर्डर्स, और जमाखोरों के खिलाफ डिक्लेरेशन आफ वार है। आपने कहा कि इस सरकार के समय में दाम बढ़ गये तो इससे तो किसानों को ही फायदा हुआ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस सरकार के समय में दाम बढ़ते थे तो उससे काश्तकारों को नुकसान होता था या और एस० बी० डी० की सरकार के समय में दाम बढ़ते हैं तो उससे किसानों को लाभ होता है। यह कौन सी लाजिक है?

श्री रामदत्त---

हम तो जानते ही हैं कि आप हमेशा से जखीरेबाजी के पक्ष में रहे हैं और आप आज भी घूम फिर कर उनका ही पक्ष लेते हैं।

श्री चन्द्रदेव (जिला देवरिया)---

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अभी एक माननीय सदस्य महोदय ने कहा कि इधर के लोग जखीरेबाजी के पक्ष में है तो क्या जखीरेबाजी जब यह कांग्रेस सरकार थी और उसने सिर्फ ढाई सौ मन रखने की इजाजत दी थी, तब थी या इस सरकार के जमाने में ज्यादा जखीरेबाजी है या यह लोग जखीरेबाज हैं जब इन्होंने १ हजार मन तक जखीरेबाजों को रखने की इजाजत दे रखी है?

श्री उपाध्यक्ष---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय जोशी जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री रामदत्त---

यह कहा गया कुछ जखीरेबाज इधर बैठे हैं। अगर यह बात भी मान ली जाय तो और भी हमें धन्यवाद देना चाहिये कि उनके खिलाफ हमने गल्ला वसूली की योजना को लागू किया है।

भूमिहीनों के लिये कहा गया कि बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। जब कांग्रेसी सरकार थी तब हम उधर बैठते थे और ये लोग इधर मूर्खों के स्वर्ग में विचरते थे। अपने प्रदेश में इन्होंने १८ स्टेट फार्म खड़े किये, हजारों हजारों एकड़ के। पूछा गया कि यह क्यों हो रहा है? तो कहते थे कि रूस, अमेरिका और कनाडा जैसे प्रगतिशील राष्ट्रों में ऐसे स्टेट फार्म हैं इसलिये हम भी स्टेट फार्म्स बनायेंगे। यह नहीं सोचा गया कि रूस का रकबा हिन्दुस्तान का ६ गुना है और आबादी आधी है, अमेरिका का रकबा ३ गुना है और आबादी हमारे से १/३ है। वहां जमीन खाली पड़ी है आदमी नहीं मिलते हैं यहां लाखों आदमी बेकार हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि फिर आप काहे के लिये सरकारी फार्म बनाते हैं। मेरी मांग है इस सरकार से कि भूमिहीन लोगों की समस्या का एक ही हल है और वह यह है कि जितने स्टेट फार्म हैं उस सबको तोड़ दिया जाय और उनकी जमीन का भूमिहीनों में बांट दिया जाय और इसके साथ ही छोटे-छोटे उद्योग पनपाये जायं ताकि हर एक को काम मिल सके और उसकी रोटी का सहारा हो सके। उस तराई भाबर के इलाके में कांग्रेस सरकार की बरपा की हुई लानत बाकी है। वहां की जमींदारी अभी बाकी है। वहां के किसान आज भी अपनी जमीन के मालिक नहीं है। यह मौजूदा सरकार उस लानत को खत्म करने के लिये सोच रही है। वह मलवा इतना इकट्ठा हुआ है कि उसको साफ करने में कई साल लगेंगे।

पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये एक एडवाइजरी बोर्ड बनाने की बात है। मैं सरकार को याद दिलाऊं कि पहले एक हिल डेवलपमेंट बोर्ड स्थापित करने की बात कही गई थी। गवर्नर साहब ने अपने भाषण में भी उसका जिक्र किया था। यह बात कही गई थी कि ३३ करोड़ रुपया दिया जायेगा फिर बाद को रिवाइज्ड करके ६० करोड़ रुपया उसके विकास के लिये रखा गया। इन्दिरा जी ने भी कहा था कि पर्वतीय क्षेत्रों की समस्या अलग है। उनका अलग नियोजन होना चाहिये और उनका अलग बजट होना चाहिये। इसके बिना वहां का विकास नहीं हो सकता है। वहां विकास करना इसलिये जरूरी है कि चीन की फौज का मुकाबला करना जरूरी है। इसलिये एडवाइजरी बोर्ड न बना कर उसको अधिकृत बोर्ड बनाया जाना चाहिये जिसको अधिकार हो कि वहां नियोजन में वह राय दे सकें जिसको सरकार माने और स्वीकार करे। कांग्रेस सरकार ने भी इसको स्वीकार किया है कि पिछले २० साल में कुछ गलत प्लानिंग रही जिसकी वजह से देश में कुछ गड़बड़ हुई और प्रदेश की हालत खराब हो गई लेकिन यह नहीं बताया गया कि प्लानिंग में क्या खराबी थी। पंडित जवाहरलाल जी ने पार्लियामेंट

में कहा था कि इन प्लानिंग की वजह से देश बहुत समृद्ध हो गया है और देश में दौलत बढ़ गई है। उनसे पूछा गया कि प्रधान मंत्री जी बताइये कि दौलत तो बढ़ी लेकिन वह दौलत कहां चली गई ? इसके बारे में एक जांच कमीशन बैठाना पड़ा। इस पर मुझे एक लतीफा याद आ गया। बादशाह अकबर ने एक तोता पाला था और उनका हुक्म था कि इस तोते के मरने की जो खबर देगा उसकी गरदन कलम कर दी जायगी। तो आप जानते हैं कि तोते की उमर ५, ६, ७ साल होती है। एक दिन ऐसा आया कि वह तोता मर गया। अब सारे महल में किसी को हिम्मत नहीं कि बादशाह सलामत को कोई खबर करे। अगर कोई आदमी खबर करता है कि तोता मर गया तो उसकी गरदन कलम कर दी जायगी। उस वक्त बीरबल की लोगों को याद आई कि वह बहुत होशियार आदमी है उसको भेजा जाय। बीरबल को बादशाह के पास भेजा गया। उसने जाकर बादशाह से कहा कि आपका प्यारा तोता दो दिन से कुछ खाता नहीं है। अपने पैर फैलाये पड़ा है। अपनी आंखें फैलाये हुये पड़ा है। चोंच भी फलाये हुये है। तो बादशाह ने कहा कि सीधे सीधे यह क्यों नहीं कहते कि वह मर गया। बीरबल ने कहा कि यह मैं कैसे कह सकता हूं। इसी तरह से मैं कांग्रेस वालों से पूछता हूं कि अगर दौलत बढ़ी है तो वह कहां चली गई ? दरअसल उनको मालूम है कि यह सारी दौलत पूंजीपतियों की जेब में चली गई जिसके प्रतिनिधि उधर बैठे हैं। यहां पर जो २० साल तक आप राज्य करते रहे हैं यह उनकी ही बदौलत हैं। २ महीने में उस पाप को धोया नहीं जा सकता है। इसके लिये कुछ समय चाहिये। हमारा पक्का इरादा है और हमने संकल्प किया है कि हम ७, ८ और ९ पार्टियां इस समय इकट्ठा होकर इस प्रदेश की सेवा करेंगी जब तक कि आपकी बरपा की हुई लानत का सफाया न हो जाय।

*श्री जगदम्बा प्रसाद --

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस सामान्य चर्चा में विचारों को व्यक्त करने के लिए मुझे समय प्रदान किया। बजट को पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वैसे तो पर्वतीय और पूर्वी दो हिस्से हैं जिनकी उन्नति के लिए सरकार अपने को प्रयत्नशील कहती है, लेकिन इस बजट में केवल पर्वतीय जिलों के लिए तो साधन हैं पर पूर्वी जिलों के लिए जिसमें फैजाबाद, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ हैं उनके विकास के लिए कोई योजना नहीं है। जब कि मौजूदा सरकार ने हमेशा इस बात को माना है कि पूर्वी जिले डेफिसिट एरिया हैं, नान-इरिगेटेड एरिया हैं और इस योग्य नहीं हैं कि अपनी आवश्यकता के अनुसार गल्ला पैदा कर सकें। ११२ ट्यूबवेलों की कुछ प्रदेश में व्यवस्था है जो बिल्कुल नगण्य है। पूर्वी क्षेत्र में मेरे इलाके में निरन्तर एक्जीक्युटिव इंजीनियर, सुडरिटेंडिंग इंजीनियर ने महसूस किया और कांग्रेस की सरकार ने और माननीय सिंचाई मंत्री भी मानते हैं कि उस एरिया में कोई भी सिंचाई के साधन नहीं हैं और ८ ट्यूबवेल स्वीकृत हो चुके हैं, सर्वे हो चुका है लेकिन अभी तक नहीं लगाये गये। इसलिए मालूम होता है कि विकास की तरफ कोई प्रगति नहीं हुई है और न कोई योजना है।

यह माना कि यह ५५ लाख सरप्लस बजट है, लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि विकास के साधन नहीं होने चाहिए। साथ ही अस्पताल और नये कारखाने खोलने चाहिए जिससे बेरोजगारी दूर हो सके, उसकी भी कोई व्यवस्था वहां के लिए नहीं है। मैं मुख्य मंत्री और मंत्रिपरिषद् के सदस्यों का ध्यान दिलाता हूं कि आपकी सरकार इस कमी के लिए उत्तरदायी है। पूर्वी जनता को कैसे जनतंत्र में आस्था और विश्वास पैदा हो सकता है जब कि आपने कोई कदम वहां उन्नति के लिए नहीं उठाया।

पहली अप्रैल को कांग्रेस की सरकार फेल हुई और नयी सरकार की स्थापना हुई और १९ सूत्री जो प्रोग्राम था उसमें मुख्य चीजें यह कही गयी थीं कि दसवीं तक लड़कों के लिए फीस माफ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदम्बा प्रसाद]

कर दी जाय। गवर्नमेंट स्कूल के अध्यापक और प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों का समान वेतन-क्रम होगा और निरन्तर आपकी ओर से सवालात होते रहे और भाषण होते रहे कांग्रेस के समय में बजट के अवसर पर कांग्रेस सरकार की इसी संबंध में आलोचना होती रही कि यह सरकार की बहुत बड़ी कमी है लेकिन आपने समान-वेतन-क्रम करने का कोई साधन उपलब्ध नहीं किया है।

तीसरी चीज मैं अलाभकर जोतों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। एस० एस० पी० के मैनीफैस्टो में यह है कि अलाभकर जोतों पर से लगान माफ होना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है।

भ्रष्टाचार को खत्म करने की भी बहुत सी बातें इस सरकार द्वारा कही जाती रही हैं। आपने एक संकल्प भी पास किया था। मगर आज वास्तविकता यह है कि नौकरशाही का जो रवैया पहले था वही आज है। नौकरशाही अभी भी सरकार पर हावी है। यह सरकार भ्रष्टाचार दूर करने में सफल नहीं हो पायी है। जहां, कुछ ऐसे आफिसर्स थे जिनके खिलाफ सतर्कता आयोग ने कुछ सिफारिशें की थीं, जिनको सुचेता सरकार और दास साहब ने दबा रखा था, उनके खिलाफ इस सरकार ने कार्यवाही की है। यह अच्छा काम है। मगर मैं इस सरकार का ध्यान हमारे सामुदायिक विकास मंत्री श्री जयराम वर्मा की ओर दिलाना चाहता हूं। फैजाबाद जिले के अकबरपुर ब्लाक में, जहां का ब्लाक प्रमुख इनके विपक्ष का है, वहां माननीय जयराम वर्मा जी ने, वहां के डेवलपमेंट कमिश्नर से टेलीफोन करके, वहां के ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० तथा अन्य अधिकारियों का ट्रान्सफर कराया है क्योंकि पिछले इलेक्शन में उन लोगों ने वर्मा जी की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया। जहां तक चुनाव का प्रश्न है, उ होंने चुनाव में भाग नहीं लिया था, मगर चूंकि उनके कहने के अनुसार काम नहीं किया, और चूंकि वहां का ब्लाक प्रमुख उनके विरोध में था, इसलिये तबादला करा दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन के रोजमर्रा के कामों में और मंत्रिगण इस तरह से हस्तक्षेप करेंगे तो इससे प्रशासन स्वच्छ नहीं रहेगा और आप भ्रष्टाचार को रोक नहीं पायेंगे। एक और उदाहरण अपने यहां का देना चाहता हूं। हमारे यहां एक झगड़ा हो गया, उसमें एक पक्ष के खिलाफ एस० डी० ओ० के पास हर हफ्ते वर्मा जी का टेलीफोन पहुंचता था कि उस पर चार्जशीट लगी या नहीं। एक तरफ आप भ्रष्टाचार को समाप्त करने की ओर कदम उठा रहे हैं, दूसरी ओर मामूली कामों में आप दखल देते हैं, इससे प्रशासन स्वच्छ नहीं होगा और भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। सरकारी कार्यों को सरकार को निष्पक्ष भाव से करना चाहिये, तभी प्रशासन में सुधार होगा।

यह ठीक है कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने डाक्टरों की लापरवाही को ठीक किया है। अस्पतालों में जहां डाक्टर बैठते नहीं थे, अब समय से बैठने लगे हैं। जहां तक इनके डिपार्टमेंट का सम्बन्ध है ये अपनी जगह पर अपना कर्तव्य ठीक समझते हैं। हमारे माननीय मंत्री जी ने इस दिशा में डाक्टरों को, जो ये समझते थे कि सरकार हमारी नौकर है, उन्हें यह समझा दिया है कि आप ही वाकई जनता के नौकर हैं। इन्होंने यह काम किया है। इसलिये आज डाक्टरों की हालत पहिले की बनिस्बत अच्छी है।

मैं अपने ही निर्वाचन क्षेत्र की बाढ़ के सम्बन्ध में बात कहना चाहता हूं। हम इस ओर बराबर सरकार का ध्यान दिलाते रहे हैं। वह क्षेत्र बाढ़ से पीड़ित है। उसकी तरफ राज्यपाल के सम्बोधन में अगर हमारे मंत्रिपरिषद, के सदस्य उस भाषण को पढ़ने का कष्ट करेंगे तो घसियारी मंडी, वाजिदपुर ऐसे गांव हैं जहां हमेशा बाढ़ आती है, इस बजट में उसकी तरफ कोई उल्लेख और ध्यान नहीं किया गया है।

कुछ जगहें वहां ऐसी हैं जहां बीमारी होने पर कोई भी दवा का साधन नहीं है। मैंने पहिले भी स्वस्थ्य मंत्री का ध्यान एक प्रार्थना-पत्र द्वारा दिलाया था कि वहां औषधालय खोलने का कष्ट करें। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दे दिया था पर इस बजट में उसका कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि वह आश्वासन केवल कागज पर ही रह गया है लेकिन वहां जनता के लिये कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से फिर उनका ध्यान दिलाना

चाहता हूं कि वहां एक औषधालय खोलने की व्यवस्था अवश्य करें जिससे वहां के लोगों का कष्ट दूर हो सके।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि वार्षिक आय-व्ययक के बारे में यहां पर माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। परन्तु इस समय यहां पर न माननीय वित्त मंत्री ही हैं और न मुख्य मंत्री ही हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रकार की व्यवस्था करें कि माननीय मुख्य मंत्री या वित्त मंत्री उपस्थित रहें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय प्रतापसिंह जी बड़े सचेत मंत्री हैं, वे उपस्थित हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, बात यह नहीं थी, बात तो इतनी थी कि न माननीय मुख्य मंत्री हैं और न वित्त मंत्री ही।

श्री भग्गूराम (उपनाम भृगुनाथ) (जिला वाराणसी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा चल रही है। यह बजट जैसा कि सामने आया है गरीबों के हित का बजट है। आज से बीस वर्ष पहले जो बजट पेश किये जाते थे उनको देख से ऐसा मालूम होता था कि वह बजट गरीबों का नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत के जा के बाद १९३६ में १२.३९ करोड़ का बजट था और बीस साल की कांग्रेस सरकार ने उसको बढ़ा कर गरीब जनता पर टैक्स लगा कर इतना अधिक कर दिया कि देश की हालत खराब हो गयी।

देश में आज भुखमरी का बोलबाला है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। हुकूमत के बदल जा पर विरोधी पक्ष के लोग यह सोच रहे हैं कि आज क्या करना चाहिये क्योंकि वे देख रहे हैं कि इस बजट के कारण और इस सरकार के लिये जनता में हर्ष छाया हुआ है। इसको देख कर कांग्रेस के लोग तिलमिला रहे हैं। क्योंकि २० वर्ष तक उन्होंने कांग्रेस के नाम पर राजसत्ता का सुख भोगा है और उसका यह नतीजा हुआ है। बहुत से विरोधी दलों के साथियों ने कांग्रेस को दुहाई दी और उन्होंने यह बताया कि उन लोगों ने ही अंग्रेजों को भगाया। लेकिन अंग्रेजों को भगाने में विरोधी पक्ष के लोगों का ही हाथ नहीं था, इधर के भी बहुत से माननीय सदस्यों ने उसमें भाग लिया था। जब इधर के बैठे हुए हम लोग रेल की पटरियों को हथौड़ा लेकर उखाड़ रहे थे, डाकखानों को लूट रहे थे, स्टेशनों को जला रहने के और इधर के बहुत से मिनिस्टर लोग जो स्थानों पर बैठे हैं जेलों में पड़े थे। ११ तारीख का वह दिन मुझे भूलता नहीं है जब ८ तारीख को हमें यह मालूम हुआ कि जयप्रकाश नारायण को फांसी का हुक्म हुआ है तो हम नौजवानों में गुस्सा की लहर दौड़ गयी। शाम होते होते हमारे हृदयों में धड़कन शुरू हो गयी और गिरोह बना कर निकल पड़े। ११ तारीख को मड़ुवाडीह स्टेशन को फूंका, नोटों को जलाया, मिट्टी के तेल को फूंका। हमारे जिले के कांग्रेसी सदस्यों को बुला बुला कर गिरफ्तार किया गया। सम्पूर्णानन्द जो भागे जा रहे थे उनको सारनाथ में जाकर गिरफ्तार किया गया। कमलापति जी तो बम्बई से आ रहे थे, इलाहाबाद में पुलिस को बुलवाकर अपने को गिरफ्तार करवाया। लेकिन आज आप कहते हैं कि हमने ही अंग्रेजी हुकमत को भगाया। आज जो लोग हुकूमत में आये हैं वे जनता के लोग हैं और उन्होंने जनता की निगाह से जैसा बजट बनाया जाना चाहिये, वैसा बनाया है। इससे गरीबों को राहत मिली है। २० वर्षों में कांग्रेस हुकूमत ने प्रदेश और देश की जनता में वैसा दर्द पैदा कर दिया था जैसा किसी इन्सान को चेचक हो गयी हो और उसके प्रत्येक फोड़े में नासूर हो जाय और उस प्रत्येक फोड़े के लिये एक एक डाक्टर की आवश्यकता हो। इसी प्रकार से जितनी बीमारी इस कांग्रेस सरकार ने पैदा कर दी हैं, उनके लिये एक एक डाक्टर की आवश्यकता है।

[श्री भग्गूराम]

आज प्रदेश में भुखमरी का बोलबाला है, भ्रष्टाचार जोरों पर है, चारों ओर त्राहि-त्राहि मची हुई है। कोई भी विभाग ले लीजिये ऐसी ही हालत है। सिंचाई विभाग का कोई भी इंजीनियर ऐसा नहीं है जिसका मकान न हो, ओवरसियर की अट्टालिका न हो। जो ट्यूबवल अंग्रेजी हुकूमत में १३ हजार रुपये में लगता था, कांग्रेसी हुकूमत में एक लाख रुपये में लगने लगा है। फजाबाद में इस कांग्रेसी हुकूमत ने एक जर्मन फर्म को ठेका दिया और यह शर्त हुई कि जहां ट्यूबवेल में पानी नहीं निकलेगा उसके लिये ११ हजार रुपये देने होंगे और इस प्रकार कर डों रुपया उस फर्म को दे दिया गया और वहां पर पानी नहीं निकला। आज जहां पर नलकूप लगे हैं, मैं चाहता हूं कि सरकार जांच करावे कि जर्मन की कम्पनी जो पहले की थी और जिसके जमाने में कांग्रेसी हुकूमत ने नलकूप लगाने का वादा किया था वह वहां लगे हैं या नहीं और जब वह कम्पनी चली गई तो वहां नलकूप लग गये। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन को २० साल तक यह ज्ञान नहीं था कि समाजवाद किसे कहते हैं, उनको इस की कोई जानकारी नहीं रही लेकिन उधर पहुंच कर अब उन्हें समाजवाद की याद आने लगी। पहले यह कहते थे कि समाजवाद किस चिड़िया का नाम है और आज वही समाजवाद की बात करते हैं। जब इनका अवाडी का सम्मेलन हुआ तो वहां पर प्रथम बार नेहरू जी ने समाजवाद का नारा लगाया। तब भी यह कहते रहे कि समाजवाद क्या है लेकिन उधर बैठने के बाद अब उनको समाजवाद की सुधि आई है। अब आप यह भी देखें कि आपने कैसे शासन चलाया था, समय आयेगा और आप देखेंगे कि आप की नीति का नतीजा क्या हुआ। समय आप को बतायेगा कि आपने क्या किया था और कितना प्रदेश का नुकसान किया है। सीता जी को हरने वाला रावण राक्षस था, सोन का मृग मारीच था, पहलाद को जलाने वाली होलिका भी राक्षसी थी और यह जनता जान गई है कि २० साल राक्षस तक किस किस राक्षस ने उसके ऊपर क्या अत्याचार किये हैं। चाहे आप कितने ही नारे समाजवाद के अब लगायें लेकिन जनता जान चुकी है कि उधर बैठने वाले वही प्रक्रियावादी लोग हैं जिन्होंने देश की जनता के खून को चूसा है और हड्डियों को चचोड़ा है। आज आपकी सत्ता समाप्त होने बाद जनता से मोह और प्यार पैदा हुआ है और समाजवाद की आप बात करने लगे हैं। आप घबरायें नहीं घबराने की कोई बात नहीं है। जिस चीज की बात आप करते हैं...

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

क्या यहां पर लिखा हुआ भाषण पढ़ने की अनुमति है?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य विषय से अधिक दूर न जायं।

(व्यवधान)

श्री भग्गूराम--

अभी सन् ५४ की बात है। नहर रेट के आन्दोलन को लेकर हम लोग ३५०० आदमी जेल गये और उसके फलस्वरूप ३ आने की उसम कमी हुई लकिन आप की हुकूमत ने किसानों की मर्जी के खिलाफ फिर उस रेट को बढ़ा दिया। इस हुकूमत ने लगातार २० साल तक जनता की नसों को सुखाया है और हड्डियों को सुखाया है। आपने विदेशों से भीख मांगने की आदत डाली और जो हमारे प्रदेश से भी छोटे देश हैं जावा और सुमात्रा तक से और बरमा से भी भीख मांग की और आप को शर्म नहीं आती। अगर आपने किसान को पानी खाद दिया होता तो आज यह हालत न होती और दूसरे देशों से अन्न न मंगाना पड़ता।

इस मौके पर मैं गोपालपुर सहकारी फार्म का भी जिक्र करूंगा। यह श्री कमलापति त्रिपाठी के रिश्तेदारों का दस हजार एकड़ का फार्म है और उसके नाम पर माननीय कमलापति त्रिपाठी ने करीब ७०--७५ हजार का लोन लिया है और केवल सौ सवा सौ एकड़ पर कोल और भी लड़ेती करते हैं। अगर यह दस हजार एकड़ जमीन गरीब किसानों को दी गई होती और उस पर

१ मन एकड़ भी गल्ला पैदा होता तो वह कितने फायदेमन्द बात होती। इस तरह से इन के जमाने में बराबर जनहित की हानि हुई है। मैंने गोरखपुर में मंसूरगंज और केम्पियरगंज के फार्मों को देखता हूं ५-५ और ६-६ एकड़ के फार्म हैं जिन पर कोई खेती नहीं होती और पटवारी को मिलाकर हर साल एक कोने से दूसरे कोने तक फर्जी परताल हो जाती है

आज यहां पर लगान समाप्त करने की बड़ी चर्चा है। हमारे सोशलिस्ट और संयुक्त विधायक दल के प्रोग्राम में है कि लगान समाप्त किया जाय मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि अलाभकर जोत से लगान समाप्त किया जाय इससे उनको ६ करोड़ की बचत होगी। अगर सारा लगान खत्म किया जाय और कृषि कर लगाया जाय तो २६ करोड़ के अतिरिक्त ३२ करोड़ की बचत होगी। अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि लगान खत्म करके बड़ी जोत पर कृषि कर लगाना चाहिये। इससे हमारे उत्पादन में उन्नति होगी। दूसरा काम सरकार को वह करना चाहिये कि जो बड़ी बड़ी जोतों वाले लोग हैं, उनसे भूमि लेकर जो हमारे खेतिहर मजदूर हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं हैं, उनको जमीनें दी जायं यदि ऐसा कर दिया जाय तो निःसन्देह पैदावार बढ़ेगी।

सिंचाई के बारे में पहली सरकार की जो योजनायें चल रही हैं, उनके बारे में सरकार को हिदायत की गयी थी कि आप इन साधनों से वांछित सिंचाई नहीं कर सकते और अन्न का उत्पादन नहीं हो सकता है। अगर पहली सरकार सर्वे करा लेती और उसके अनुसार सिंचाई के साधन बढ़ाती तो यह जो २० वर्षों में करोड़ों रुपया व्यय किया गया है, उससे प्रदेश सिंचाई का कोई दूसरा ही नक्शा होता। आज लोग भूखों न मरते। आज लोग कहते हैं कि मिर्जापुर में भुखमरी है। पहली अप्रैल को जब हम लोगों ने नवगढ़ और चकिया तहसील के बारे में उस समय सरकार से पूछा तो उस सरकार ने रिपोर्ट दी कि एक भी आदमी वहां पर नहीं मरा है। पन्नुगंज के एक सब इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट दी कि वहां पर १५ आदमी भूख से मरे हैं तो उसकी तनज्जुली कर दी गयी और उसको सेकिन्ड ओफिसर बना कर मिर्जापुर में रखा गया है। आज वह बेचारा ४ महीने की छुट्टी लेकर पड़ा हुआ है। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं इस सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इसकी पूरी जांच करके इस अधिकारी को, जिसके साथ इतना अन्याय हुआ है, फिर से बहाल किया जाय।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, मैं प्रस्तुत बजट का तो समर्थन नहीं करता परन्तु मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात के लिये अवश्य बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने २ करोड़ १७ लाख के घाटे को ५५ लाख बचत में दिखाने की कुशलता दिखायी है। मान्यवर, जब से यह सरकार बनी इसने कई तरह के काम किये है। सबसे पहले इस मंत्रिमंडल के मंत्रियों के विषय में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस सरकार के जो मंत्री है, उनके एक दूसरे के विचार अलग अलग हैं। वाराणसी में जो दंगा हुआ, उसके बारे में मान्यवर, माननीय रुस्तम सैटीन जी ने एक वक्तव्य में कहा कि अमुक वर्ग के लोग दोषी हैं, परन्तु वर्मेश्वर पांडेय जी ने कहा कि दूसरे वर्ग के लोग दोषी हैं। इसी तरह से मान्यवर, एक मन्त्री, माननीय प्रतापसिंह जी ने कहा कि हमारे प्रदेश की सीमा पर चीनी बड़ी संख्या में एकत्रित हैं और मुख्य मन्त्री जी ने उसका खंडन करते हुए कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रतापसिंह)--

श्रीमन्, माननीय चरणसिंह जी ने यह नहीं कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई सूचना नहीं है। यह नहीं कहा कि वहां पर कोई चीनी नहीं है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मन्त्रि मण्डल के सम्बन्ध में ऐसी संसदीय मान्यता है कि मन्त्री मण्डल की ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी होती है। एक बार नहीं, २ बार नहीं, ३-३ बार माननीय प्रतापसिंह जी इस

[श्री रामायण राय]

बात को दुहरा चुके हैं, समाचार पत्रों को भी दे चुके हैं और साथ ही इस समय भी सूचना दी है तो वह आश्चर्य की बात है कि उनके मन्त्रि मण्डल के एक सदस्य को यह जानकारी है परन्तु माननीय मुख्य मन्त्री को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। जिस राज्य के मुख्य मन्त्री को इस बात की सूचना नहीं है उनके मन्त्रिमण्डल के एक सदस्य बार-बार कह रहे हैं, उस राज्य का क्या होने वाला है इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री माताप्रसाद--

जब राज्य कर्मचारियों के वेतन के बारे में रिपोर्ट आयी तो उप मुख्य मन्त्री ने नेताओं को बुला करके यह कहा कि हम भविष्य में कुछ समय बाद, १०, १५ रोज बाद इस पर विचार करेंगे। उसके दूसरे दिन मुख्य मन्त्री का स्टेटमेंट हुआ कि इस तरह की कोई बात नहीं है। निर्णय फाइनल हो गया है, कोई तनख्वाह बढ़ने की बात नहीं है। इसी तरह से माननीय रामचन्द्र विकल और माननीय उदितनारायण शर्मा के विचार लगान के खत्म करने के बारे में एक दूसरे के विरोधी रहे हैं।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इस बजट में वित्त मन्त्री ने यह लिखा है कि ११२ नलकूप आगामी वर्ष में लगाए जायेंगे और कल माननीय टम्बेश्वरप्रसाद ने कहा कि ११० नलकूप लगेंगे। इनके मन्त्रियों को पहले चाहिए कि जो बात सरकार की ओर से कही जाय वह एक हो अन्यथा अलग-अलग मन्त्री अलग अलग बात करेंगे तो इस से जनता में भ्रम पैदा होता है। कहते हैं कि हमने १९ सूत्री कार्यक्रम को बजट में लिख दिया है। जाति सूचक नामों के बारे में कहा गया कि जिन शिक्षा संस्थाओं के सामने ऐसे नाम हों उन को हटाने के लिए आदेश दिए गए अन्यथा उन को मान्यता नहीं दी जाएगी, ग्रान्ट नहीं दी जायगी। इस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि मन्त्रि मण्डल के सदस्यों को ज्यादा अच्छा होता यह कदम पहले मन्त्रियों के नामों के बारे में उठाया गया होता। मान्यवर, हाथी के दांत खाने और और दिखाने के और हैं। पहले अपने नामों के आगे से जाति सूचक नाम हटाते तब स्कूलों के बारे में कहते। तो यह कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।

इसी तरीके से मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अखबारों में बहुत चर्चा आयी कि हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं को खत्म करने के बारे में सरकार सोच रही है। मैं इसका विरोध करता हूं। अगर इस तरह की चीज हो गई और जैसा कि सरकार सोच रही है कि शिक्षा संस्थाओं द्वारा परीक्षायें ली जायें तो गरीब लड़के जो हैं, या जिन की कोई सिफारिश नहीं होती है वे लड़के अच्छे नम्बरों से कभी पास नहीं हो सकेंगे। अध्यापकों की मैं इज्जत करता हूं लेकिन आज प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक जो वहां की प्रबन्धक कमेटियां हैं उनके चंगुल में किसी न किसी तरह रहते हैं और इसी तरह से बहुत से अध्यापक ट्यूशन करते हैं। तो अगर यह चीज हुई और स्कूल में परीक्षा लेकर सार्टिफिकेट देने लगेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि प्रबन्धक कमेटियों के दबाव में आकर वहां के अध्यापक के दबाव के कारण या जो अध्यापक किसी भी वजह से किसी विद्यार्थी से सम्बन्धित होंगे उनको अच्छे नम्बर मिल जायेंगे और गरीब लड़के फेल कर दिए जायेंगे या बहुत ही कम नम्बर से पास होंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा कि इस तरह का कदम न उठाएं इससे गरीबों का बहुत बड़ा अहित हो जायगा।

राज्य कर्मचारियों की बाबत बहुत बात कही गयी। जैसा आप श्रीमन्, जानते हैं यह रिपोर्ट आयी और गुप्ता जी के जमाने में आयी लेकिन उसके बाद कांग्रेस सरकार ही नहीं रही। अगर २, ४ रोज कांग्रेस सरकार रह जाती तो उस रिपोर्ट का प्रकाशन या घोषणा कांग्रेस सरकार कर देती। लेकिन मौका ही नहीं मिला। वह रिपोर्ट आयी लेकिन दूसरे दिन परिस्थिति बदल गई और वह रिपोर्ट उस दिन घोषित नहीं कर सके गुप्ता जी और माननीय चरणसिंह ने उस की घोषणा की। वह कहते हैं कि राज कर्मचारियों की तनख्वाह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो गई। यह तो एक तरह से सरासर धोखा है उन के साथ। अच्छा यह होता कि जितनी

तनख्वाह बढ़ायी गई थी उतना ही कहे होते कि इतनी बढ़ा रहे हैं और भविष्य में विचार करेंगे। लेकिन यह कहना कि उनकी तनख्वाह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर कर दी गई है यह सरकार उनको धोखा देना है और उन की आंखों में धूल डालना है। यह बात बिल्कुल गलत है कि राज कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सेन्टर के बराबर कर दिया गया है। उधर के लोग पहले जहां भी उनके प्रदर्शन होते थे उनकी मांगों का बड़े जोरों से समर्थन करते थे और जब उनको वह कार्य करने का अवसर मिला तो वह अपने वायदों से मुकर रहे हैं।

उधर से यह वायदा भी किया गया था कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जायगा और इसके लिए सरकारी स्कूल, गैर सरकारी स्कूल के अध्यापकों के वेतन एक कर दिए जायेंगे। जिला परिषद् के क्लर्क और पंचायतों के सेक्रेटरियों के वेतन भी बढ़ा दिए जायेंगे लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। लिहाजा ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कांग्रेस सरकार जिस प्रकार आर्थिक कठिनाइयों की बात कहती थी उसी प्रकार आप भी कह रहे हैं।

किसानों के लिए कहा गया कि उनको सिंचाई की सुविधा देने के लिए प्रदेश में साल भर में ११० नलकूप लगाए जायेंगे यानी एक जिले में दो नलकूप होंगे और कमांड एरिया ६०० एकड़ से घटा कर ३०० एकड़ कर दिया गया है। यानी एक जिले में साल भर में ६०० एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था होगी तो यह किसानों की सिंचाई की सुविधा दी जा रही है? वित्त मन्त्री वर्मा जी कहते थे कि हमें लूप नहीं नलकूप चाहिए लेकिन आज उनको भी लूप की जरूरत पड़ गयी है और वे भी इसका समर्थन करने लगे हैं।

एक बात के लिए मैं सरकार की जरूर तारीफ करूंगा। कांग्रेस के जमाने में भी यह बात चल रही थी कि लोक सेवा आयोग में एक हरिजन सदस्य नियुक्त किया जाय और गुप्ता जी ने भी इसको करने के लिए आश्वासन दे दिया था किन्तु राजनीतिक परिस्थितियां बदल जाने के बाद इस सरकार ने यह कार्य कर दिया है। गुप्ता जी ने ही इस कार्य को कर दिया होता लेकिन वह सरकार में नहीं रहे और इस सरकार ने उस कार्य को कर दिया इसके लिए यह सरकार जरूर बधाई की पात्र है। लेकिन दुख इस बात का है कि इस सरकार ने इतना बड़ा बजट बनाया लेकिन एक शब्द भी हरिजनों, अनुसूचित जातियों के लिए नहीं कहा। मैं चाहूंगा कि जिला स्तर पर जो चुनाव हों और जो कमेटियां बनाई जायं उनमें हरिजनों और अनुसूचित जातियों का भी प्रतिनिधित्व हो ताकि उनको संरक्षण मिल सके और नौकरियों में उनका संरक्षण पूरा हो सके जो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इसकी बहुत बड़ी आलोचना माननीय श्री मंगलदेव भी करते थे, दूसरे माननीय सदस्य भी करते थे। मैं समझता हूं कि अब-जब इनको मौका मिला है तो वे इस काम को तो जरूर कर दें।

एक चीज की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमें आशंका होती है कि ऐसा न हो कि भविष्य में यह सरकार जनता पर कोई टैक्स लगाए क्योंकि बजट में इन्होंने कहा कि बाकी ८ करोड़ ५० लाख रुपए का घाटा अतिरिक्त साधन जुटा कर तथा राज्य की हुंडियों को भुना कर पूरा करने का प्रयत्न किया जायगा। तो मैं चाहूं कि जब वे उत्तर देने लगें तो यह आश्वासन दें कि कोई भी टैक्स जनता पर नहीं लगेगा।

इसके अलावा भूमिहीनों को भूमि बांटने की बात १९ सूत्री कार्यक्रम में कही गयी है लेकिन इसका भी जिक्र बजट में कहीं नहीं किया है। भूमिहीन खेतिहर मजदूर या शहरों में जो दूसरे काम करने वाले मजदूर हैं उनके भविष्य में तो इस सरकार ने बिल्कुल आंख मूंद ली है और बजट में इसका भी कोई जिक्र नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि सरकार की कथनी और करनी में जो फर्क है उसको कर के दिखाइए और जिन चीजों के लिए सरकार ने वायदा किया है उसको पूरा करके दिखाइए, आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आप यह नहीं करते हैं तो आप जनता को बहुत बड़ा धोखा देते हैं। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

मिर्जापुर जिले में भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ के अन्तर्गत मेरे पास पांच सूचनायें आयी हैं। इसमें एक है माननीय अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' की। इसमें उन्होंने कुछ मिर्जापुर जनपदमें भूख से मौतों का सिलसिला जारी है, लिखा है। अभी हाल में सात मौतें हुई हैं। समस्या अकाल क्षेत्र न घोषित करने से बड़ी विषम हो गयी है। क्योंकि कल ही माननीय राकेश जी को बोलने का अवसर मिला था और वाद-विवाद चल रहा था तो मैंने इस पर केवल इतना ही किया है कि मन्त्री महोदय को आवश्यक कार्यवाही के लिए और सूचना के लिए प्रसारित कर दिया है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

अकाल की घोषणा का प्रश्न है, सही बात है। सरकार को इसे मानना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

वह आपकी बात ठीक है लेकिन एक अवसर कल ही मिल चुका है माननीय राकेश जी को। उस समय भी वह अकाल की बात कर सकते थे और की भी थी उन्होंने। क्योंकि यह सब चर्चा हो चुकी और आज प्रश्न और है। कल माननीय गेंदासिंह ने जो दिया था वह भी मिला-जुला इसी स्थिति से सम्बन्धित है.....

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

जो आज्ञा है वह तो शिरोधार्य है लेकिन अगर उसको पूरा पढ़ दिया जाय तो हम लोग को मालूम हो जाता कि किस पैमाने पर लोग भूखों मर रहे हैं और राकेश जी ने जो सदन सूचना दी है उससे सदन अवगत हो जाता।

श्री अध्यक्ष--

नियमों में यह है कि जो नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें आयें उनको साधारणतया पढ़ना आवश्यक नहीं है लेकिन मैं ऐसा करता रहा हूं और करूंगा भी कि कोई सूचना जो मुझे इस योग्य लगे कि जिससे सदन को अवगत कराऊं तो उसको पढ़ भी दूंगा.....

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)--

अगर आप मौका दें तो जैसा माननीय सदस्य ने कहा, एक मिनट के लिए उस सारी जानकारी से मैं सदन को अवगत करा दूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं अधिक से अधिक इतना मौका दे रहा हूं कि बजाय इसके कि आप अपने मुखारविन्द से कष्ट करें मैं आपके द्वारा जो लिखित सूचना है उसको पढ़कर सदन को अवगत कराए देता हूं। वह इस प्रकार है कि--

"मिर्जापुर जनपद में भूख से मौतों का सिलसिला जारी है। सरकारी सद्प्रयासों के बावजूद, वितरण व्यवस्था में व्यतिक्रमों के कारण साथ ही सरकार द्वारा युद्धस्तर पर समस्या समाधान करने के लिए अकाल क्षेत्र न घोषित करते हुए टालमटोल और निश्चय विहीनता की नीति से अत्यन्त क्षोभ व्याप्त है। जिला स्तरीय प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य मन्त्री महोदय के समक्ष भी प्रदर्शन हुए किन्तु अभी तक कोई ठोस कार्यवाही अनेक प्रखंडों में न हो सकी। अभी हाल में सात मौतें भूख से हुईं। अतएव उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मुख्य मन्त्री महोदय का तथा सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

मैं इतना और बता दूं कि वहां ७ मौतें हुई हैं उसके सम्बन्ध में सूचना और संकलित कर लें तब सदन के सामने आयें। अभी तो सूचना का कुछ आधार नहीं दिया है।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वदी 'राकेश'—

श्रीमन्, अगर मैं मरने वालों की सूचना देता रहूं और लाशें इकट्ठा करता रहूं तो एक दिन ऐसा आ जायगा....

श्री अध्यक्ष—

लाशें न लाइए केवल सूचना दीजिए।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि माननीय राकेश जी सदन और प्रदेश के धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि यह सवाल ऐसा है कि इस पर जितनी जल्दी से जल्दी विचार किया जा सके उतना ही उचित है। मैं तीन दिन से बहस सुन रहा हूं। दो करोड़ आदमी आधे पेट रहकर गुजर कर रहे हैं उनकी तरफ न तो सरकार का कुछ ध्यान है और न दूसरे लोगों का है। राकेश जी का जो प्रश्न है उसको जितनी अहमियत दी जा सके दी जानी चाहिए। श्रीमन्, खाली मिर्जापुर की ही यह कैफियत नहीं है बल्कि बड़े भारी पैमाने पर सारे सूबे में यही स्थिति है और हम लोग मुंह बन्द करके बर्दाश्त कर रहे हैं।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय राकेश जी ने जो सूचना दी है उसके लिए थोड़ा सा समय हमें दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

जिन्होंने सूचना दी है उनको मैं अवसर नहीं दे रहा हूं तो आपको अवसर देने का प्रश्न कहां ह ? माननीय गेंदासिंह जी और कई सदस्यों ने और खास तौर से राकेश जी ने इसके महत्व पर बहुत जोर दिया है। मन्त्री जी यहां बैठे हैं, मैंने सूचना के रूप में तो इसे स्वीकार नहीं किया है लेकिन सदन की भावना को देखते हुए अगर वह कोई वक्तव्य देना चाहें तो उसके लिए कोई समय बता दें।

कृषि मन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—

श्रीमन्, अगर आपकी आज्ञा हो तो वक्तव्य दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

मेरी अनुमति तो है इसमें....

श्री जयराम वर्मा—

तो २६–२७ रख लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, २७ रही वक्तव्य के लिए।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कृपया अवसर दें। मिर्जापुर के सम्बन्ध में जब माननीय मंत्री जी वक्तव्य दे रहे हैं तो समूचे पूर्वी जिलों में जिनमें फैजाबाद, बनारस, गोरखपुर और इलाहाबाद डिवीजन के जिले, पहाड़ी जिले सभी जिले शामिल किये जायं, क्योंकि हालत बहुत खराब है। मैं पहले दिन उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता था लेकिन शायद मैं अपने प्रश्न को उतना महत्व नहीं दे पाया मैं आज फिर आप की कृपा चाहता

[श्री कल्पनाथ सिंह]

हूं, इस सम्बन्ध में आपकी अनुज्ञा चाहता हूं कि मंत्री जी से आप केवल एक बयान जुड़वा दें कि गोरखपुर, फैजाबाद और बनारस डिवीजन के सभी जिलों और इलाहाबाद और बांदा वगैरह सब जिले जहां पर अकाल की हालत है जहां पर लोगों का जीवन दूभर हो रहा है उन सभी जिलों को मंत्री जी के वक्तव्य में सम्मिलित करवा दें।

श्री राममरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---

इसमें प्रतापगढ़ का नाम कहीं नहीं आता न पूर्व में न कहीं।

श्री अध्यक्ष---

यह जो बजट पर विवाद चल रहा है इसमें अलग-अलग मदें सदन के सामने आयेंगी। एक मद तो बिलकुल खालिस ऐसी है जिसमें इस विषय पर आप को चर्चा करने का समय मिलेगा और खास तौर से विरोधी दल को पूर्ण अधिकार होता है कि किस मद पर बहस हो और किस पर न हो। उसको आप देख सकेंगे। एक वह अवसर होगा। मेरे सामने जो प्रश्न था उसके सम्बन्ध में उनको कहा। वह सारी बातें सुन रहे हैं। उसके बाद यदि वह और सूचना देना चाहेंगे तो देंगे।

नियम ५१ के अन्तर्गत आध घंटे का विवाद होता है, आध घंटे इस प्रक्रिया में लग चुका। इसलिये इतना पर्याप्त है। माननीय मंत्री २७ तारीख को सम्भवतः स्टेटमेंट देंगे उस वक्त बात कर लीजियेगा।

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)---

आपने इस सम्बन्ध में एक दिन का समय दिया था।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'---

मैं कुछ स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। मेरी बात को सिर्फ राजनीतिक चर्चा का विषय न बनाया जाय। मेरी जो भावना है उसको भी उसके साथ जोड़ दिया जाय। यह स्पष्ट कर दिया जाय कि जो भी माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें कम से कम इस प्रकार की सूचना मंगवा लें कि जो सद्प्रयास सरकार की ओर से हो रहे हैं उनके बावजूद वितरण व्यवस्था में क्या दोष है और इसके लिये कौन से लोग दोषी हैं। वही पुराने मरीज जो २० साल से चले आ रहे हैं जो भूखों की लाशों पर अपनी रोटियों को सेंक रहे हैं, जेबों को भर रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाहियां की जायं वरना राजनीतिक हथकंडे चलते रहेंगे और वर्तमान स्थिति में कुछ हो नहीं पायगा। यह प्रश्न राजनीतिक चर्चा का विषय न बनता तो अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष---

सदन में जो बात आती है वह चर्चा का विषय बनती है। मैं कह रहा था कि आप न कहें। आपने और तरह से भाषण दे दिया।

खैर, माननीय सदस्य का जो एक दिन की चर्चा के लिये गालिबन जो उनका संकेत था अजंडे के उस आइटम की ओर, जो तीन अप्रैल को अवशिष्ट था, उसके बारे में मैंने आज अपराह्न मैंने माननीय मुख्य मंत्री से बात की थी। उन्होंने यह अनुमति दी कि दो, तीन, चार दिन में उस पर समय निश्चित कर देंगे, कि कौन सी तारीख होगी। २६ तारीख को घोषणा कर देंगे कि कौनसी तारीख होगी। लेकिन इस मिर्जापुर वाले मामले में चर्चा हो जायगी। वह दोनों वक्तव्य एकदिन में करवा देंगे।

इसके बाद शेष जो सूचनाएं नियम ५१ के अन्तर्गत आयी हैं उनको अस्वीकार कर दिया है।

श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, एक दफा ५२ का मैंने भी दिया था। काउन्सिल हाउस के दरवाजे के सामने १६ तारीख से मुजाहरा कर रहे हैं। हालत यह हो गयी है कि आज के अखबारों में निकला है कि ६ आदमियों ने इजाजत मांगी है उस समिति से जो आन्दोलन कर रही है कि हम को इजाजत दी जाय, हमारी डिमांड्स जैसा कि संयुक्त विधायक दल ने वादा किया था उसके बावजूद उर्दू को दूसरी जबान मानने के सिलसिले में मंजूर नहीं करते। तो हमें इस बात की इजाजत दी जाय कि हम अपने आप को आग में जला लें। इस प्रदेश के लिये...

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

श्री जियाउर्रहमान—

मैं यह चाहता हूं कि दफा ५२ के सवाल के लिये इस प्रदेश के....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर के अपना स्थान ग्रहण करें। देखिये ऐसा है कि हर एक माननीय सदस्य जब कोई प्रश्न मेरे सामने भेजता है तो जरूर यह समझ कर भेजते हैं कि यह बहुत जरूरी है जनहित में है और उसका महत्व है। लेकिन मुझे भी नियम की कसौटी पर उसे देखना पड़ता है उसकी इम्पार्टेंस अपेक्षाकृत देखना पड़ता है। मैं यह साफ कर दूं कि मैं सदन में यह परम्परा नहीं डालना चाहता कि जिन माननीय सदस्य का प्रश्न स्वीकार न हो वे खड़े होकर उसका कारण मुझसे पूछें और मैं उनको समझाऊं। यदि कोई कारण पूछना चाहते हैं तो वे कृपा करके मेरे कार्यालय में पधारने का अनुग्रह करें, मैं कोशिश करूंगा कि उनको मुतमईन कर सकूं। इस समय जो हमारी प्रक्रिया नियमावली है उसके अनुसार मैं मजबूर था उसको अस्वीकार करने क लिये।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक प्रश्न भेजा था आपके पास। बैसे जो आपने आज्ञा दी वह तो मुझे शिरोधार्य है.....

श्री अध्यक्ष—

तो इस बात में आप मेरी मदद करें।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, मैं मदद ही कर रहा हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो माननीय जयबहादुर सिंह एम० पी० के सम्बन्ध में था, तो कृपा करके उसे आप स्वास्थ्य मंत्री के पास ही भेज दें।

श्री अध्यक्ष—

वह मैंने कर दिया है। उस आवश्यकता को मैं अनुभव करता हूं। किसी एम० पी० या किसी नागरिक की चिकित्सा सम्बन्धी सहायता रुकनी नहीं चाहिये। इसकी आवश्यकता को मैं भी समझता हूं और उसे मैंने स्वास्थ्य मंत्री के पास भेज दिया है।

खरीफ की बोवाई के लिये बीज के अभाव के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब आइटम नंबर ९ के अन्तर्गत खरीफ की बोवाई के लिये बीज के अभाव के सम्बन्ध में श्री गेंदा सिंह तथा श्री जितेन्द्र नाथ मिश्र द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य होगा।

कृषि उप मन्त्री (श्री रूप नाथ यादव)---

सिंचित क्षेत्रों में खरीफ की बुवाई प्रारम्भ हो गई है। असिंचित क्षेत्रों में बुवाई वर्षा प्रारम्भ होने पर ही चालू हो सकेगी। सरकार सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति से भली भांति अवगत है। सरकार ने बीज की आवश्यकता ज्ञात करने के लिए प्रत्येक मंडल में अपने अधिकारी भेज कर बीज की आवश्यकता का सर्वेक्षण करा लिया है और जिन जिलों में बीज की कमी पाई गयी वहां पर आवश्यकतानुसार बीज उपलब्ध करा दिया गया है। उन अभा ग्रस्त क्षेत्रों के लिये जहां कि सूखे का अधिक प्रकोप है, बिशेषरूप से अधिक मात्रा में बीज उपलब्ध करने की व्यवस्था कर दी गयी है।

सरकार काअनुमान है कि बड़े-बड़े किसानों के पास अपने-अपने बोने के लिये बीज का पर्याप्त प्रबन्ध रहता है। इनमें से कुछ किसान छोटे किसानों को भी बीज बांटते हैं। ऐसी स्थिति इस वर्ष भी है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के छोटे-छोटे किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध कराने की दृष्टि से ५ एकड़ या उससे कम जोत वाले किसानों को ही बीज देने का प्रबन्ध किया गया है। लकिन मिर्जापुर तथा इलाहाबाद जिले की करछना तथा मेजा तहसीलों के लिये यह सुविधा १० एकड़ तक के जोत वाले किसानों के लिये कर दी गयी है ?

सरकार ने काफी मात्रा में ८२.९० लाख रुपये की आपत्तिकालीन तकावी (Distress Taccavi) विभिन्न जिलों में उपलब्ध कर दी है। यह तकावी मुख्यतया बीज के लिये दी जायगी। किसान बीज किसी भी जगह से क्रय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ३० लाख रुपए की व्यवस्था अधिक उपज देने वाली फसलों के बीज की तकावी के लिये भी कर दी गयी है। किसान इस तकावी से भी लाभ उठा सकते हैं।

यथासम्भव सरकार का प्रयत्न है, और रहेगा, कि कोई भी कृषि क्षेत्र बीज की कमी के कारण, बिना बोये न रहने पाये।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---

क्या सरकार ने इन क्षेत्रों का कुछ विवरण भी इकट्ठा किया है कि कितने क्षेत्र में बीज की कमी पड़ेगी और कितना बड़े किसानों से बीज मिल जायगा और कितने बीज का बन्दोबस्त सरकार ने किया है ? यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या बन्दोबस्त किया है इस पर माननीय कृषि मंत्री जी कुछ रोशनी डालने की कृपा करेंगे ?

कृषि मंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

वैसे तो आवश्यकता थोड़ी बहुत हर जगह हो सकती है और उसका कुछ प्रबन्ध भी किया गया है। लकिन उन जिलों के लिए जहां पर खासतौर पर सूखे का प्रभाव रहा है, बीज इकट्ठे करने की व्यवस्था की गयी है। वे स्थान हैं--वाराणसी जिले की नौगढ़ तहसील, मिर्जापुर जिले के ४ ब्लाकों को छोड़ कर शेष इलाहाबाद की मेजा व करछना तहसीलें और बांदा जिला है। इन स्थानों के लिए खास करके बीज की कमी को पूरा करने के लिये प्रयत्न किया गया है। इस वक्त हमारे पास से प्रदेश भर के लिए कृषि विभाग की तरफ से ७५ हजार क्विंटल बीज का इंतजाम हो गया है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

जो बीज के सम्बन्ध में आदेश भेजे गये हैं, उसमें यह है कि मिर्जापुर के करछना तहसील के अतिरिक्त जो अन्य सूखा ग्रस्त इलाके हैं उनमें सदा पांच एकड़ से कम काश्तवालों को ही दिया जाएगा और जो उसके ऊपर के किसान हैं और जिनकी फसल सूख रही है उनके लिये सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री जयराम वर्मा---

कृषि विभाग आमतौर से नार्मल बीज का कभी इंतजाम करता नहीं। लेकिन इस बार यह देख कर असाधारण स्थिति पैदा हो गयी है तो जहां हो सक नार्मल बीज का प्रबन्ध कर दिया

जाए और जहां तक हो सकेगा उसको बीज हम देंगे जिससे उनका कोई खेत बिना बीज बोए पड़ा न रहे। वैसे तो थोड़ी-थोड़ी जरूरत हर जगह है। और जगहों से भी उनको जरूरत मंगाई गई है जिनके लिये बीज की आवश्यकता पड़ेगी। उसे भी यदि माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो बता दिया जाएगा।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)--

मेरा विचार है कि मिर्जापुर जिले में प्रायः प्रत्येक किसान को बीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या माननीय मंत्री जी यह हमें आश्वासन देंगे कि उन सब किसानों को बीज दिया जा सकेगा ?

श्री जयराम वर्मा--

यह कभी तो किया नहीं गया, लेकिन वहां से जो जरूरत के आंकड़े मंगाये गये हैं और जिसे वहां के जिला मैजिस्ट्रेट ने भेजा है उसमें यह है कि २५,५०० क्विंटल बीज की आवश्यकता पड़ेगी। किन्तु इसके विपरीत वहां के दूसरे लोग कहते हैं कि ये आंकड़े बहुत ज्यादा रखे गये हैं, इतने बीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी उनकी जरूरत की मांग के अगेन्स्ट हमने १८ हजार क्विंटल का इंतजाम कर लिया है। और फिर अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो उसका भी इंतजाम करने का प्रयास किया जाएगा।

श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)--

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि हमारे जिले के लिये उन्होंने क्य सोचा है वहां भी जरूरत पड़ेगी, वहां आपने देख भी लिया है और वहां पर माफी भी दी है? दूसरी बात यह है कि आज किसान को सबसे बड़ी जरूरत जानवरों की है। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास जानवर नहीं हैं और बिना जानवर के वे बीज नहीं बो पाएंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप बीज और जानवर एक में क्यों मिला रहे हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी को यह सूचना है कि मिर्जापुर जिला और मेजा और करछना तहसील तो भुखमरी के प्रतीक बन गये हैं और सही है लेकिन पूरब के बहुत से जिले हैं जैसे गाजीपुर में भिटौरा क्षेत्र समिति में ५० गांव ऐसे हैं जहां ३ साल से सूखा पड़ा है और एक एकड़ धान भी वहां नजर नहीं आया जो खरीफ की फसल बीती है और वहां डेढ़ रुपये दो रुपये किलो तक धान का बीज उपलब्ध नहीं है। आपने आदेश दिया कि १ बीघा या ५ बीघा तक जिनके पास जमीन है उनको ही बीज सप्लाई करेंगे तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे वहां बोआई हो सके ?

श्री जयराम वर्मा--

पांच एकड़ की बात है। गाजीपुर के लिये जो आंकड़े हैं उनके अनुसार वहां २३५० क्विंटल की जरूरत है और २,३२३ क्विंटल का इन्तजाम किया जा चुका है।

श्री शब्बीर हसन--

मैं पूछ रहा था कि हमारे जिले फतेहपुर का नाम नहीं आ रहा है। मंत्री जी वहां गये थे वहां गंगा और जमुना के बीच की हालत बहुत खराब है, अगर वहां बीज नहीं पहुंचा तो बोआई कैसे होगी ?

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि हमने सभी जिलों के लिये आदेश कर रखे है कि जितना भी वहां लोकली बीज मिल सके प्रोक्योर किया जाय। फतेहपुर जिले के आंकड़े मेरे पास नहीं है। आंकड़े मेरे पास सिर्फ उन जिलों के हैं जो खासतौर से सूखे से प्रभावित है।

श्री गेंदा सिंह--

५१ से ७५ फीसदी तक जिलों में खरीफ की फसल बहुत जिलों में नष्ट हुई थी। वहां का बीज इस्तेमाल नहीं होना चाहिये क्योंकि वह काम के लायक नहीं होगा। मैंने तो उसके लिये दूसरा उपाय सोचा था लेकिन अब वह चाहे जैसा करें। ५१ से ७५ तक जहां नष्ट हुआ है वह १७ या १८ जिले हैं। यह अकाल पीड़ित स्थान है वहां तो होना चाहिये लेकिन बहुत से जिले ऐसे हैं जहां कितनी बीज की व्यवस्था है जरा तफसीलवार बतला दें तो कृपा होगी ?

श्री जयराम वर्मा--

हमने तो सभी के लिए कहा है कि उस जिले या बगल के जिले से जहां से काम चल सकता हो वह खरीदा जाय। पिछले साल कुल ३५ हजार क्विंटल बीज दिया गया था इस साल ७५ हजार क्विंटल का इंतजाम कृषि विभाग से हम कर चुके हैं। इससे हम समझते हैं कि कमी नहीं पड़ेगी और अब भी कोशिश की जा रही है कि जो बीज मिल सके वह लिया जाय। ख्याल यह है कि जो काश्तकार बड़े हैं उनके पास होगा वह खुद बोयेंगे और दूसरों को देंगे। छोटे काश्तकारों को कितनी आवश्यकता होगी उसको देख लिया गया है और उसके लिये व्यवस्था करने की कोशिश की गयी।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)--

मंत्री जी ने बताया कि उन जिलों के आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं जहां सख्त जरूरत है। मैं यह जानना चाहता हूं कि गाजीपुर जिले में जमानिया और दूसरे इलाकों में जहां रबी और खरीफ की दोनों फसलें मारी गयीं और इसीलिये लेवी वहां नहीं वसूल की गयी है तो अब उन्होंने खरीफ आ रही है तो क्या उस समय के लिये इस इलाके के लिये बीज का कोई इंतजाम किया है क्योंकि जिलाधीश से बातचीत करने पर वह कहते हैं कि पता नहीं है कि कितना बीज जिले को मिल पायेगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उस जिले के लिये कितने बीज का इंतजाम किया है ?

श्री जयराम वर्मा--

गाजीपुर के बारे में मैंने बता दिया। गाजीपुर की जरूरत जो जिला मैजिस्ट्रेट ने भेजी है वह २३५० क्विन्टल है और २३२३ क्विन्टल का इन्तजाम हो गया है।

श्री प्यारे लाल--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पिछले साल कितने बीज का इन्तजाम जिलों के लिये किया गया था और इस वर्ष कितने क्विन्टल बीज का इन्तजाम किया गया है ?

श्री जयराम वर्मा--

पिछले साल ३५ हजार क्विन्टल का इन्तजाम कृषि विभाग से किया गया था और इस वर्ष ७५ हजार क्विन्टल का इन्तजाम किया गया है।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)--

मैं माननीय कृषि मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी उन्होंने इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील का जिक्र किया है कि वहां जिलाधीश महोदय ने कुछ बीज के लिये मांग की

है। इस तहसील को पूरा सूखा क्षेत्र घोषित किया गया है। यह ठीक है कि वहां बीज दिया जाय लेकिन चाइल, मंझनपुर, दोआबा और सिराथू क लिये जिलाधीश ने कोई मांग की है या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा--

जिला मैजिस्ट्रेट ने जिले की आवश्यकता क्या होगी यह बताई है। उन्होंने ८,५०० क्विन्टल की आवश्यकता बताई है। यह पूरा इन्तजाम हो गया है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--

गतवर्ष मन्त्री जी सूखे की स्थिति को देखने के लिये बस्ती गये और मेरे साथ इलाके को देखा था कि सारी फसल मारी गई है। वहां पर धान की फसल थी वह सब मारी गई थी जहां से चावल सप्लाई हुआ करता था। क्या वहां के लिये कुछ प्रबन्ध किया गया है और कितना बीज लेट पैडी अर्ली पैडी के लिया दिया गया है ?

श्री जयराम वर्मा-

जी हां, बस्ती के लिये इन्तजाम किया गया है। सब जगह से मेरे लिये आंकड़े मंगाना मुश्किल था। कम समय था लेकिन जितने मिल सकते थे उनको प्राप्त किया है। आज ही यह बयान देना था। इतने कम समय में सब जगह से आंकड़े मंगाना मुश्किल था।

श्री कृष्णानन्द राय--

मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो आंकड़े मंगाये हैं वह क्या इस आधार पर भेजे हैं जिन किसानों के ५ एकड़ से कम खेत हैं उनको बीज दिया जायगा या जिन किसानों के १० एकड़ या २० एकड़ के खेत हैं और जो बिलकुल सूख गये हैं उनके आंकड़े मंगाये हैं ? इस भ्रम को दूर कर दें कि वह किन के लिये आंकड़े बता रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा--

ये आंकड़े ५ एकड़ के हिसाब से मंगाये गये हैं। मैं यह बात भी बतला दूं कि मैं गाजीपुर गया था तो मुझे यह बात कही गई कि यहां पर आमतौर पर सभी काश्तकार ५ एकड से कम के हैं। इससे अधिक बहुत थोड़े काश्तकार होंगे जो १५ एकड़ से ज्यादा वाले हैं, जो ज्यादा वाले हैं उनके पास अपना बीज मौजूद होगा।

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, हमारे बस्ती जिले में लगातार दो वर्ष से खरीफ की फसल नष्ट हो गई है। हम लोग जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं उनके यहां एक सेर भी लेट पैडी नहीं हुआ है। वहां के लिये क्या प्रबन्ध हुआ कोई निश्चित बात बतलाई जाय। कोआपरेटिव स्टोर ने जितना बीज काश्तकारों को दिया था उसमें एक सेर लेट पैडी का बीज उनके यहां वापस नहीं आया। ५ एकड़ के काश्तकारों का तो आपने इन्तजाम तकावी का कर दिया है लेकिन वह काश्तकार रुपया लेकर कहां जायेंगे जिनकी खरीफ फसल में एक दाना भी पैदा नहीं हुआ है। पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ है तो वहां पर क्या इन्तजाम किया गया है।

श्री अध्यक्ष--

किसी एक जिले से संबंधित जो बात है वह तो प्रश्न के उत्तर में आ सकती है लेकिन हर एक जिले के लिये अगर प्रश्न पूछा जायगा तो वह मुश्किल होगा। यदि मंत्री जी बता सकते हों, तो बता दें।

श्री जयराम वर्मा--

बस्ती के लिये इन्तजाम किया गया है। बस्ती के लिये कितनी मांग है और कितना हमारी तरफ से इन्तजाम किया गया है मैं यह जवाब नहीं दे सकता हूं। कोआपरेटिव विभाग का जितना बीज है उसका उसने इन्तजाम किया होगा और हर साल वह करता है। यह संभव हो सकता है कि कोआपरेटिव विभाग के पास ज्यादा बीज न हो। यह बात उनकी सही हो सकती है लेकिन हमने कोआपरेटिव विभाग के अलावा इन्तजाम किया है। बस्ती में इन्तजाम हुआ होगा। मेरे पास उसके आंकड़े इस समय नहीं हैं।

माननीय सदस्य देखना चाहेंगे तो मैं मंगा कर उनको दिखा दूंगा।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिलों से जो मांग आयी थी क्या उस सबकी पूर्ति हो चुकी है या नहीं क्योंकि मेरी सूचना यह है कि बीज बीज गोदामों तक नहीं पहुंचा है।

श्री जयराम वर्मा--

इस वक्त ७५ हजार क्विन्टल्स का इन्तजाम सारी स्टेट के लिये कर दिया गया है। पिछले साल केवल ३५ हजार क्विन्टल का ही था। इसके अलावा हम १३ लाख एकड़ में अधिक उपज वाली फसलें उगाना चाहते हैं। उसके लिये बीज अलग होगा उसके लिये पूरा बीज हर जिले में पहुंच चुका है।

श्री चन्द्र शेखर (जिला वाराणसी)--

वाराणसी जिले की चंदौली और चकिया तहसील के लिये कितने धान बीज की आवश्यकता है और कितना पहुंच चुका है?

श्री जयराम वर्मा--

वहां की मांग १० हजार क्विन्टल की थी, इस वक्त ५ हजार १३ क्विन्टल पहुंच चुका है, १,६०० क्विन्टल का इन्तजाम और होने वाला है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह बीज जो दिया जाता है वह सवाई पर दिया जाता है या कीमत पर अगर कीमत पर तो किस भाव से?

श्री जयराम वर्मा--

कृषि विभाग से उनको तकावी मिलती है उससे वे बीज लेते हैं। जिस भाव पर हम एफ० ए० क्यू० फेयर एवरेज क्वालिटी का बीज खरीदते हैं उस बीज पर क्वालिटी मार्जिन हम २-४ रुपये प्रति क्विन्टल्स तक देते हैं। इसके अलावा इस पर हम साढ़े १२ परसेंट प्रीमियम देते हैं। प्रीमियम मैक्जिमम ८.०४ रुपया पड़ता है। ताइचूंग नेटिव नं० १ पर हम २५ परसेंट प्रीमियम देते हैं क्योंकि यह नयी क्वालिटी है। इस पर कास्ट प्राइस पर हम ४ परसेंट का ओवरहेड चार्जेज लगाते हैं। इस के अलावा अलग-अलग बीजों की अलग अलग कीमतें हैं, वह कैसे एकदम बतायी जा सकती हैं।

श्री दुर्गाप्रसाद (जिला खीरी)--

क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में मछलीशहर और मड़ियाहूं तहसील जो तीन साल से सूखे से पीड़ित हैं और जिलों के अन्य भागों में जो सूखा पड़ा है वहां के लिये क्या व्यवस्था की है, खरीफ की फसल के लिये।

श्री अध्यक्ष--

जिलेवार सूचना की क्या आवश्यकता है?

श्री दुर्गा प्रसाद--

क्योंकि जिलेवार आपने मंगाया है इसलिये मैं पूछ रहा हूं।

श्री जयराम वर्मा--

उसके हिसाब से वहां पर जरूरत होगी १६१० क्विंटल की और हमारे यहां से इन्तजाम जौनपुर के लिये २,३६४ क्विंटल कुछ फाजिल हो चुका है। कहीं जरूरत होगी तो हम अधिक बीज को ट्रांस्फर कर देंगे।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

गत वर्ष जिस बीज की व्यवस्था की गई थी उसमें कितना बीज किसानों तक पहुंचा। जो नहीं पहुंचा वह कहां गया। जिन कारणों से नहीं पहुंचा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई। वितरण व्यवस्था के दोष को सम्हालने के लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री जयराम वर्मा—

पिछले साल के बारे में तो मैं समझता हूं कि बीज पहुंच गया होगा क्योंकि अब तक शिकायत नहीं है कि बीज नहीं पहुंचा है। इस साल के बारे में मैं कह सकता हूं कि बीज पहुंचेगा। अगर नहीं पहुंचेगा तो जो आदमी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री गेंदा सिंह--

श्रीमन् मैं माननीय कृषि मंत्री की शुभकामना का अनुगृहीत हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस विषम परिस्थिति में सही अनुमान जिलों से लग सकेगा और उस बीज की सप्लाई करने की व्यवस्था की जा सकेगी। तकाबी की रकम इतनी कम है कि पांच एकड़ से कम वाले तक वह सीमित है। क्या कोई ऐसी बात बता सकेंगे जिससे उनको भी और सदन को इतमीनान हो जाय कि इस खरीफ में बीज बोये बिना न रह जाय।

श्री जयराम वर्मा--

मैं कुछ कहना नहीं चाहता था लेकिन यह इन्तजाम तो खरीफ की फसल खत्म होने के बाद पूरी मुस्तैदी से शुरू होना चाहिये था। जब गवर्नमेंट आई तो उसी वक्त देखा गया। उसी वक्त आदेश जारी किये गये इस संबंध में कि कोई कोताही नहीं होनी चाहिये। अगर उसी समय से व्यवस्था की गई होती तो आसानी होती।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, मैंने पहिले स्पष्ट पूछा था कि सरकार आजमगढ़ जिले में खरीफ की बुवाई के लिये अर्लो और लेट पैडी के लिये कितने बीज दे रही है। मुझे उत्तर मिला था कि ५५० क्वींटल जल्दी पकने वाली, २३० क्विंटल देर से पकने वाली की मात्रा है। मान्यवर, हमारे आजमगढ़ जिले की तहसीलों में से चार तहसीलों में धान की फसल होती है। मैंने पूछा था तो बताया गया था कि सूबे की जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी उसको जनहित में बताना ठीक नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार का यह उत्तर कि ५०० क्विंटल बीज दिया गया था, वहां के जिलाधीश ने क्या मांग की है अथवा सरकार कितना देने की सोच रही है।

श्री जयराम वर्मा--

वे आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। मैं नहीं कह सकता कि वे सही हैं या नहीं।

श्री शंकर शर्मा (जिला लखनऊ)--

क्या कृषि मंत्री जी को मालूम है कि जिस बीज से कांग्रेस पैदा होती थी उसकी बहुत कमी हो गई है और उन्होंने उसके लिये इन्तजाम किया है या नहीं ?

(हंसी, कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री गेंदा सिंह--

पिछली गवर्नमेंट ने गलती करदी और उसने बीज नहीं रखा । क्या उसका दंड किसानों को देंगे कि बीज न दें? बीज बोने का काम जून-जुलाई में होता है और यह सरकार पहली अप्रैल से आई । क्या आपने सोचा कि कितने बीज की जरूरत होगी ? यदि हां, तो क्या उस तफसील को सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री जयराम वर्मा--

मुझे दुख है कि उन्होंने मेरी बातों को सुनने की कोशिश नहीं की । मैंने यह नहीं कहा कि पिछली गवर्नमेंट ने गलती कर दी । उस समय बीज मिलना आसान था, अब कठिन है । हमने तो अप्रैल से शुरू किया कि कितनी जरूरत है और हर जगह आदेश दिये कि अगर जरूरत हो तो पास के जिले से भी लिया जाये । बाजार से बीज खरीदने में कठिनाई भी होती है, कहीं धान की जगह जड़हन मिल जायगा । हमें संतोष है कि कोई खेत बीज के बगैर नहीं रहेगा । काश्तकार हमारे ही ऊपर निर्भर नहीं करता है । हम उसी बीज का इन्तजाम करते हैं जो उसके पास नहीं है, जैसे अधिक उपज के बीज । गरीब जो बीज नहीं रख सकते हैं वे हमसे चाहते हैं और हम उनके लिये इन्तजाम करते हैं ।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६७

श्री अध्यक्ष--

अब आइटम १० है । यह ५ बजे होने को था, सदन ने कल स्वीकृत किया था । ३-४ मिनट रह गये हैं । मैं उसे अब सदन की अनुमति से लेना चाहूंगा ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरमेश्वर पांडेय)--

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६७ पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, टाउन एरिया, रेवती, जिला बलिया, का चुनाव नवम्बर, १९६४ में हुआ था लेकिन उस समय वार्ड नम्बर १ और ४ के चुनाव को उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया था और आज भी उस पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है । उसकी तिथि ३०-६-६७ है । इसलिये इस विधेयक को लाने की आवश्यकता पड़ी ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६७ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

†२० जून, १९६७ की कार्यवाही में छपा है ।

खण्ड २, १, शीर्षक तथा प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६७

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६३

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिका व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के अट्ठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, १९६७ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६३ की धारा ३ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ की धारा ३ में अंक तथा शब्द "३० जून, १९६७" के स्थान पर अंक तथा शब्द "३० जून, १९६८" रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वरमेश्वर पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन) विधेयक, १९६७ पारित किया जाय।

***श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—**

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मंत्री जी न जो विधेयक हमारे सामने रखा है उसको रख कर हमारे साथ बड़ी ज्यादती की गयी है। जब कि यह सदन ५ बजे उठने जा रहा है यकायक यह विधेयक रख दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

यकायक तो नहीं रखा गया। कल सदन ने इसको स्वीकृत दी थी। अब तक तो आपने इस पर कोई ऐतराज नहीं किया। क्लाज बाई क्लाज भी पास हो गया फिर भी आपने शिकायत नहीं की, और अब आप शिकायत कर रहे हैं।

***श्री कृष्णानन्द राय—**

श्रीमन्, जब मैं विधेयक का विरोध करने उठा हूं और अगर आप उसके लिये थोड़ा सा समय भी न दीजियेगा तो बड़ी कठिनाई हो जायगी। मैं निवेदन कर रहा था कि सदन के उठने के आखिरी समय में यकायक यह विधेयक हमारे सामने रखा गया है जब कि दिन भर के काम से हमारा मस्तिष्क थक गया है। विधेयक में क्या क्या प्रश्न निहित हैं, यह समझ सकना भी कठिन है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि हाईकोर्ट के चुनाव के प्रश्न को लेकर कोई स्थगन आदेश दे दिया है और उसकी अवधि ३० जून को समाप्त होने जा रही है। इसलिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

यह आवश्यक है कि यह विधेयक आज पास कर दिया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने अपनी सरकार ३ अप्रैल को बनायी और सरकार बना कर वे सो गये जैसे इस उत्तर प्रदेश में कोई विधान सभा है ही नहीं। उन्होंने इस बात की आवश्यकता ही नहीं समझी कि विधान सभा को बुलाया जाय और उसके सामने ऐसे जरूरी कार्यक्रमों को रखा जाय जिससे उन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा सके और उनकी छानबीन की जा सके। लेकिन उन्होंने इसका अवसर नहीं दिया।

आजकल तो बड़ी कठिनाई है, इस समय बजट चल रहा है, समय कम है, ३० जुलाई से पहले बजट पास करना है और ३० जून तक हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार एक टाउन एरिया का चुनाव भी सम्पन्न नहीं हो पा रहा है वह सारी चीजों को एक साथ सम्मिलित करके यह चाहते हैं कि विधान सभा को जो स्वस्थ कार्य प्रणाली है जो उसके स्वस्थ चिन्तन का एक तरीका है उस सबको समाप्त कर दिया जाय और समय की आवश्यकता को हमारे सिर पर लादकर हर चीज को स्वीकार करा लिया जाय। इस को छोड़कर और कोई चीज इस बिल में नहीं है इसलिये मैं इस का अवश्य ही विरोध करना चाहता हूं और जिस ढंग से विधानसभा के साथ यह व्यवहार किया जा रहा है वह स्वस्थ परम्परा नहीं है।

श्री वरमेश्वर पांडेय—

श्रीमन्, अभी माननीय सदस्य, श्री कृष्णानन्द जी राय ने जो इस विधेयक का विरोध करने के लिये तर्क उपस्थिति किये हैं मैं समझता हूं कि उन में कोई तथ्य नहीं है। आज से नहीं वरन् सन् ६४ से ३० जून, सन् ६७ तक माननीय मुख्य मंत्री की सरकार ने और हम ने इस बिल को नहीं बढाया है, यह उच्च न्यायालय के आदेश से चुनाव रुका है और जब तक वहां से अंतिम निर्णय न हो जायगा सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। मैं समझता था कि माननीय कृष्णानन्द जी अपने पिछले समय के इतिहास को याद करके इस विधेयक का कोई तर्कपूर्ण विरोध उपस्थित करेंगे जिसका कि यह माननीय सदन स्वागत करेगा। अब इस विषय में अधिक कहने की आश्वयकता नहीं है। यह बिल इतना बड़ा नहीं है और न इस में अधिक तर्क लगाने की आवश्यकता ही है केवल २ मिनट की बात है और जितने सेंस रखने वाले विधान सभा के माननीय सदस्य हैं वे इस बिल को तुरन्त समझ सकते हैं और इसे स्वीकार कर सकते हैं। इसलिये उनका विरोध तर्कपूर्ण न होने के कारण मान्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६७ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और सोमवार, २६ जून, १९६७ को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ६ मिनट पर सोमवार, २६ जून, १९६७ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२१ जून, १९६७।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ४१ एल० ए०—१९६७-८४६।